नई दिल्ली
रविवार 13 सितंबर 2026
भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष
द्वितीया वर्ष : 30, अंक : 146
पृष्ठ : 12 मूल्य : 2.00

मौसम
अधि. 34
न्यून. 27

हरिभूमि
दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश से एक साथ प्रकाशित
समाचार ही नहीं, विचार भी
haribhoomi.com

11 जूनियर एशिया कप हॉकी : फाइनल में टीम इंडिया, सुप्रिया ने लगाई हैट्रिक

यह जानकारी ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन के समापन पर हुई विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता से मिली है

पहलगाम हमले के साथ आतंकवाद और उसके सभी रूपों की ब्रिक्स ने की कड़ी निंदा

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले महत्वपूर्ण सत्र के दौरान विदेशी राष्ट्राध्यक्षों ने एकजुटता के साथ आतंकवाद (पहलगाम हमला शामिल) और उसके रूपों, प्रकारों की कड़ी निंदा की है। साथ ही यह भी कहा कि आतंकवाद से जुड़ा कोई भी कृत्य आपराधिक श्रेणी का है। जिसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। आतंकवाद की निंदा से जुड़े मामले में पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को भी शामिल किया गया है। यह जानकारी शनिवार को सम्मेलन के पहले दिन के अंत में विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) सुधाकर दलेला ने दी है।

उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद को लेकर समूह देशों का हमारा यही विचार नई दिल्ली घोषणापत्र में भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। उधर, सैन्य मामलों के जानकारों की राय में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद को कतई स्वीकार न करने को लेकर भारत की जमीन से उसे साफ संदेश दे दिया है। यहां बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को पिछले साल 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकियों ने अंजाम दिया था। जिसमें कुल 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी ▶▶ शेष पेज 5 पर

ब्रिक्स सम्मेलन में बाएं से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग

संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर रहे ध्यान

इस समस्या से निपटने को लेकर या आतंकी खतरों की रोकथाम के लिए जारी प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर (यूएन) मुख्य है। यूएन के उद्देश्यों, सिद्धांतों और प्रोटोकॉल का पालन भी इस मामले में किया जाना चाहिए। इसके अलावा मानवाधिकार, शरणार्थी और मानवीय कानून भी इस कवायद का हिस्सा हैं। समूह ने आतंकवाद रोधी कार्य समूह और उसके 5 उप समूहों की गतिविधियों का स्वागत किया है। साथ ही इस संबंध में व्यापक अभिसमय को जल्द अंतिम रूप देने और उसे अपनाने का आह्वान किया है। घोषणापत्र में खासतौर पर युवा पीढ़ी के बीच उग्रवाद, कट्टरपंथ से निपटने के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। इस विषय पर समूह देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सम्मेलन में जोर दिया गया।

शून्य सहिष्णुता का किया आह्वान

वहीं, नई दिल्ली घोषणापत्र के मुताबिक, ब्रिक्स समूह देशों ने इस बात को स्वीकार किया कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह के साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा इस प्रकार की तमाम गतिविधियों में शामिल लोगों, उनके समर्थकों को हर हाल में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की इसमें अहम भूमिका होनी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद को लेकर शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस को सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। साथ ही कहा कि आतंकवाद से मुकाबले को लेकर वह दोहरे मानदंडों को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं।

जारी रहेगा वैश्विक चुनौती के खिलाफ संघर्ष

दलेला ने यह भी कहा कि ब्रिक्स देशों के प्रमुखों ने यह भी माना आतंकवाद की प्रेरणा चाहे कुछ भी रही हो या वह कहीं से भी कभी भी और किसी के द्वारा किया गया हो। उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। सभी देश इस वैश्विक चुनौती, उसके तमाम रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ संघर्ष करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। जिसमें सीमा पर आतंकवादियों की आवाजाही, वित्तपोषण और उन्हें मिली हुई सुरक्षित पनाहगाह का मुद्दा भी शामिल है।

हरिभूमि से बातचीत में नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन के आयोजन का देश-दुनिया के लिए महत्व और लाभ समझाते हुए बोले विशेषज्ञ

भारत से पश्चिम को गया स्पष्ट संदेश, किसी के विरोध में नहीं, शांति के पक्ष में खड़ा 'ब्रिक्स'

कविता जोशी ▶▶ नई दिल्ली

विशेष खबर

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किए जा रहे 18 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की धरती से पश्चिम के देशों के अलावा पूरी दुनिया को साफ शब्दों में यह संदेश चला गया है कि 11 देशों का यह अंतरराष्ट्रीय समूह किसी का विरोधी नहीं है। बल्कि इसका मकसद तथा सोच सिर्फ और सिर्फ शांति पर ही केंद्रित है। इस बाबत हालांकि शुरुआत में कुछ मुश्किलें जरूर आईं। लेकिन नई दिल्ली घोषणापत्र ने सभी को धता बता दिया। घरेलू स्तर पर आयोजन की अहमियत यह रही कि इसके माध्यम से भारत यह बताने में पूरी तरह से कामयाब रहा कि उसके माध्यम से विश्व के सामने संघर्षों के बीच शांति की बात आम-सहमति से मजबूती से रखी जा सकती है। जबकि दुनिया के मामले में शांति-सौहार्द से इतर ब्रिक्स एक भरोसेमंद वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अपनी धमक को बरकरार रख पाया। यह जानकारी विदेश मामलों के विशेषज्ञों ने हरिभूमि से बातचीत में दी है।

पीएम की संवाद डिप्लोमसी की हुई जीत: पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत ने कहा कि यह जो नई दिल्ली घोषणापत्र जारी हुआ है। उसका श्रेय कहीं न कहीं बीते कुछ महीनों से चल रही हमारी बैक चैनल बातचीत और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन से इतर ईरान, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और चीन जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ लगातार की गई उच्च-स्तरीय बैठकों को जाता है। मैं, इसे दुनिया के अलग-अलग भागों में संघर्षों के मध्य शांति के लिए की गई हमारी मध्यस्थता की कोशिश नहीं कहूंगा। बल्कि एक ईमानदार वार्ताकार की महत्वपूर्ण पहल कहना पसंद करूंगा। उन्होंने कहा कि जब कोई समूह बनता है, तो उसके बीच मतभेदों का उभरना ▶▶ शेष पेज 5 पर

ट्रंप ने बढ़ाया ब्रिक्स का हौसला

त्रिगुणायत ने कहा, ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे। जिन्होंने आज दुनिया के सामने मुख्य रूप से व्यापार के मामले में ब्रिक्स को एक सशक्त वैकल्पिक ढांचे के रूप में खड़ा कर दिया है। उन्होंने बीते समय में कई ऐसे एकतरफा निर्णय लिए। जिसने तमाम अंतरराष्ट्रीय नियम-कायदों को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, भारत-चीन व अन्य देशों के लिए टैरिफ बढ़ाया तो कहीं युद्ध करा दिया। इस चिंताजनक भू-राजनीतिक परिदृश्य में आज ग्लोबल साउथ के अलावा बाकी विकासशील देश भी एक लचीला और भरोसेमंद इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में ब्रिक्स की तरफ देख रहे हैं। भारत, रूस ने डॉलर की जगह पर समान मुद्रा में कारोबार शुरू किया है। बात तब आगे बढ़ेगी जब चीन व अन्य देश भी इसमें शामिल होंगे। मैं ये भी कहूंगा कि शांति की बात को लागू करवाना ब्रिक्स के हाथ में नहीं है। क्योंकि न तो इसके लिए अमेरिका तैयार होगा, न इजरायल, न ईरान और न ही रूस।

आपसी तालमेल-समन्वय ही कोर इश्यू

विदेश मामलों के पत्रकार रंजीत कुमार ने कहा कि इस सम्मेलन का भारत के लिए यही महत्व है कि उसके आमंत्रण पर रूस, चीन जैसी दो बड़ी महाशक्तियां एक मंच पर एकजुट हो गई हैं। जिससे अमेरिका व पश्चिम के बाकी हलकों में खासी चिंता है। इस सम्मेलन से यह संकेत मिलता है कि भविष्य में समूह देश आपस में वित्तीय लेनदेन को डॉलर के बाहर और अधिक सुचारू बनाकर व्यापार को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने पहले ही यह साफ कर दिया है कि हम किसी भी तरह से पश्चिम के खिलाफ नहीं हैं। बल्कि हमारे प्रयास अपनी सुविधा और संवर्धन के लिए के तालमेल और समन्वय के साथ एक प्रणाली के तहत इस आयोजन के लिए एकत्रित हुए हैं।

वंतारा, माधुरी के साथ जीवन भर खड़ी रहेगी, चाहे उसका घर कहीं भी हो

कोल्हापुर। कोल्हापुर में महादेवी के नाम से जाने वाली और प्रिय माधुरी (हाथी) को 30 जुलाई

2025 को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्देशों के अनुपालन में जामनगर स्थित वंतारा लाया गया था। इन निर्देशों को माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय और

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। वंतारा ने उसकी कस्टडी की मांग नहीं की थी। उसे वहां लाया गया और उसकी देखभाल की गई, क्योंकि

ऐसा करने का निर्देश दिया गया था। हम कोल्हापुर में माधुरी को लेकर लोगों की गहरी भावनाओं को पूरी तरह समझते हैं। महाराष्ट्र सरकार, उसके अधिकारियों, हितधारकों और समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा के बाद, वंतारा ने 06 अगस्त 2025 को कहा था कि वह उन भावनाओं का सम्मान करता है और सक्षम प्राधिकारियों के निर्देशों का पालन करेगा। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षों को अपने दावे उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखने का निर्देश दिया। पक्षों की सुनवाई करने, रिपोर्ट मंगाने और नंदानी स्थित सुविधा का निरीक्षण करने के बाद, उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 09 सितंबर 2026 को एक कारणयुक्त आदेश पारित किया, जिसमें सख्त शर्तों के अधीन माधुरी को कोल्हापुर लौटने की अनुमति दी गई। इन शर्तों में शामिल है कि उसका उपयोग जुलूसों या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, उसे चौबीसों घंटे देखभाल प्रदान की जाएगी और हर पखवाड़े उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा। वंतारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अधिकार का सम्मान करता है और उसके निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करेगा। माधुरी के संबंध में हमारा रुख हमेशा पशु चिकित्सा विज्ञान और उसके कल्याण से निर्देशित रहा है। निरंतर पशु चिकित्सा देखभाल के माध्यम से उसकी स्थिति को स्थिर किया गया है, लेकिन उसकी पुरानी बीमारियां समाप्त नहीं हुई हैं। उसे अभी भी उचित देखभाल, सहायक उपचार एवं प्रबंधन तथा नियमित पशु चिकित्सा निगरानी की आवश्यकता है। माधुरी के कोल्हापुर लौटने के साथ हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। वंतारा ने उसकी वापसी की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करने में मदद की है कि उचित रहने की

परिस्थितियां, पशु चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचा, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों। उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्देशानुसार, वंतारा के पशु चिकित्सक हर पखवाड़े कोल्हापुर में माधुरी का चिकित्सकीय परीक्षण करने और अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारियों को सौंपने जाएंगे। यह देखभाल की निरंतरता बनाए रखने और उसके कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में है, चाहे उसे कहीं भी रखा जाए। वंतारा ने नंदानी स्थित उस बाड़े और सुविधा पर भी काम किया है, जहां माधुरी अब लौट रही है। उपलब्ध बुनियादी ढांचे के भीतर उसके लिए सर्वोत्तम संभव व्यवस्थाएं की गई हैं। इस चरण में बुनियादी ढांचे में और सुधार नहीं किया जा सका, क्योंकि नगर नियोजन संबंधी बाधाओं के

कारण ट्रस्ट की भूमि से होकर गुजरने वाली सड़क ने विकास के लिए उपलब्ध भूमि को सीमित कर दिया है। माधुरी के वहां व्यवस्थित हो जाने के बाद, वंतारा सुविधा के उन्नयन के लिए मठ को सहयोग देने हेतु उपलब्ध रहेगा। यदि न्यायालयों या सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है,

तो वंतारा इस उन्नयन में भी समान रूप से सहायता करेगा। वंतारा का मानना है कि वास्तविक पशु कल्याण के लिए तथ्यों, पशु चिकित्सा विज्ञान, जिम्मेदार देखभाल, उचित कानूनी प्रक्रिया के

सम्मान और जीवन की हमेशा रक्षा करने की अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। वंतारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय

और HPC के निर्देशों के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। हम महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों तथा उनके अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। हम मठ और कोल्हापुर के लोगों के भी समान रूप से आभारी हैं, जिन्होंने माधुरी के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। हम माधुरी की स्थिति को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष लाने में पेटा इंडिया की भूमिका को भी स्वीकार करते हैं और पशु कल्याण के उद्देश्य से उनके साथ अपने लंबे संबंध को महत्व देते हैं। माधुरी का कल्याण वंतारा की पहली प्राथमिकता बना हुआ है। उसके स्वास्थ्य, कल्याण और गरिमा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह कहां रहती है। हम उसके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे, सुरक्षित एवं सुखमय जीवन की कामना करते हैं। *-वंतारा*

निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई

कर चोरी और राजस्व के नुकसान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी दिल्ली सरकार: रेखा गुप्ता

■ करीब 5 करोड़ रुपये का माल पकड़ा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली सरकार कर चोरी और राजस्व के नुकसान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई के दौरान करीब 5 करोड़ रुपये का माल पकड़ने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने रेलवे अधिकारियों के समन्वय से बड़ी कार्रवाई करते हुए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य के कॉपर स्क्रैप समेत लगभग 50 टन माल की खेप जब्त की है। विभाग को खुफिया जानकारी मिली थी कि रेलवे नेटवर्क के जरिए अनिवार्य दस्तावेजों, जैसे इनवॉइस और ई-वे बिल के बिना माल का परिवहन किया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर विभाग ने रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, सरकार का लक्ष्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी प्रभावी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें कारोबार पारदर्शी तरीके से हो और प्रत्येक देय कर की वसूली सुनिश्चित हो। यह खेप आंध्र प्रदेश के रेणिगुंटा से रवाना हुई ट्रेन के जरिए लाई गई थी और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंची थी। जांच के दौरान अधिकारियों ने करीब 25 टन कॉपर स्क्रैप जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये है। इसके अलावा करीब 25 टन मिश्रित स्क्रैप, कपड़े और अन्य सामान भी मिला, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है। इस प्रकार पकड़े गए माल का कुल अनुमानित मूल्य करीब 5 करोड़ रुपये है।

बिना जरूरी दस्तावेजों के हो रहा था माल का परिवहन

पकड़े गए माल के साथ आवश्यक इनवॉइस और ई-वे बिल उपलब्ध नहीं थे। विभाग द्वारा अब माल और उससे संबंधित दस्तावेजों का विस्तृत सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही, जीएसटी कानून के तहत माल के परिवहन से संबंधित वैधानिक अनुपालन की भी जांच की जा रही है। विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई सड़क मार्ग के अलावा रेलवे नेटवर्क के जरिए होने वाले माल के परिवहन पर निगरानी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय और रेलवे मार्गों की निगरानी बढ़ाकर बिना हिसाब-किताब के माल, अनियमित दस्तावेजों और संभावित कर चोरी के मामलों का पता लगाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार कर चोरी और राजस्व के नुकसान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार का लक्ष्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी प्रभावी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें कारोबार पारदर्शी तरीके से हो और प्रत्येक देय कर की वसूली सुनिश्चित हो। रेलवे सहित माल परिवहन के सभी माध्यमों पर निगरानी बढ़ाकर जीएसटी अनुपालन को मजबूत किया जाएगा। सुशासन, पारदर्शिता और सरकारी राजस्व की सुरक्षा दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में हैं और कर चोरी में शामिल तत्वों के खिलाफ कानून के अनुरूप सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

भाजपा में दलित मंडल अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं तो आम दलित कितना सुरक्षित: आप

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा है कि जब भाजपा में उनका अपना दलित मंडल अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं तो आम दलित लोग कितना सुरक्षित होंगे इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। आप एमएलए का कहा है कि भाजपा के एक विधायक ने अपने ही मंडल के दलित अध्यक्ष को घर पर बंधक बनाकर पीटा और जाति सूचक गालियां दी। लेकिन इस गंभीर मसले पर भाजपा की चुप्पी से साफ हो गया कि दिल्ली में दलित होना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है।

कुलदीप ने कहा कि दिल्ली पुलिस को चाहिए कि इस मामले में एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करे और भाजपा अपने विधायक को तुरंत निलंबित करे। उन्होंने दलित समाज से भी आह्वान किया कि अगर अब भी आप इस घटना के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो कल किसी और दलित का नंबर आना तय है।

सिंघु बॉर्डर पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने घोषित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के निर्देश पर यहां सिंघु बॉर्डर पर कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लिखने और खालिस्तान समर्थक भित्तिचित्र बनाने के मामले में पंजाब से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। सिंघु बॉर्डर पर दीवारों पर ये नारे और भित्तिचित्र छह सितंबर को मिले थे जिसके बाद दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (एसएफजे) के प्रमुख पन्नू ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा कर घटना की जिम्मेदारी भी ली थी। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों की पहचान प्रीतपाल, हरमिंदर सिंह और शीशपाल के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि जांचकर्ताओं ने सिंघु बॉर्डर की सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर उनकी गतिविधियों का पता लगाया जिसके बाद उन्हें पंजाब के फरीदकोट से गिरफ्तार किया गया। सूत्रों ने कहा कि आरोपियों ने जिस कार का कथित तौर पर इस्तेमाल किया था, उसे भी

बरामद कर लिया गया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रीतपाल कथित तौर पर पन्नू के सीधे संपर्क में था और पन्नू ने ही उसे सिंघु बॉर्डर के पास दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखने का निर्देश दिया था। सूत्रों ने कहा कि जांचकर्ता इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं कि प्रीतपाल कहीं पाकिस्तान में मौजूद आतंकी तत्वों के भी संपर्क में तो नहीं था। उन्होंने बताया कि प्रीतपाल के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत पहले से एक मामला दर्ज है। जांच के सिलसिले में विशेष प्रकोष्ठ और खुफिया ब्यूरो (आईबी) की टीम अलीपुर थाने में तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं।

डेढ़ लाख रुपये की ठगी मामले में तीन लोग किए अरेस्ट

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

गुजरात के एक व्यक्ति से कम कीमत पर वॉशिंग मशीन के पुर्जे बेचने के नाम पर की गई ठगी की राशि वसूलने और ठिकाने लगाने में इस्तेमाल तीन खातों के धारकों को पकड़ा गया है, जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र और एक बाइक टैक्सी चालक शामिल हैं। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गुजरात के पाटन निवासी एक व्यक्ति से कथित तौर पर 1.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। पीड़ित ने वॉशिंग मशीन के पुर्जों के लिए ऑनलाइन भुगतान किया था, लेकिन उसे वादे के मुताबिक सामान नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि धोखाधड़ी से प्राप्त राशि कई खातों के जरिये प्राप्त की गई और उस राशि का कुछ हिस्सा पूर्वी दिल्ली के एक एटीएम से निकाला गया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान दिल्ली के शकरपुर निवासी विकास सोनी (22), नैतिक (21) और त्रिलोकपुरी निवासी सागर (31) के तौर पर की। पीड़ित से ऑनलाइन शिकायत मिलने के बाद, पुलिस ने सात सितंबर को औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज की।

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि धोखाधड़ी से हासिल की गई रकम का एक हिस्सा नैतिक के एक बैंक खाते में जमा किया गया था। उसने बताया कि जांच में पैसे के अंतरण में विकास की कथित भूमिका की जानकारी मिली और दोनों को पकड़ लिया गया। बाद में, पुलिस ने सागर को भी पकड़ लिया। अधिकारियों ने बताया कि विकास बीए तृतीय वर्ष का छात्र है और कथित तौर पर उसने ठगी से प्राप्त राशि लेने के लिए अपने खाते के इस्तेमाल की अनुमति दी। उन्होंने बताया कि नैतिक दिल्ली विश्वविद्यालय के मुक्त शिक्षा विद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है और उसने ठगी के पैसे प्राप्त किए व निकाले। पुलिस के मुताबिक, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और बाइक टैक्सी चालक सागर ने कथित तौर पर कमीशन पर अपने खाते का इस्तेमाल करने की अनुमति ठगों को दी और नकदी निकाली। पुलिस ने विकास के पास से एक आईफोन 13 बरामद किया।

उन्होंने कहा कि इस उपकरण में कथित तौर पर लेन-देन से जुड़ी चैट और अन्य बातचीत मौजूद है तथा डिजिटल सबूत के लिए इसकी जांच की जा रही है।

फसलों में किसी प्रकार का छिड़काव ना करें किसान: पूसा

नई दिल्ली। वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि किसी प्रकार का छिड़काव ना करें तथा खड़ी फसलों (दलहनी फसलों, मक्का आदि) व सब्जी नर्सरियों में जल निकास का उचित प्रबंधन रखे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पूसा) के कृषि परामर्श सेवाओं, कृषि भौतिकी संभाग की नोड़ल अधिकारी डॉ. अनन्ता वशिष्ठ ने किसानों को यह सलाह जारी की है। वहीं, कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि धान की फसल इस समय मुख्यतः बाली बनने वाली स्थिति में है अतः फसल में कीटों की निगरानी करें। तना छेदक कीट की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच प्रति 3-4 प्रति एकड़ लगाए। यदि तना छेदक कीट का प्रकोप अधिक हो तो करटापदवाई 4 प्रतिशत दानें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ का बुरकाव करें। सलाहकार समिति के कृषि वैज्ञानिक डॉ. सुभाष नटराजा पिल्लै (अध्यक्ष, कृषि भौतिकी संभाग), डॉ. सचिन सुरेश सुरोशे (परियोजना समन्वयक, मधुमक्खी पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना) डॉ. दिनेश कुमार (प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग), डॉ. ए. के. सिंह (प्रधान वैज्ञानिक व इंचार्ज, केटेट) डॉ. गोगराज सिंह जाट (वरिष्ठ वैज्ञानिक, सब्जी विज्ञान संभाग), डॉ. बिष्णु माया (वरिष्ठ वैज्ञानिक, पादप रोग संभाग) ने कहा कि इस समय धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट होपरका आक्रमण आरंभ हो सकता है अतः किसान भाई खेत के अंदर जाकर पौध के निचली भाग के स्थान पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण करें। यदि प्रकोप अधिक दिखाई दें तो इमिडाक्लोप्रिड दवाई 1.0 मि. ली. प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त श्री **अश्वनी कुमार पुत्र श्री कंपानी शाह (सीटी/जीडी नंबर 107353102), निवासी पीओ परबत्ता, पीएस परबत्ता, जिला खगड़िया, बिहार–851216 (फोन नंबर 6204762380) कार्यालयः बाराचक 5, सीआईएसएफ बैरक, सेक्टर–5, रोहिणी रिठाला, दिल्ली–110085 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या एम/37/2024, धारा 138 एनआई एक्ट के तहत** थानाः आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त श्री **अश्वनी कुमार** नहीं मिल रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि श्री **अश्वनी कुमार** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। अतः इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या एम/37/2024, धारा 138 एनआई एक्ट के तहत** थानाः आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली **के उक्त अश्वनी कुमार,** से अपेक्षा किया जाता है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **29.10.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
स्नेहिल शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
(एनआई एक्ट)–01, कमरा नं.43
पटियाला हाउस कोर्ट,
नई दिल्ली

DP/12959/IGIA/2026

भारतीय मजदूर संघ ने सरकार को चेताया, मांगे नहीं मानी तो 21 को दिल्ली सहित देशभर में करेंगे प्रदर्शन

नई दिल्ली। भारतीय मजदूर संघ ने सरकार को चेताया है कि अगर संगठन द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी 21 सितंबर को दिल्ली सहित देशभर में राज्य परिवहन कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। इस बारे में महासंघ के संगठन मंत्री कैलाश मलिक ने बताया कि परिवहन संबंधित मामलों को लेकर हमने लंबे समय से इंतजार किया लेकिन किसी ने सुना नहीं। अब फैसला लिया गया है कि अगर सरकार नहीं चेती तो 21 सितम्बर 2026 को एक साथ देश के सभी प्रदेशों में राज्य परिवहन कर्मचारी सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेंगे। मलिक ने बताया कि मजदूर संघ मिल-बैठकर समझौते के पक्ष में है, लेकिन सरकार को लग रहा है कि मजदूर संघ सो रहा है। अब आन्दोलन का बिगुल बज गया है, यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। मलिक ने बताया कि हमारी प्रमुख मांग है कि सभी राज्य परिवहन निगमों में अनुबंध प्रथा समाप्त की जाए। जो अनुबंध पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें स्थाई किया जाए और आगे अनुबंध प्रथा बंद हो। जब तक स्थाई नहीं किया जाता तब तक अनुबंध कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों के समान वेतन व अन्य लाभ दिए जाएं।

महिला की हत्या के मामले में पति और उसकी प्रेमिका गिरफ्तार

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली के प्रहलादपुर में पिछले महीने हुई एक महिला की हत्या के मामले में उसके 22 वर्षीय पति और कथित प्रेमिका को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि जांच के दौरान पता चला कि महिला की हत्या पति और प्रेमिका के बीच संबंधों के कारण की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी मोहम्मद लाल बाबू उर्फ जाहिद अली और रुखसार खातून को दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मुंबई में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल समेत व्यापक जांच के बाद गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार, लाल बाबू ने कथित रूप से रुखसार के साथ मिलकर साजिश रची और प्रहलादपुर स्थित एक घर के बाथरूम में पत्नी सबीला खातून की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद 29 अगस्त को शाहबाद डेयरी थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसने कहा कि लाल बाबू और सबीला प्रहलादपुर में रह रहे थे। आरोप है कि लाल बाबू का रुखसार के साथ संबंध था और वह उससे शादी करना चाहता था। पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद लाल बाबू अपने नाबालिग बेटे के साथ दिल्ली से नोएडा की ओर भाग गया, जहां उसने अपने ममेरे भाई मोहम्मद ओसामा से संपर्क किया। पुलिस ने बताया कि ओसामा ने कथित रूप से लाल बाबू के ठहरने की व्यवस्था की और अन्य मदद दी तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए बिहार जाने में उसकी सहायता की। जांच के दौरान उसे पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हत्या के बाद पुलिस ने कई जगहों पर तलाशी ली और आरोपियों का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच तथा मौके पर जाकर सत्यापन किया। पुलिस ने बताया कि जांचकर्ताओं ने अपराध के बाद लाल बाबू द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल किए गए रास्तों और स्थानों का पता लगाया और आखिरकार उसे तथा रुखसार को खोज निकाला। अधिकारियों के अनुसार, जांच में सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल, तकनीकी जानकारी और कई राज्यों में जुटाई गई स्थानीय सूचनाओं का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने बताया कि बिहार के सीतामढ़ी का निवासी लाल बाबू मुख्य आरोपी है और वह मृतका का पति है।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी/84 बीएनएसएस देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **शाहिद पुत्रः फरीद अहमद पताः मकान नं. झुग्गी नं. 59, धरम कांटा के पास, 18 क्वार्टर विस्वास नगर, शाहदरा,–110032 दिल्ली** ने case **FIR No. 95/2018 U/s 324/326 IPC, थानाः विवेक विहार, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **शाहिद** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **शाहिद** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है।)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि case **FIR No. 95/2018 U/s 324/326 IPC, थानाः विवेक विहार, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **शाहिद** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद/मुकद्मा का उत्तर देने के लिए **दिनांक 16.10.2026** को या उससे पूर्व हाज़िर हो।

आदेशानुसार
श्री मोहित शर्मा
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी
रूम नं. 59, तीसरी मंजिल, शाहदरा जिला
कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली

DP/12805/SHD/2026 (Court Matter)

5 संपत्तियों पर सील, 29 को नोटिस

नगर निगम का तोड़फोड़ अभियान जारी, 33 अवैध निर्माण पर कार्रवाई

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का तोड़फोड़ अभियान शनिवार को भी जारी रहा। एमसीडी का दावा है कि दिल्ली के सभी 12 जोनों में भवन विभाग ने 33 अवैध निर्माण पर व्यापक कार्रवाई की है। सघन प्रवर्तन अभियान के दौरान 29 संपत्ति मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए है जबकि 5 संपत्तियों को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) और बिल्डिंग बाय-लॉ (भवन उपनियमों) के उल्लंघनों के खिलाफ खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण पर की गई है। एमसीडी के अनुसार अभियान के दौरान साउथ जोन में पॉश क्षेत्र कहे जाने वाले सतबड़ी और सैनिक फार्म्स में प्रवर्तन कार्रवाई की गई। वहीं नॉर्थ जोन के नेहरू विहार और गांधी विहार में विशेष रूप से खतरनाक इमारतों के खिलाफ प्रमुख डेमोलिशन

कार्रवाई की गई। नॉर्थ वेस्ट जोन के रोहिणी सेक्टर-3 में डेमोलिशन कार्रवाई की गई, जहां तीसरी मंजिल की छत पर कमरे के ऊपर बने अवैध निर्माण को हटाया गया। इसके अलावा विजय विहार तथा रोहिणी के सेक्टर 15 और 16 में भी कार्रवाई की गई। नॉर्थ ईस्ट जोन में भजनपुरा, सोम बाज़ार, साउथ गामड़ी, ईस्ट रोहतास नगर और शाहदरा में कार्रवाई की गई। साउथ वेस्ट जोन में द्वारका और काकरोला में डेमोलिशन की कार्रवाई की गई। वेस्ट जोन में तिहाड़ गांव, राजौरी गार्डन एक्सटेंशन और पश्चिम विहार में कार्रवाई की गई, जबकि सेंट्रल जोन के जोगाबाई एक्सटेंशन, जामिया नगर में प्रवर्तन कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एमसीडी ने बताया कि शनिवार तक गए सर्वेक्षण के तहत, लगभग 2251 भवनों की पहचान की गई है जहाँ पीजी सुविधाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें लगभग 47 हजार से अधिक लोग रह रहे हैं। एमसीडी ने दोहराया है कि खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माणों और एमपीडी व बिल्डिंग बाय लॉज के अन्य उल्लंघनों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी। निगम भवन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा के लिए नियमित निरीक्षण कर रहा है और आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

एमएलए झा ने लगाए पांचवीं मंजिल को सील करने में भेदभाव के आरोप

नई दिल्ली। बुराड़ी से आप पार्टी के विधायक संजीव झा ने आरोप लगाया कि मेरे क्षेत्र में खतरनाक बिल्डिंग गिराने और पांचवीं मंजिल को सील करने के मामले में भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ भाजपा सरकार आम लोगों के छोटे छोटे मकानों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिल्डरों द्वारा बनाए 5-6 मंजिला इमारतों पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। दिल्ली सरकार ने जब कोई नियम बनाया है तो कार्रवाई सब पर एक समान होनी चाहिए। बड़ी उम्मीदों के साथ भाजपा को लाने वाली दिल्ली की जनता आज उसी के आतंक से त्राहि त्राहि कर रही। उन्होंने कहा कि पांचवीं मंजिल की सीलिंग और डैमेज बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर जिस तरह अभियान चल रहा है, उसे लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। संजीव झा ने कहा कि पूरी दिल्ली में जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी सरकार ने पांचवीं मंजिल को सील करने और डैमेज बिल्डिंग को डेमोलिश करने का निर्णय लिया है, तब से किसी भी बड़े बिल्डर का मकान डेमोलिश नहीं हो रहा है। कोई आम आदमी अगर मकान बना रहा है तो उसको डेमोलिश कर दे रहे हैं, लेकिन जो बड़े बिल्डर 50 से 100 कमरे और पांच-छह फ्लोर बना रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह आदेश इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियां रुकें, बल्कि इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि वसूली में इनका हिस्सा और जनता का एक्सटॉर्शन बढ़ जाए।

भाजपा नेताओं के चल रहे है पीजी हाउस, एमएलए ने सत्य निकेतन में किया अवैध कब्जा: सौरभ

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा विधायक अनिल शर्मा सहित अन्य भाजपा नेता पर कहा कि अवैध तरीके से भारी संख्या में पीजी हाउस चलाए जा रहे है। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा विधायक अनिल शर्मा के पिता के नाम पर है पीजी की जमीन, जबकि उनका बेटा व उनके परिवार के अन्य सदस्य शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतना ही नहीं भाजपा के दूसरे नेता भी है जिनका बेटा भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है। अनिल शर्मा के पिता ने 600 वर्ग गज में बनी पीजी को चलाने के लिए अपने पोते की कंपनी को लीज पर दी है। भारद्वाज ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से दस्तावेज निकाल कर अनिल शर्मा के झूठ को बेनकाब कर दिया है। अनिल शर्मा के पिता ने 600 वर्ग गज में बनी पीजी को चलाने के लिए अपने पोते की केष्टो गैदर होम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लीज पर दी है। भाजपा विधायक की पोल पूरी तरह खुल गई है। क्या सांसद बांसुरी स्वराज इस पर कोई टिप्पणी करेंगी। भारद्वाज ने कहा कि सत्य निकेतन में जो पीजी चल रहे हैं, उन्हें भाजपा के बड़े-बड़े नेता चला रहे हैं।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **लोकेश यादव**, पुत्र स्वर्गीय अल्बेल सिंह निवासी F-237, गली नंबर 11, मोलरबंद एक्सटेंशन, बदरपुर, नई दिल्ली ने **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 148/2026 धारा 20/61/85 NDPS अधिनियम थाना बदरपुर, नई दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **लोकेश यादव** मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **लोकेश यादव** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसके खिलाफ माननीय अदालत द्वारा **धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** की कार्यवाही जारी हो चुकी है। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 148/2026 धारा 20/61/85 NDPS अधिनियम थाना बदरपुर, नई दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **लोकेश यादव** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए **04.11.2026** को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसारः श्री कुमार रजत,
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-04/विशेष न्यायाधीश (NDPS),
कोर्ट नंबर 312, दक्षिण-पूर्व ज़िला,
साकेत कोर्ट, नई दिल्ली।

DP/12529/SE/2026

लोक निर्माण विभाग दो वर्ष में पूरा करेगा निर्माण कार्य

'आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक जांच होगी तेज, शेख सराय में बनेगी फोरेंसिक लैब'

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली के शेख सराय में 151.81 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बनेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक जांच के लिए फोरेंसिक सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में शेख सराय में अत्याधुनिक क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल) के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना के लिए 151.81 करोड़ रुपये के

बजट को भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को परियोजना का निर्माण कार्य दो वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य दिया है। शेख सराय में बनने वाली नई क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला लगभग 6,300 वर्गमीटर के भूखंड पर बनाई जाएगी और इसका कुल निर्मित क्षेत्र 18,300 वर्गमीटर होगा। पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित यह भवन वैज्ञानिक जांच की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एकीकृत फोरेंसिक सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा।

'कानूनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी'

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से गृह विभाग और दिल्ली पुलिस को नए आपराधिक कानूनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कारण आपराधिक मामलों में फोरेंसिक जांच की मांग में काफी वृद्धि हुई है। नई आरएफएसएल इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में सहायता करेगी। इससे आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक जांच के लिए आवश्यक क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

'न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए है आवश्यक'

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई आरएफएसएल रोहिणी स्थित मौजूदा एफएसएल की वैज्ञानिक सहायता को मजबूत करेगी। फोरेंसिक विज्ञान आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक जांच के साथ-साथ आपराधिक मुकदमों और न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। नई प्रयोगशाला से राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक सहायता को भी मजबूती मिलेगी। इसका विशेष लाभ दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और मध्य दिल्ली के जिलों को मिलेगा।

'साक्ष्यों की जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट की प्रक्रिया होगी तेज'

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नई क्षेत्रीय एफएसएल के शुरू होने के बाद मामलों से जुड़े साक्ष्यों की जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम अधिक तेज और सुगम हो जाएगा। नई सुविधा से साक्ष्य आधारित जांच को मजबूती मिलेगी। साथ ही, इससे आपराधिक मामलों को न्यायालयों में समय पर निपटाने में सहायता मिलेगी। नई क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण से दिल्ली में वैज्ञानिक जांच के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और मध्य दिल्ली के जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ यह सुविधा रोहिणी स्थित एफएसएल को वैज्ञानिक सहायता मजबूत करने में भी सहायक होगी।

'दिल्ली भवन श्रमिक स्वास्थ्य योजना' को मंजूरी

निर्माण श्रमिकों को मिलेगा दो लाख तक का इलाज : संधू

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली में पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रित परिवारों के लिए बड़ी राहत की योजना को मंजूरी मिल गई है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 'दिल्ली भवन श्रमिक स्वास्थ्य योजना' को मंजूरी दे दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली मंत्रिमंडल इस योजना को मंजूरी दे चुके हैं। योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को इलाज के लिए आर्थिक परेशानी से बचाना है। इसके तहत प्रत्येक पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उसके पात्र जीवनसाथी को 'हर साल स्वास्थ्य जांच' की सुविधा मिलेगी। योजना के तहत श्रमिक और पात्र परिवार के सदस्य सूचीबद्ध अस्पतालों में 'बिना नकद भुगतान के बाह्य रोगी विभाग में डॉक्टर से परामर्श, जांच और दवाएं' ले सकेंगे। अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ने पर इलाज की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये सेवाएं 'केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की निर्धारित दरों' पर उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी को एक वर्ष में अधिकतम '2 लाख रुपये तक के उपचार' की सुविधा मिलेगी। वहीं एक परिवार के लिए यह सीमा '10 लाख रुपये सालाना' होगी। इससे गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में श्रमिक परिवारों पर इलाज का बड़ा आर्थिक बोझ कम हो सकेगा।

इन बीमारियों और जरूरतों को भी किया शामिल

योजना में केवल सामान्य इलाज ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया गया है। इनमें 'आपातकालीन उपचार, काम के दौरान होने वाली बीमारियां, पुरानी बीमारियां, विशेष उपचार, मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल और इलाज के बाद पुनर्वास'' जैसी सुविधाएं शामिल हैं। निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना या अचानक चिकित्सकीय आपात स्थिति होने पर लाभार्थी को नजदीकी ऐसे अस्पताल में भी इलाज कराने की अनुमति होगी, जो योजना में सूचीबद्ध नहीं है। ऐसे अस्पताल को इलाज की सीमित अवधि के लिए अस्थायी रूप से सूचीबद्ध माना जाएगा। इससे दुर्घटना के समय अस्पतालों की सूची तलाशने में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा।

सहरावत ने केशोपुर में किया डेंगू दिवस-जागरूकता अभियान का उद्घाटन

नई दिल्ली। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने शनिवार को केशोपुर में डेंगू दिवस-जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर मच्छर जनित बीमारियों से बचाव एवं रोकथाम के उपायों पर आधारित प्रदर्शनी का भी सांसद ने अवलोकन किया। सांसद ने वार्ड-103 में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 8 नई कूड़ा संग्रहण गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सांसद सहरावत ने डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की। कार्यक्रमों में सहरावत के अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य राजीव बब्बर, वार्ड समिति अध्यक्ष हरीश ओबरॉय, उपायुक्त, पश्चिमी क्षेत्र कर्नल विनोद अत्री, उप स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय कुमार आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि व निगम के अधिकारी-कर्मचारी आदि मौजूद थे। अपने संबोधन में सांसद सहरावत ने कहा कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय मच्छरों को पनपने से रोकना है।

ब्रिक्स सम्मेलन : एमआरएस मशीनों से रात-दिन हो रही है सड़कों की सफाई

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

विदेशी मेहमानों के सामने सड़कें गंदी न दिखे इसके लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद नई दिल्ली क्षेत्र की सड़कों को एमआरएस मशीनों से रात-दिन साफ कर रही है।

एनडीएमसी से मिली जानकारी के अनुसार एनडीएमसी एमआरएस मशीनों का इस्तेमाल करके नियमित रूप से सड़कों की सफाई कर रहा है और मुख्य सड़कों से जमा धूल, सड़क के किनारे का कचरा और मलबा हटा रहा है। एनडीएमसी का कहना है कि सफाई की ये मशीनें नई दिल्ली की

सड़कों को साफ, साफ-सुथरा और बेहतर बनाए रखने में मदद कर रही हैं, साथ ही धूल और कचरे के जमाव को भी कम कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में दो दिनों का ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेशी मेहमान दिल्ली में आए हुए हैं। चूंकि एनडीएमसी का क्षेत्र नई दिल्ली के कई मार्गों पर विदेशी मेहमानों का आवागमन होगा इसलिए एनडीएमसी ने सड़कों की सफाई में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। एनडीएमसी के कर्मचारी रात-दिन काम पर लगे हैं और अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे रह हैं। एनडीएमसी ने शनिवार का अपने स्वच्छता कर्मियों की मेहनत का सम्मान करते हुए एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर रखने के पीछे हैं हमारे समर्पित स्वच्छता कर्मी है। दिन की शुरुआत से लेकर देर रात तक, एनडीएमसी के स्वच्छता कर्मी पूरी निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ शहर की सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने में लगातार जुटे हैं।

डीटीसी के अस्थाई कर्मचारियों ने केंद्र से की बेसिक डीए ग्रेड पे बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के अस्थाई कर्मचारियों ने डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के बैनर तले शनिवार को केंद्र सरकार से बेसिक डीए ग्रेड पे को तुरंत बढ़ाने की मांग की है। यूनियन ने अपने एक्स हैंडल पर अपनी मांग को लिखते हुए कहा कि देश की राजधानी में ब्रिक्स सम्मेलन के आयोजन पर हमे गर्व है पर देश की राजधानी में डीटीसी के अस्थाई कर्मचारी कई कई सालों से संविदा नौकरी गुलामी की जिंदगी जी रहे है। हम चाहते हैं समान काम समान स्कले। यूनियन ने लिखा कि भारत देश एक तरफ अपने आप को अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत बताता है और दूसरी तरफ जो राजधानी को कर्मचारी चलाते हैं उनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है। दिल्ली में बढ़ती महंगाई में अस्थाई कर्मचारी अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं। अस्थाई कर्मचारी परिजनों की दवा पर खर्च, रूम रेंट, राशन पानी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। भारत सरकार से निवेदन है कि डीटीसी के अस्थाई कर्मचारियों का बेसिक डीए ग्रेड पे वेतन तुरंत बढ़ाया जाए। डीटीसी के अस्थाई कर्मचारियों की 20 से 25 सालों से यही एक मांग रही है कि डीटीसी के अस्थाई कर्मचारियों ड्राइवर और कंडक्टर की नौकरी पक्की स्थाई की जाए।

स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पर डॉक्टरों को देना होगा विशेष ध्यानः संधू

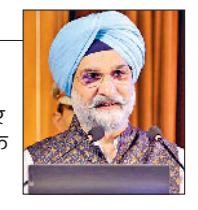

नई दिल्ली। 'उपचार, सशक्तीकरण और सम्मान' की भावना के अनुरूप महिलाओं के स्वास्थ्य को केवल जच्चा-बच्चा उपचार एवं देखभाल तक सीमित न रखकर व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना आवश्यक है। इसके लिए डॉक्टरों को बीमारियों की रोकथाम, समय पर पहचान, बेहतर उपचार, चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पर विशेष ध्यान देना होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू ने शनिवार को प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों के संगठन, एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स ऑफ दिल्ली के 48वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर यह बात साझा की। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूरचिकित्सा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक तकनीक का बेहतर उपयोग करके महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को उद्धृत करते हुए उपराज्यपाल संधू ने कहा कि 'नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है।' उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य में किया गया निवेश वास्तव में भारत की मानव पूंजी और देश के उज्ज्वल भविष्य में निवेश है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ महिला न केवल स्वस्थ परिवार की आधारशिला होती है, बल्कि एक सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

'संवाद की संस्कृति का देश है भारत'

नई दिल्ली। भारत संवाद की समृद्ध परंपरा और उसकी विशिष्ट सांस्कृतिक भावभूमि का देश है। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. बलदेव भाई ने शनिवार को मंडी हाउस स्थित त्रिवेणी कला संगम के सभागार में यह बात कही। सभागार में संस्कृति पर्व के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि भारत संवाद की संस्कृति का देश है और हमारी सांस्कृतिक परंपरा की निर्मिति के मूल में संवाद ही रहा है। बता दें कि साहित्य संस्कृति फाउंडेशन के आठवें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. संजय पासवान ने कहा कि संवाद और संविधान ही सभी तरह की समस्याओं के समाधान का एक मात्र साधन है। उन्होंने कहा कि एक ही समय में चिंतन की अलग-अलग दिशा और दृष्टि के कारण जिसे कुछ लोग संस्कृति समझते हैं उसी को दूसरे कुछ लोग विकृति मान बैठते हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि ऐसा प्रायः परम्पराओं के ज्ञान के अभाव में ही होता है इसलिए हमें भारत की विशिष्ट परम्पराओं का ज्ञान होना चाहिए तथा सभी सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। उद्घाटन सत्र का संचालन मिरांडा हाउस कॉलेज की प्रो. संगीता राय ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के डॉ. मनीष ने किया। संस्कृति पर्व के अवसर पर साहित्य संस्कृति फाउंडेशन की ओर से चर्चित कथाकार कवयित्री अलका सिन्हा को साहित्य सम्मान, सभ्यता अध्ययन केंद्र के संस्थापक रविशंकर को संस्कृति श्री सम्मान, ध्रुपद गायक सुमीत आनंद पाण्डेय को कला श्री सम्मान एवं न्यूरो सर्जन डॉ. मनीष कुमार को सेवा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया।

डूसू चुनाव : एबीवीपी का महिला सुरक्षा और छात्रावास विस्तार पर फोकस

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव के लिए अपने केंद्रीय पैनल के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद शनिवार को चुनाव अभियान तेज कर दिया है। अध्यक्ष पद पर यश डबास, उपाध्यक्ष पद पर ईशू मौर्य, सचिव पद पर रिया छाबड़ी एवं संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्यराज सिंह एबीवीपी के प्रत्याशी हैं।

चारों पदों पर जीत के लक्ष्य के साथ एबीवीपी कार्यकर्ता विभिन्न कॉलेजों, छात्रावासों एवं विद्यार्थी बहुल क्षेत्रों में लगातार संपर्क और संवाद कर रहे हैं। एबीवीपी पैनल से डूसू सचिव पद की प्रत्याशी रिया छाबड़ी ने कहा कि 'महिला सुरक्षा और हॉस्टल की सुविधा विद्यार्थियों की जरूरतें हैं। एबीवीपी ने इन मुद्दों को हमेशा जमीन पर उठाया है। हम चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिले और हर विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई के

दौरान उचित और सुरक्षित आवास मिल सके। दावा करते हुए उन्होंने कहा कि एबीवीपी की मांग पर 2400 बिस्तर के गर्ल्स हॉस्टल का काम शुरू हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय में हॉस्टल की जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। इसलिए आने वाले समय में हॉस्टल की सीटें बढ़ाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। विद्यार्थियों के बीच एबीवीपी के पैनल को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उससे हमें पूरा विश्वास है कि इस बार डूसू में एबीवीपी 4-0 से जीत दर्ज करेगी।'

पीजी एवं छात्रावासों में विद्यार्थियों से किया संपर्क

शनिवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न पीजी एवं छात्रावासों में विद्यार्थियों से संपर्क कर विद्यार्थी हित से जुड़े मुद्दों पर संवाद किया। सत्य निकेतन हादसे के बाद चल रहे 'आखिर कब तक?' अभियान के तहत सुरक्षित विद्यार्थी आवास का मुद्दा उठाया गया। एबीवीपी की मांग और लगातार प्रदर्शनों के बाद 2400 बिस्तर के गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में हॉस्टल की सीमित संख्या और सीटों की कमी को देखते हुए सभी विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की सीटें बढ़ाना और सुरक्षित एवं सुलभ आवास उपलब्ध कराना एबीवीपी का प्रमुख मुद्दा है।

आधार और राशन कार्ड में एक ही मोबाइल नंबर होना जरूरी

राशन वितरण व्यवस्था को डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही सरकार

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली सरकार उचित दर की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक डिजिटल एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में राशन कार्डधारकों के लिए सीबीडीसी (केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा) व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।

नई व्यवस्था के तहत राशन कार्डधारकों के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर का एक ही होना महत्वपूर्ण होगा। सरकार की ओर से राशन कार्डधारकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने दोनों दस्तावेजों में दर्ज मोबाइल नंबर की जांच कर लें। यदि आधार कार्ड और राशन कार्ड में अलग-अलग मोबाइल नंबर दर्ज हैं तो उन्हें एक समान करवा लें, ताकि डिजिटल राशन वितरण व्यवस्था लागू होने के बाद किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

दिल्ली में बड़ी संख्या में परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। ऐसे में मोबाइल नंबर से संबंधित छोटी-सी लापरवाही भविष्य में राशन लेने की प्रक्रिया में परेशानी पैदा कर सकती है। खासकर ऐसे परिवार, जिनके मोबाइल नंबर हाल ही में बदले हैं या जिनके आधार और राशन कार्ड में अलग-अलग नंबर दर्ज हैं, उन्हें प्राथमिकता से अपना रिकॉर्ड जांच लेना चाहिए। सरकार की अपील है कि राशन कार्डधारक आखिरी समय का इंतजार न करें और अपने दस्तावेजों में मोबाइल नंबर की स्थिति पहले ही जांच लें। इससे सीबीडीसी व्यवस्था लागू होने के बाद डिजिटल सत्यापन अथवा राशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा।

क्यों जरूरी है मोबाइल नंबर का एक जैसा होना?

सीबीडीसी आधारित व्यवस्था में राशन वितरण को डिजिटल माध्यम से अधिक व्यवस्थित और सत्यापन योग्य बनाने की तैयारी है। ऐसे में लाभार्थी की पहचान और संबंधित डिजिटल प्रक्रिया में मोबाइल नंबर की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए सरकार चाहती है कि राशन कार्ड और आधार से संबंधित मोबाइल विवरण में किसी तरह का अंतर न रहे। सरकार से मिली जानकारी के अनुसार राशन कार्डधारक दो में से किसी एक तरीके से अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करा सकते हैं। जिसमें पहला विकल्पः राशन कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर को आधार कार्ड में अपडेट करा लें। दूसरा विकल्पः आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर को राशन कार्ड में अपडेट करा लें। यानी दोनों दस्तावेजों में एक ही मोबाइल नंबर पंजीकृत होना चाहिए।

गरीबों की झुग्गी बस्तियों को पर्दे से छिपाना भाजपा सरकार की विफलताः यादव

नई दिल्ली। दिल्ली में आयोजित हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी मेहमानों वाले प्रमुख आवागमन वाले मार्गों पर झुग्गी झोपड़ियों को पर्दों से छिपाना भाजपा सरकार की विफलता है। यह बात शनिवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कही। यादव ने कहा कि केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद जब भी दिल्ली किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी करती है, तो गरीब आदमी सबसे ज्यादा पीड़ित होता हैं क्योंकि उनकी झुग्गी बस्तियों को पर्दे व अन्य संसाधनों से छिपाकर विदेशी मेहमानों को वास्तविकता से अलग दिल्ली का दोहरा स्वरुप दिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन क्या गरीबों का अपमान और असुविधाओं के अधीन जीवन जीते लोगों के प्रति अपवाद नहीं है। यादव ने कहा कि 12-13 सितंबर, 2026 को हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले, कई झुग्गी झोंपड़ी समूहों और कम आय वाले गरीब लोगों को प्रमुख आवागमन वाले मार्गों के साथ बड़े नीले और सफेद या हरे रंग के पर्दे और कपड़े के पर्दे के पीछे छिपा दिया गया था। जिनमें वसंत विहार में कुली कैंप बस्ती के आसपास सहित अन्य जगहों, जो केंद्र सरकार द्वारा उच्च स्तरीय राजनयिक कार्यक्रमों के दौरान शहरी असमानता और गरीबी के प्रति भेदभाव की नीति को दर्शाता है।

खबर संक्षेप

दुकान से सोना व 3 लाख चोरी करने वाला अरेस्ट

फरीदाबाद। थाना एनआईटी क्षेत्र में ज्वैलरी पर हॉलमार्क करने वाली दुकान से 209 ग्राम सोना व 3 लाख रुपए नकद चोरी करने के मामले में थाना कोतवाली की टीम ने दुकान पर काम करने वाले आरोपी संतोष निवासी जिला सांगली महाराष्ट्र को पुणे महाराष्ट्र से 9 सितम्बर को गिरफ्तार कर तीन दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता दादासो यमगर निवासी एनआईटी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मार्किट नंबर.1 में एचयूआईडी सेंटर चलाते हैं। आरोपी संतोष उनकी दुकान पर काम करता था तथा दुकान पर ही रहता था। दुकान व तिजोरी की चाबी भी उसके पास रहती थी। 4 सितंबर की रात दुकान बंद कर वह घर चले गए थे। संतोष का मोबाइल बंद मिला और दुकान के सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे। दुकान पर पहुंचने पर तिजोरी खुली मिली, जिसमें से 209 ग्राम सोना व 3 लाख रुपए नकद गायब थे।

एसके भारद्वाज भारी मतों से चुने गए प्रधान

फरीदाबाद। सेक्टर-12 स्थित जिला टैक्स बार एसोसिएशन फरीदाबाद के वर्ष 2026-27 के कार्यकारिणी चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। इसमें छह सीटों का चयन मतदान प्रक्रिया के द्वारा हुआ। कार्यकारिणी में एस. के भारद्वाज भारी मतों से प्रधान चुने गए, इसके अतिरिक्त चेतन भारद्वाज सीनियर वाइस प्रेजिडेंट, एडवोकेट राजेश गुप्ता वाइस प्रेजिडेंट, सतेंद्र यादव महासचिव, सत्यवान नरवाल कैशियर एवं विनीत त्यागी संयुक्त सचिव के लिए चुने गए। पंजाब हरियाणा बार काउंसिल चंडीगढ़ के निर्देशानुसार महिला मेंबर्स को कार्यकारिणी में शामिल किया गया, इसमें एडवोकेट मीनू कुमारी को वाइस प्रेसीडेंट फीमेल चुना गया। कार्यकारिणी सदस्यों में निखिल चौधरी, सोनिया सैनी एवं दिपांशु को निर्विरोध शामिल किया गया। सभी सदस्यों ने चुनाव अधिकारी नरेंद्र चौधरी का धन्यवाद किया। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाया। चुनाव अधिकारी नरेंद्र चौधरी के सहायक के रूप में एडवोकेट दीपक गेरा एवं एडवोकेट संदीप मक्कड का धन्यवाद किया।

बैठक में निगमायुक्त प्रदीप दहिया, अतिरिक्त निगमायुक्त यश जालुका समेत नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

गुरुग्राम में विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार, राव नरबीर ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध काम के निर्देश

धर्मेंद्र कौशिक ▶▶ गुरुग्राम

गुरुग्राम में सड़क, सीवर, ड्रेनेज और जलापूर्ति से जुड़े विकास कार्यों को अब गति देने की तैयारी है। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री राव नरबीर सिंह ने निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे हों और गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता न किया जाए। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर चल रहे, पूरे हो चुके और प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी ली।

बैठक में बताया गया कि नगर निगम के वार्ड-1 से 18 तक विभिन्न विकास कार्यों पर करीब 366.40 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इनमें सड़क, सीवर, जलापूर्ति और जल निकासी से जुड़े कार्य प्रमुख हैं।

अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए

मंत्री ने नगर निगम सीमा में चल रहे आरएमसी प्लांटों को बाहर करने की कार्रवाई करने और धनकोट मुख्य सड़क पर निर्माण से पहले अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है, ताकि सड़क बनने के बाद दोबारा खुदाई की स्थिति न आए।

जलभराव रोकने पर विशेष जोर

राव नरबीर सिंह ने सड़क निर्माण के दौरान रोड लेवल और आसपास की ड्रेनेज व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क और सीवर मैनहोल का स्तर सही रखा जाए, ताकि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या न हो और वाहन चालकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में वार्ड-9, 8, 16 और 4 में चल रहे स्टॉर्म वाटर ड्रेन के कार्यों की भी समीक्षा की गई। सेक्टर-9 और सेक्टर-9ए में करीब 12.57 करोड़ रुपए के जल निकासी कार्य चल रहे हैं। वार्ड-16 में उप्पल साउथएंड क्षेत्र को मास्टर ड्रेन से जोड़ने तथा वार्ड-9 में विभिन्न क्षेत्रों में ड्रेनेज व्यवस्था मजबूत करने के काम भी शामिल हैं।

सड़क और मॉडल रोड पर भी फोकस

वार्ड-15 में साउथ सिटी-2, निर्वाणा कंट्री और आसपास के क्षेत्रों में मॉडल रोड, फुटपाथ, ड्रेनेज और सडक़ पुनर्निर्माण के कार्यों की भी समीक्षा हुई। इसके अलावा धनकोट, पलड़ा और बेगमपुर खटौला में सीवर और जलापूर्ति से जुड़े कार्यों को भी गति देने के निर्देश दिए गए। बेगमपुर खटौला में 6.94 करोड़ रुपए की लागत से 2 एमएलडी एसटीपी का निर्माण हो रहा है, जिसका ट्रायल रन दिसंबर 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य है।

डिट्रिस्क्ट गर्वनर लायन संदीप कुमार ने लॉयस क्लब फरीदाबाद ओल्ड की इंस्ट्रालेशन सेरेमनी व 5 सदस्यों को दिलवाई शपथ

लायन सुरेश मदान बने प्रधान, लॉयस क्लब फरीदाबाद ओल्ड की इंस्ट्रालेशन सेरेमनी में सदस्यों ने ली शपथ

- जनसेवा के कार्य करने व जरूरतमंदों के लिए बड़े प्रकल्प पर विचार करने का निर्णय किया
- दोहराया जरूरतमंदों की सेवा का संकल्प, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया
- जनपद पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए

हरिभूमि न्यूज ▶▶ फरीदाबाद

लॉयस क्लब फरीदाबाद ओल्ड का स्थानीय जिमखाना क्लब सेक्टर-15ए में स्वर्ण जयंती शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें डिस्ट्रिक्ट-321ए-1 के पदाधिकारियों, विभिन्न लॉयस क्लबों के पदाधिकारियों, सदस्यों व अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का गौरवपूर्ण संचालन लायन आर.के. चिलाना ने विशेष कौशल से किया। पूर्व प्रधान लायन उमेश पांचाल ने मीटिंग प्रारंभ की। ईश वंदना व राष्ट्रीयगान डॉ. शिवम मदान द्वारा की गई।

दीपशिखा तथा कार्यक्रम का उद्घाटन मल्टीपल के सचिव व पूर्व गर्वनर लायन ओंकार सिंह रेणु ने किया। समारोह के चेयरमैन लायन देवेंद्र गोयल ने सभी का स्वागत अभिनंदन किया। को-चेयरमैन लायन एसपी सचदेवा व संयोजक लायन बीएस चौधरी ने अपना सहयोग दिया। पूर्व गर्वनर लायन एनके गुप्ता ने क्लब से जुड़े पांच नए सदस्यों को मोमबत्ती जलाकर दीक्षा समारोह सम्पन्न कराया। कार्यकम के मुख्यातिथि डिट्रिस्कट गर्वनर लायन संदीप कुमार ने क्लब के निदेशकों पीआरओ, कोषाध्यक्ष, सचिव, प्रधान सभी पदाधिकारियों को उनके पद की जिम्मेदारियां समझाते हुए कुशल अंदाज में शपथ ग्रहण कराया व सेवा कार्य करते रहने का संकल्प दिलाया। नवनिर्वाचित प्रधान लायन सुरेश मदान का पदाधिकारियों, सदस्यों व अतिथियों ने फूल मालाएं पहनाकर अभिनंदन किया। प्रधान लायन सुरेश मदान ने स्वर्ण जयंती वर्ष में बढ़-चढ़कर जनसेवा के कार्य करने व जरूरतमंदों के लिए बड़े प्रकल्प पर विचार करने का निर्णय किया तथा अपने लांयस भवन सेक्टर-19 को मंदिर बताते हुए पीआरओ लायन प्रदीप गर्ग की क्लब के स्वर्ण जयंती वर्ष पर भावपूर्ण कविता को सराहा गया। एक्लेसेडर ऑफ गुडविल पूर्व गर्वनर लायन तेजपाल सिंह खिल्लन ने क्लब के कार्यो को सराहा व जनसेवा के बड़े कार्य करने को प्रोत्साहित किया व सहायता का आश्वासन भी दिया। वाइस डिस्ट्रिक्ट गर्वनर डा. प्रतिभा अग्रवाल व राकेश कुमार जग्गी ने क्लब को शुभकामनाएं देते हुए उत्तम सेवा कार्य करते रहने को प्रोत्साहित किया। पूर्व गर्वनर लायन अनिल अरोड़ा ने सभी की ओर से क्लब को शुभाशीष व शुभकामनाएं दी।

क्लब के सदस्य लायन आर.एस. गांधी व लायन नरेश कुमार ने डिस्ट्रिक्ट लायन विद्यालय के छात्रों के लिए 50 हजार रुपए राशि की पुस्तकें दिलाने की घोषणा की। जनपद पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। पचास वर्ष पूर्व 14.6.77 को लायन ए.आर. वोहरा द्वारा इस क्लब की स्थापना की गई थी।

पदाधिकारियों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की

सभी ने उन्हें दिल से बधाईयां दी। क्लब में पांच स्थायी प्रकल्पों द्वारा प्रतिदिन सेवा कार्य किए जाने की सभी जनपद पदाधिकारियों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। सर्व लायन आई.एस. कटारिया, राजपाल गर्ग, मुकेश अरोड़ा, राधेश्याम अग्रवाल, विनीत गर्ग, सचिव जयदीप कत्याल, रचना कात्याल, संजीव महाजन, जे.एम. मल्होत्रा, अशोक अरोड़ा, मुकेश गर्ग, राजेश शर्मा, रवि शर्मा, दिनेश गर्ग, धर्मेन्द्र कौशिक, सुभाष आहूजा सभी ने अपनी दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। इस अवसर पर अन्य क्लबों के माननीय व विशिष्ठ लायन सदस्यों बीएम शर्मा, नरगिस गुप्ता, एसके मधोक, टीएस बेदी, योगेंद्र तेवतिया, महेश बांगा, संजीव ग्रोवर, जेपी गुप्ता, आरके ओझा, आरके गोयल, जीके गुप्ता, आरपी ओझा, जेपी गुप्ता, संजीव गर्ग, प्रो.चुघ, राजन भटिया, सतीश परनामी, अनिल मेहता, गिरीश गुप्ता, प्रवीण राघव, शैलेंद्र सिंघल राहुल सिंघल आदि ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई।

पहल का उद्देश्य गुणवत्ता वाला आउटडोर एडवरटाइजिंग ईको सिस्टम तैयार करना

नमो भारत कॉरिडोर पर साहिबाबाद से मोदीपुरम के बीच पियर और पोर्टल पर विज्ञापन के लिए निविदाएं बुलाई गईं

हरिभूमि न्यूज ▶▶ गाजियाबाद

एनसीआरटीसी जल्द ही दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर साहिबाबाद से मोदीपुरम के बीच पियर्स और पोर्टल स्ट्रक्चर पर विज्ञापन कराएगा। इसके लिए पियर्स और पोर्टल स्ट्रक्चर पर विज्ञापन अधिकारों की लाइसेंसिंग हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

एनसीआरटी सी के पुनीत वत्स ने बताया कि नमो भारत कॉरिडोर गाज़ियाबाद और मेरठ के घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और व्यस्त बाज़ार वाले क्षेत्रों से होकर गुज़रता है, विशेषकर इस निविदा के अंतर्गत प्रस्तावित 50 किलोमीटर से अधिक लंबे खंड पर। इसके साथ ही, कॉरिडोर उन प्रमुख हाईवे और मुख्य सड़कों के साथ-साथ भी गुजरता है जहाँ वाहनों की अत्यधिक आवाजाही बनी रहती है। वर्तमान में इस कॉरिडोर पर प्रतिदिन करीब 1.1 लाख यात्री यात्रा कर रहे हैं और इसने अब तक 4.5 करोड़ से अधिक कम्यूटर जर्नी का माइलस्टोन पार कर लिया है। यह नमो भारत पर लोगों के बढ़ते विश्वास के साथ ही यह दर्शाता है कि यह इस क्षेत्र में तेज़ी से एक पसंदीदा परिवहन साधन के रूप में उभर रहा है। बढ़ती यात्री संख्या, रिहायशी, व्यावसायिक एवं बाजार क्षेत्रों के बीच कॉरिडोर की मौजूदगी और इसके साथ मौजूद सड़कों पर वाहनों की अधिक आवाजाही, पियर्स और पोर्टल पर उपलब्ध विज्ञापन स्थानों को आउटडोर कैंपेन के लिए एक आकर्षक अवसर बनाते हैं। कॉरिडोर के पियर्स रणनीतिक रूप से सड़कों के मीडियन पर स्थित हैं। इससे इनपर दिए गए विज्ञापनों की बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सुनिश्चित होगी।

इस पहल का उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला आउटडोर एडवरटाइजिंग ईको-सिस्टम तैयार करना है, जो कॉरिडोर को देखने में आकर्षक बनाने के साथ-साथ गैर-किराया राजस्व में भी योगदान देगा। साहिबाबाद से मोदीपुरम के बीच के इस खंड में कई औद्योगिक क्षेत्र, पियर्स पर विज्ञापन के लिए स्थान विकसित होने से इस मार्ग पर मौजूद व्यवसायों, स्कूल-कॉलेजों, रियल एस्टेट समूहों, अस्पतालों, एफ एंड बी चेन आदि के लिए यह एक प्रमुख ब्रांडिंग अवसर के रूप में उभर सकता है।

न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी के दिशा-निर्देशों पर राज्य भर में लोक अदालतों का आयोजन

फरीदाबाद लोक अदालत में 1.31 लाख मामले रखे गए, 1.25 लाख से अधिक मामलों का आपसी सहमति से समाधान

हरिभूमि न्यूज ▶▶ फरीदाबाद

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं न्यायमूर्ति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, हरसिमरन सिंह सेठी के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा प्रांत में प्रत्येक जिले के अंदर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुधीर जीवन की अध्यक्षता एवं निर्देशानुसार तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह की देखरेख में आज जिला अदालत सेक्टर 12 फरीदाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस लोक अदालत में 19बेंच लगाए गए जिनमें सुधीर जीवन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कंवरपाल सिंह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अजय शर्मा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विनीत सपरा अतिरिक्त प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, रितु यादव अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सौरभ शर्मा जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमितेंद्र सिंह जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हिमानी जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिज्ञासा शर्मा जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोमल दहिया जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उपासना दहिया जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जयोत्सना रावत न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, रजत कुमार कनौजिया न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वर्तिका मिश्रा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आनिया खिजरा अशरफ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पंखुरी शुक्ला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सारिका न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम, पारस चौधरी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सरिता सोलंकी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की बेंच बनाई गई जिनमें 131940 केस रखे गए जिनमे 125165 केसों का निपटारा, आपसी सहमति से लोक अदालत द्वारा किया गया जिनमें मोटर वाइकल दुर्घटना 52, छोटे-मोटे अपराधिक मामले 2564, चेक बाउंस 408, बिजली से संबंधित 872, समरी चालान 112850, वैवाहिक संबंधित 199, दीवानी 562, बैंक रिकवरी 3608, रेवेन्यू 4030, एग्जीक्यूशन 20 का निपटारा आपसी सहमति से किया गया। सीजेएम जितेंद्र सिंह ने बताया कि आज की लोक अदालत में लोगों का ट्रैफिक केसों को लेकर लोगों का रुझान रहा यानी की इस लोक अदालत में अधिक से अधिक ट्रैफिक चालान से संबंधित केसों का निपटारा किया गया। इस अवसर पर न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि लोक अदालत में फैसला होने पर जिसकी सुप्रीम कोर्ट तक कोई अपील नहीं होती कोर्ट फीस वापस हो जाती है तथा केस का फैसला हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है जिससे पैसे व समय की बचत होती है।

छत्तीसगढ़ के खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह बोले- खनन की अनुमति नहीं दी

तारा कोल ब्लॉक पर भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार

हरिभूमि न्यूज ▶▶ गुरुग्राम

तारा कोल ब्लॉक को लेकर कांग्रेस नेताओं की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। यहां एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने कहा कि तारा कोल ब्लॉक के संबंध में कांग्रेस नेताओं द्वारा रखे जा रहे तथ्यों को पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जून 2021 में केंद्र सरकार से तारा कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम सीएमडीसी को आवंटित करने का आग्रह किया था। सौरभ सिंह ने कहा कि वर्तमान में तारा कोल ब्लॉक में खनन शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है। भारत सरकार की वाणिज्यिक कोयला नीलामी में सीजी सिन-गैस एंड केमिकल्स लिमिटेड सफल बोलीदाता रही है। खनन शुरू होने से पहले वन स्वीकृति सहित सभी आवश्यक वैधानिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाएं पूरी की जानी हैं। उन्होंने पेड़ों की कटाई को लेकर किए जा रहे दावों पर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 10 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने का दावा सही नहीं है। उनके अनुसार परियोजना में इससे काफी कम संख्या में पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है और यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी। सिंह ने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सरकार की प्राथमिकता है।

क्लीनिक में मरीजों की मेडिकल जांच, शीघ्र निदान और समय पर उपचार की सुविधाएं मुहैया कराई गई

मरीजों के लिए क्लीनिक में एक छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध

फोर्टिस एस्कॉर्ट्स फरीदाबाद ने शीघ्र निदान और समय पर उपचार के लिए लॉन्च किया क्षेत्र का पहला फीवर क्लीनिक

हरिभूमि न्यूज ▶▶ फरीदाबाद

मौसमी बुखार और वेक्टर जनित बुखार रोगों में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पीटल ने आज इस क्षेत्र का पहला फीवर क्लीनिक खोलने की घोषणा की है। इस क्लीनिक में मरीजों की मेडिकल जांच, शीघ्र निदान और समय पर उपचार की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं जो उन्हें मौसमी और संक्रामक रोगों से उबरने में सहायक होगी।

फीवर क्लीनिक सोमवार से शनिवार तक दोपहर 3 बजे से 4 बजे के दौरान इंटरनल मेडिसिन टीम फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पीटल फरीदाबाद की देखरेख में काम करेगा। फरीदाबाद स्थित पूरे दिल्ली एनसीआर में मॉनसून और मौसम में बदलाव की वजह से मुख्य रूप से वेक्टर-जनित तथा वायरल संक्रमणों के कारण बुखार के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। यह फीवर क्लीनिक मौसमी वायरल इंफेक्शंस, डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, टायफायड, इंफ्लुएंजा, एन1एच1,अज्ञात कारणों या लंबे समय तक बने रहने वाले एक्यूट और संक्रामक रोगों के अलावा अन्य बैक्टीरिया जनित या संक्रामक कारणों समेत तथा इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड़ मरीजों में बुखार के मामलों में उपचार प्रदान करेगा। मरीजों के लिए विस्तृत रूप से देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करने के मकसद से, क्लीनिक में एक छत के नीचे सभी सेवाएं, जैसे फीवर कंसल्टेशन, स्पेश्यलाइज्ड़ लैब जांच जिनमें सीबीसी और रैपिड डायग्नॉस्टिक टेस्ट, फार्मेसी तथा मेडिकेशन सपोर्ट, डे-केयर एवं अन्य ऑब्जरवेशन सुविधाएं शामिल हैं, इमरजेंसी एस्केलेशन एवं हॉस्पीटल एडमिशन रेफरल्स और फालो.अप आदि उपलब्ध होगा। फीवर क्लीनिक के लॉन्च के मौके पर डॉ राजेश कुमार बुद्धिराजा, सीनियर डायरेक्टर, इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पीटल फरीदाबाद ने कहा कि मानसून और मौसम में बदलाव के समय, बुखार अलग-अलग कारणों से हो सकता है और समय पर रोगी का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण होता है। डॉ बी एन सिंह डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पीटल फरीदाबाद ने कहा कि फीवर क्लीनिक का मकसद समय पर मूल्यांकन और प्रबंधन की सुविधाएं मरीजों के लिए अधिक सुलभ बनाना है। डॉ अनुराग अग्रवाल सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पीटल फरीदाबाद ने कहा कि कुछ बुखार ऐसे होते हैं जिनका प्रबंधन समय पर सही मेडिकल सलाह मिलने से हो सकता है, जबकि कुछ मरीजों को अधिक गहन ऑब्जरवेशन या हॉस्पीटल केयर की आवश्यकता होती है।

---

10 आईफोन 12 सौ रुपए नगद बरामद हुए

फर्जीवाड़ा कर ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले 2 काबू

हरिभूमि न्यूज ▶▶ गाजियाबाद

थाना इन्दिरापुरम पुलिस ने क्रेडिट कार्ड के बिल जमा करने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले 02 ठगों को गिरफ्तार किया है। उनकेकब्जे से 10 मोबाइल आईफोन, 01 बोट एयरपॉड्स, 01 क्रोमा ईअरबड्स, 01फिलिप्स ट्रिमर, 01 फिलिप्स गारमेन्ट्स स्टीमर , 01 पावर बैंक व 3 मोबाइल एडॉप्टर व 1200 रू नगद बरामद हुए है। थाना इन्दिरापुरम पर एक महिला ने तहरीर दी थी कि युवकों द्वारा खुद को एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट कर्मचारी बताकर एक्सिस बैंक के खाते से दो बार में करीब 3,12,589/- रुपए की राशि अनाधिकृत से ऑनलाइन फ्रॉड कर निकाल ली। जिसके संबंध में थाना इन्दिरापुरम पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई।

खबर संक्षेप

फौजी की मौत पर उठ रहे बड़े सवाल

रांची। झारखंड के कटकमसांडी प्रखंड क्षेत्र के छड़वा डैम स्थित जंगल में पेड़ से फंदे के सहारे सेना के जवान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कंचनपुर गांव निवासी धनंजय कुमार देव (29), पिता राजकुमार देव के रूप में हुई है। धनंजय वर्ष 2016 में सेना में भर्ती हुआ था और वर्तमान में आर्मी में जवान के पद पर कार्यरत था। वह करीब एक माह की छुट्टी लेकर घर आया था।

छात्र नेता दिलीप दरभंगा से एमएलसी चुनाव लड़ेंगे

दरभंगा। बिहार के चर्चित छात्र नेता दिलीप कुमार ने आगामी विधान परिषद चुनाव में दरभंगा स्नातक एमएलसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एमएलसी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से हुई कंफ्यूजन को भी दूर कर दिया है। दरअसल, राजद ने पटना स्नातक सीट से भी दिलीप कुमार नाम के कैंडिडेट को टिकट दिया है।

बीएएमएस डॉक्टरों की भत्ता बढ़ाने की तैयारी

लखनऊ। सरकारी चिकित्सालयों में 7,500 रुपये मासिक भत्ते पर इंटर्नशिप कर रहे बीएएमएस डॉक्टरों को अब 25 हजार रुपये मिलने की उम्मीद जगी है। आयुर्वेद सेवा निदेशालय ने भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों और चिकित्सालयों से इंटर्न की संख्या और भत्ता बढ़ाने पर आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का पूरा ब्योरा मांगा है।

उत्तर प्रदेश के 57,600 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी

पीएम नरेन्द्र मोदी की पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' पढ़ने के साथ-साथ आत्मसात भी करनी चाहिए

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर बच्चे को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' जरूर पढ़नी और आत्मसात करनी चाहिए। यह कहना अन्याय होगा कि युवा किताब नहीं पढ़ता, जरूरत किताबों को उन तक पहुंचाने की थी...

हरिभूमि न्यूज ▶▶ लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर बच्चे को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' जरूर पढ़नी और आत्मसात करनी चाहिए।

यह कहना अन्याय होगा कि युवा किताब नहीं पढ़ता, जरूरत किताबों को उन तक पहुंचाने की थी। ज्ञान को संकुचित दायरे में सीमित करने के दुष्परिणाम समाज और राष्ट्र, दोनों को भुगतने पड़ते हैं। 10 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश को 'बीमारू' राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया था। यूपी के

नौजवान के सामने पहचान का संकट था और नागरिक अपनी पहचान बताने से बचते थे। सकारात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप आज प्रदेश की तस्वीर बदली है। डिजिटल युग ने शहर और गांव की दूरी को कम किया है।

पहले संकुचित दायरे में बांधने का प्रयास किया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी व्यक्ति की तरह ही समाज और राष्ट्र भी तब बीमार होता है, जब उसकी क्षमता समाप्त होने लगती है और वह अपनी विरासत से दूरी बनाने लगता है। पहले भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को संकुचित दायरे में बांधने का प्रयास किया गया, जिसके परिणाम सहने पड़े। उत्तर प्रदेश की धरती भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्वपूर्ण केंद्र रही है।

सीएम ने विश्वविद्यालय परिसर में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित 5वें गोमती पुस्तक महोत्सव-2026 का शुभारंभ करने के उपरांत युवाओं को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम ने वहां मौजूद बच्चों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' वितरित की। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को यह पुस्तक पढ़नी और आत्मसात करनी चाहिए। यह केवल स्कूली छात्रों के लिए नहीं, बल्कि हर युवा और नागरिकों के लिए भी उपयोगी है। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है।

युवा किताब नहीं पढ़ता, यह कहना अन्याय

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कहना कि युवा पुस्तकों से दूर हो गया या सोशल मीडिया पर अपना समय खराब कर रहा, पूरी तरह सही नहीं। ऐसा कहना युवा के साथ अन्याय होगा। जरूरत पुस्तकों को उसके पास पहुंचाने की व्यवस्था करने की है। जब पहली बार युवराज मलिक ने लखनऊ में पुस्तक महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था, तब मैंने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से चर्चा की। इसे प्रोत्साहित करने की बात कही।

17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक प्रदेशभर में चलेगा 'सेवा संकल्प अभियान'

मोदी के साथ न वंश परंपरा थी, न विरासत तप-साधना व संघर्ष से बनाई पहचानः सीएम

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वडनगर से काशी तक की यात्रा को अभियान से जोड़ते हुए बड़नगर से काशी और काशी से बड़नगर के लिए दस-दस यात्राएं निकलेंगी...

हरिभूमि न्यूज ▶▶ लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ न कोई वंश परंपरा थी और न ही उन्हें कोई विरासत वंशानुगत रूप से मिली थी। उनके पास तप, साधना, संघर्ष और देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत थी। आज उनकी साधना और तप का लाभ पूरे देश को योग्य नेतृत्व के रूप में मिल रहा है। सात अक्तूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में शासन प्रमुख के तौर पर नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस यात्रा के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन मिलकर 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक प्रदेशव्यापी 'सेवा संकल्प अभियान' चलाएंगे।

भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने अभियान की कार्ययोजना साझा करते हुए कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन प्रदेशभर में 'सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन हर ग्राम पंचायत, नगर निकाय और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान में 'आशीर्वाद का दीया' जलाया जाएगा। इसके जरिये प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करेगी। अस्पतालों में फल वितरण के साथ रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी सेवा कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में जलेगा 'आशीर्वाद का दीया'

वंचित पात्रों तक योजनाएं पहुंचाएगा 'सेवा सेतु'

अभियान के तहत सरकारी योजनाओं से अब तक वंचित पात्र लोगों को लाभ दिलाने के लिए 'सेवा सेतु' शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 29-30 सितंबर से 10 अक्तूबर के बीच प्रत्येक विकासखंड और जिला मुख्यालय के नगर निकाय में छह से सात दिन तक शिविर लगाने की योजना है। इनमें स्वास्थ्य योजनाओं के साथ पेंशन, आवास, शौचालय, राशन कार्ड समेत विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र लोगों का पंजीकरण कराया जाएगा। योगी ने कहा कि पंजीकरण के बाद दो-तीन दिन के भीतर सत्यापन कर संबंधित कार्ड अथवा योजना का लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में 826 विकासखंड और 762 नगर निकाय हैं। जरूरत पड़ी तो अभियान दो चरणों में चलाया जाएगा। प्रयास यह रहेगा कि पात्र व्यक्ति केवल आवेदन देकर वापस न जाए, बल्कि शिविर के दौरान ही उसे संबंधित योजना से जोड़ दिया जाए।

बड़नगर से काशी तक की यात्रा को भी अभियान से जोड़ा गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की बड़नगर से काशी तक की यात्रा को भी अभियान से जोड़ा गया है। बड़नगर से काशी के लिए 10 और काशी से बड़नगर के लिए 10 यात्राएं निकाली जाएंगी। बड़नगर का जल लेकर यात्राएं काशी आएंगी, जबकि उत्तर प्रदेश की 10 नदियों का पवित्र जल लेकर यात्राएं बड़नगर जाएंगी। सभी यात्राएं 17 सितंबर को शुरू होंगी और सात अक्तूबर को अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी। यात्रा मार्ग पर हर दिन चार स्थानों पर चौपाल और जनसंवाद के कार्यक्रम होंगे।

सम्राट सरकार का बड़ा फैसला

पेपर लीक रोकने के लिए 29 जिलों में परीक्षा भवन और स्ट्रॉन्ग रूम बनेंगे

एजेंसी ▶▶ पटना

बिहार में पेपर लीक और एग्जाम में कदाचार को रोकने के लिए 29 जिलों में परीक्षा भवन और स्ट्रॉन्ग रूम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में बिहार बोर्ड यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) को निर्देश दे दिए हैं।

सरकार ने 33 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। पहले चरण में 12 जिलों में परीक्षा भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इनमें सीतामढ़ी, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, कैमूर, नालंदा, मधेपुरा जैसे जिले शामिल हैं।

पहले चरण में इन शहरों में बनेंगे परीक्षा भवन

बीएसईबी की ओर से पहले चरण में 12 जिलों में एग्जाम सेंटर और स्ट्रॉन्ग रूम के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। रोहतास जिले में सासाराम के तकिया श्रीशंकर उच्च माध्यमिक विद्यालय, लखीसराय में शरमा, रामगढ़ चौक स्थित श्रीढ़ेरनाथ महादेव उच्च विद्यालय, बेगूसराय के विष्णुपुर में राजकीय बुनियादी विद्यालय, सीतामढ़ी जिले में डुमरा के बरियारपुर मध्य विद्यालय, मोतिहारी में पीएमश्री जिला स्कूल, वैशाली जिले के भगवानपुर स्थित सराय आदर्श उच्च विद्यालय, भभुआ के रतवार उच्च माध्यमिक विद्यालय, नालंदा में राजगीर के आरडीएस प्लस 2 विद्यालय, जमुई में जमुई बाजार प्लस टू उच्च विद्यालय, कटिहार में दर्शन साह कॉलेज, नवादा में कन्हाई इंटर स्कूल और मधेपुरा में भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी परिसर में परीक्षा भवन का निर्माण होगा।

आवश्यक सामग्री के सुरक्षित भंडारण की सुविधा

अधिकतर परीक्षा भवन और स्ट्रॉन्ग रूम को मौजूदा स्कूलों के परिसर में ही बनाया जाएगा। लगभग एक से डेढ़ एकड़ जमीन पर परीक्षा भवन के साथ स्ट्रॉन्ग रूम का निर्माण किया जाएगा। परीक्षा भवन में छात्र-छात्राओं के कदाचार मुक्त एग्जाम की सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। वहीं, स्ट्रॉन्ग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम के पेपर और आंसर शीट आदि को रखने की व्यवस्था होगी। सरकार का कहना है कि इससे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के पेपर एवं अन्य आवश्यक सामग्री के सुरक्षित भंडारण की सुविधा मिलेगी।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा ने किया एक अहम प्रयोग

मायावती की भतीजी दीपिका मिशन को आगे बढ़ाएंगी

अब आनंद के बेटों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी

एजेंसी ▶▶ लखनऊ

बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब भाई आनंद कुमार के बेटे नहीं बल्कि उनकी बेटी दीपिका आनंद बसपा के मिशन को आगे बढ़ाएगी। मेरे लिए मिशन सर्वोपरि है,

लिहाजा अब मेरे भाई आनंद कुमार के बेटे नहीं, वकालत की पढ़ाई कर रही बेटी दीपिका आनंद पार्टी का कार्य करेगी। आनंद जरूरत पड़ने पर अपनी जिम्मेदारियां उसे सौंप सकते हैं। आनंद दोनों बेटों को व युवा बच्चों में से किसी को भी जिम्मेदारी नहीं सौपेंगे। बेटी के तैयार नहीं होने पर दलित वर्ग में से ही अन्य किसी मिशनरी कार्यकर्ता को भी अपनी यह जिम्मेदारी दे सकते हैं। आनंद के किसी भी बेटे को मौका नहीं देंगे । बसपा में किसी भी छोटे-बड़े पद पर राजनीति करने का मौका नहीं दिया जाएगा।

कांशीराम की तरह मैं भी 'परिवारवाद' की विरोधी

मायावती ने कहा कि अविवाहित होने की मजबूरी की वजह से मुझे अपने सभी सगे भाई-बहनों में से आनंद कुमार को अपने साथ रखने की भी जरूरत पड़ी है, जो मेरी देखभाल करने के साथ मेरी निगरानी में पार्टी की अहम जिम्मेदारियों को लंबे समय से निभा रहे हैं। लेकिन इसका लाभ अब उनके परिवार के लोग भी उठाएं, यह पार्टी व मूवमेंट के हित में सही नहीं होगा। कांशीराम जिस प्रकार से 'परिवारवाद' के विरुद्ध रहे, उनकी शिष्या होने के नाते मैं भी उसी पर कायम हूं। यदि मैं लड़की नहीं होती तो कांशीराम की तरह अपने भाई-बहनों आदि में से किसी को साथ नहीं रखती। अपनी सुरक्षा, हर परेशानी से मुक्त होकर आगे बढ़ने की मजबूरी में छोटे भाई आनंद को साथ रखना पड़ा है। मैं किसी के मोह में पड़कर पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी।

केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा मौका

मायावती ने कहा कि संगठन व सरकार बनने पर भी चाहे वह कोई भी हो, केवल एक व्यक्ति को ही मौका दिया जाएगा। उसकी आड़ में उसके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा, ताकि पार्टी परिवारवाद से मुक्त रहे तथा सर्वसमाज में से ज्यादा से ज्यादा लोग 'सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति' आंदोलन के सहभागी बन सकें।

डीजी के साथ की तकनीकी गतिविधियों और अनुसंधान कार्यों की समीक्षा

जरूरतों के अनुरूप भारतीय रेल में तकनीकी विकास

टेस्टिंग लैब्स से लेकर ट्रैक मशीन सुविधाओं का किया गया निरीक्षण

टी एन मिश्र ▶▶ लखनऊ

रेलवे बोर्ड के सदस्य अवसंरचना विवेक कुमार गुप्ता ने लखनऊ पहुंचकर अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) का दो दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आरडीएसओ में चल रही विभिन्न तकनीकी गतिविधियों और अवसंरचना से जुड़े कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।

डीजी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने भारतीय रेल की जरूरतों के अनुरूप तकनीकी विकास पर मंथन किया! इस दौरान गुप्ता ने आरडीएसओ की भू-तकनीकी, ट्रैक मशीन एवं मॉनिटरिंग, पुल एवं संरचना, धातु एवं रसायन, सिग्नल, एयर ब्रेक, इलेक्ट्रिक लोको

और फैटिग टेस्टिंग प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने इन स्थानों पर उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं, परीक्षण क्षमता और मौजूदा अवसंरचना की जानकारी ली। गुप्ता ने आरडीएसओ के महानिदेशक प्रमोद दनसाना और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में संगठन की तकनीकी गतिविधियों और अवसंरचना से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। महानिदेशक ने आरडीएसओ की ओर से भारतीय रेलवे की बदलती तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए किए जा रहे कार्यों और प्रमुख पहलों की जानकारी दी।

अनुसंधान और डिजिटल तकनीक पर जोर

विवेक कुमार गुप्ता ने आरडीएसओ की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की भी समीक्षा की। इस दौरान आरडीएसओ की ओर से प्रस्तुतीकरण दिया गया। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (क्रिस) और राइट्स (राइट्स) की ओर से इंस्पेक्शन पोर्टल के संबंध में भी जानकारी दी गई। इसमें निरीक्षण प्रक्रिया को अधिक मजबूत और व्यवस्थित बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया।

एआई मंथन 2.0 में देशभर के विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव

लखनऊ। राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में दो दिवसीय 'एआई मंथन 2.0' का शुभारंभ हुआ। जन भवन और विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में देशभर से आए विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने एआई की संभावनाओं पर चर्चा की। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी व तकनीकी टीमों समेत 500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, शासन और विश्वविद्यालय प्रशासन में एआई के उपयोग पर विचार रखे।

पेज एक का शेष

पहलगाम हमले के साथ ...

गई थी। इस हमले का बदला भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य कार्रवाई के जरिए लिया। जिसमें भारत-पाक नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार पाकिस्तान में छिपे बैठे 100 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था।

भारत से पश्चिम को गया ...

सामान्य बात है। खाड़ी के कई देश पश्चिम-एशिया युद्ध में आपस में लड़ रहे हैं, रूस भी युद्ध लड़ रहा है। लेकिन नई दिल्ली ने अपनी प्राथमिकता में शुमार शांति-स्थिरता की बात को जिस तरह से आम सहमति के साथ आगे बढ़ाया है। वह वाकई सराहनीय है। यह शांति न केवल भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए आवश्यक है। बल्कि इसका विश्व की भलाई के लिए भी बड़ा महत्व है।

शांति को धरातल पर जांचना जरूरीः विदेश मामलों के विशेषज्ञ डॉ. हेमंत अदलखा ने कहा कि बदलते वैश्विक माहौल और भारत-अमेरिका संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो दिल्ली में हो रहा ब्रिक्स सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह पश्चिम-एशिया से लेकर यूक्रेन तक युद्धों की जल्द समाप्ति के पक्ष में हैं। इन्हें खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन यहां मुख्य मुद्दा यह है कि क्या भारत ने शांति की दिशा में सिर्फ अपनी सोच दुनिया के सामने दृढ़ता के साथ रखी है या फिर इसके पीछे हमारे पास कोई ठोस योजना भी है। मेरे मुताबिक, ब्रिक्स का नई दिल्ली घोषणापत्र, हालिया समय में संपन्न हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन के अंत में सामने आए दस्तावेज से काफी हद तक मेल खाता हुआ नजर आता है। जिसमें समूह ने आम सहमति के साथ ईरान का नाम लिए बगैर ये कहा था कि तेहरान में जो कुछ हो रहा है, एससीओ उसकी निंदा करता है।

चीन के रुख से मिलते विचित्र संकेत : अदलखा ने कहा कि उन्हें चीन की तरफ से राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ब्रिक्स सम्मेलन में भागीदारी को लेकर अंतिम पलों में दी गई स्वीकृति वाला व्यवहार उचित नहीं लगा। एक ओर चीन ब्रिक्स का सबसे बड़ा सहयोगी और हिमायती होने का दावा करता है। वहीं, दूसरी ओर उनके राष्ट्राध्यक्ष समूह के सबसे बड़े वार्षिक आयोजन में शिरकत करने के संबंध में निर्णय आयोजन से ठीक पहले करते हैं। यहां इस मुद्दे को उद्घाटित करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि एलएसी विवाद की समाप्ति के बाद भारत और चीन भी अपने संबंधों को पुनः पटरी पर लाने के लिए प्रयासरत हैं। जिसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि ड्रैगन के संबंध में हर कदम फूंक-फूंक कर रखना जरूरी हो जाता है।

नौवीं क्लास में 3 छात्रों ने सहपाठी को बनाया हवस का शिकार, पिता बोले- कैमरे में कैद घटना

लखनऊ। यूपी के बुलंदशहर स्थित जहांगीराबाद के एक इंटर कॉलेज में कक्षा नौ के छात्र के साथ कुकर्म का मामला प्रकाश में आया है। छात्र ने अपनी ही कक्षा में पढ़ने वाले तीन सहपाठियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद छात्र के पिता शनिवार को शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। छात्र के पिता के अनुसार, उन्हें दोपहर में विद्यालय से बेटे के साथ झगड़ा होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर वह विद्यालय पहुंचे। वहां बेटे ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। पिता का आरोप है कि घटना की जानकारी सामने आने के बाद भी विद्यालय स्टाफ ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मामले में विद्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

घटना कैमरे में कैद है : छात्र पक्ष का दावा है कि घटना से संबंधित वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग में मौजूद है। पिता के मुताबिक, उन्होंने विद्यालय के एक शिक्षक से रिकॉर्डिंग के संबंध में जानकारी मांगी, लेकिन वीडियो होने से इनकार किया गया। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता और उसमें दर्ज घटनाक्रम पुलिस जांच का अहम हिस्सा हो सकता है।

पुलिस सीसीटीवी जांच में जुटीः गंभीर आरोपों के बाद छात्र के पिता कोतवाली पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस अब शिकायत, छात्र के बयान, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समेत अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। नाबालिग से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेगी। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

परिषदीय स्कूलों में चाइल्ड ट्रैकिंग के लिए 6.55 करोड़ जारी

यू-डायस प्लस के आंकड़ों से बच्चों की शैक्षिक स्थिति व नामांकन की होगी बेहतर निगरानी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों में बच्चों से जुड़ी सूचनाओं की निगरानी, विद्यालयी प्रबंधन और शैक्षिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

इसी क्रम में वर्ष 2026-27 के लिए एमआईएस (यू-डायस प्लस) और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के प्रभावी संचालन एवं उपयोग के लिए 6.55 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को धनराशि के उपयोग

और निगरानी के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ज्ञात हो कि इस व्यवस्था के माध्यम से योगी सरकार विद्यालयी आंकड़ों को अधिक व्यवस्थित, बच्चों की शैक्षिक प्रगति की निगरानी को अधिक प्रभावी तथा स्कूल प्रबंधन को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में डिजिटल प्रणालियों के उपयोग को मजबूत कर रही है। निर्देशों के अनुसार कुल 655.01 लाख रुपये की धनराशि जारी की जा रही है।

हर बच्चे की जानकारी को व्यवस्थित करने पर जोर

निर्देशों में यू-डायस प्लस पर विद्यालयों एवं विद्यार्थियों से संबंधित आंकड़ों के संकलन और उनके उपयोग को महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से बच्चों की शैक्षिक स्थिति पर नजर रखने की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। पत्र में अपार आईडी और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट पहचान के साथ उसकी शैक्षिक जानकारी को व्यवस्थित रूप से ट्रैक किया जा सके।

विशेषः हिंदी दिवस, 14 सितंबर

हर साल 14 सितंबर के आस-पास सरकारी दफ्तरों में हिंदी पखवाड़ा शुरू होता है, मंचों से हिंदी की महिमा गाई जाती है और अपनी भाषा पर गर्व करने की बातें होती हैं। लेकिन इन औपचारिकताओं से आगे बढ़कर हमें यह सवाल भी पूछना चाहिए कि क्या हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में हिंदी को सचमुच सम्मान देते हैं? उससे प्यार करते हैं?

हमारे हिंदुस्तान की आत्मा है हिंदी

आवरण कथा

यामिनी गजानन रामपल्लीवार

भाषा और संस्कृति का रिश्ता कोई ऊपरी बंधन मात्र नहीं होता, वह जड़ और वृक्ष का रिश्ता होता है। हिंदी के संदर्भ में यह बात और भी गहरे अर्थ रखती है, क्योंकि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, हिंदुस्तान की सांस्कृतिक पहचान का जीवंत प्रमाण है। इसकी जड़ें संस्कृत जैसी वैज्ञानिक और अनुशासित भाषा में हैं, जिसने भोजपुरी, अवधी और ब्रज जैसी सैकड़ों बोलियों को अपनी सुंदर शाखाओं की तरह जन्म दिया। यह विस्तार किसी एक भाषा की सीमा नहीं, बल्कि एक पूरे उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक चेतना का फैलाव है।

भाषा से जुड़ी देश की पहचान

14 सितंबर को जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं, तो यह अवसर केवल एक तिथि का उत्सव नहीं होना चाहिए। यह अवसर रुककर यह सोचने का भी हो कि हमने इस भाषा को कितना जिया है और कितना केवल औपचारिकता में समेट दिया है? इतिहास गवाह है कि जब कवि इकबाल ने लिखा था, 'हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा।' तब उन्होंने भाषा और राष्ट्र की पहचान को एक ही सांस में बांध दिया था। उनकी यह पंक्ति आज भी उतनी ही सार्थक है, क्योंकि जिस भाषा की पहचान हिंद महासागर के तट से लेकर हिमालय की चोटियों तक फैली हो, वह भाषा किसी परिचय की मोहताज नहीं।

शब्दों में सदियों की साधना

हिंदी का यह वैभव किसी एक कवि या रचनाकार की देन नहीं, बल्कि सदियों की साधना का परिणाम है। तुलसी ने इसे भक्ति की मिठास दी, सूर ने इसमें वात्सल्य का रस घोला, कबीर ने इसे सीधी और निर्भीक वाणी दी और निराला ने इसमें विद्रोह और नवीनता का स्वर भरा। इन सबने मिलकर हिंदी को वह समृद्धि दी, जो आज भी हर हिंदुस्तानी की रग-रग में बहती है। यही कारण है कि हिंदी को केवल एक भाषा कहना उसके साथ अन्याय होगा, वह तो भावनाओं की वह साझी विरासत है, जिसमें देश की विविधता खुद को सहज पाती है।

समावेशी भाषा है हिंदी

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हिंदी की श्रेष्ठता का यह अर्थ कभी नहीं कि अन्य भाषाओं या बोलियों को कमतर आंका जाए। हिंदी का असली गौरव इसी में रहा है कि उसने सदा दूसरी भाषाओं और बोलियों को अपनाया, उनसे शब्द लिए और उन्हें भी फलने-फूलने का अवसर दिया। भोजपुरी, अवधी, ब्रज, मैथिली और राजस्थानी जैसी बोलियां हिंदी की प्रतिद्वंद्वी नहीं, उसकी शक्ति हैं। इसी समावेशी स्वभाव के कारण हिंदी हर हिंदुस्तानी के मन में अपना स्थान बना पाई है।

कहां हैं झिझक की जड़ें

यह विडंबना ही है कि आज कुछ लोगों को हिंदी बोलते हुए झिझक या कमतरी का एहसास होता है। यह झिझक कहां से आती है, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बड़े शहरों के कॉर्पोरेट कार्यालयों में, महानगरों की पार्टियों में और यहां तक कि कुछ शिक्षित परिवारों में भी हिंदी बोलने को पिछड़ेपन से जोड़कर देखा जाने लगा है। अंग्रेजी में दक्षता आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि वह आज वैश्विक संपर्क की भाषा बन चुकी है। परंतु किसी दूसरी भाषा को सीखने और अपनी भाषा को त्यागने में बुनियादी अंतर है। जब यह अंतर धुंधला पड़ने लगता है, तभी भाषा का यह संकट जन्म लेता है। बरसों पहले मेरे एक पारिवारिक समारोह में एक किशोर अपनी दादी से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करने लगा, टूटे-फूटे शब्दों में, केवल इसलिए कि साथ बैठे उसके अंग्रेजी-माध्यम के मित्र उसे 'देसी' न समझें। दादी ठहरकर मुस्कुराईं और बोलीं, 'बेटा, जिस भाषा में मैंने तुझे कहानियां सुनाईं, उसी में बात कर, शर्म किस बात की?'

उस किशोर की दादी के एक वाक्य ने पूरा वातावरण बदल दिया। गहराई से सोचें तो स्पष्ट होता है, वह झिझक केवल उस बच्चे की नहीं थी, वह उस पूरी पीढ़ी की झिझक थी, जिसे यह सिखाया गया कि तरक्की अंग्रेजी की जुबान से होकर गुजरती है और अपनी भाषा पीछे छूट जाने वाली चीज है। यह संकट केवल भाषाई नहीं, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक भी है। जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा बोलने में संकोच करता है, वह धीरे-धीरे अपनी जड़ों से भी दूर होता चला जाता है। हमें इस बात को समझना होगा कि भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, वह सोचने की एक शैली होती है, संस्कारों को आगे बढ़ाने का माध्यम होती है। जब बच्चा अपनी दादी की कहानियां, लोरियां हिंदी में नहीं सुन पाता, जब वह लोकगीतों की लय से अपरिचित रह जाता है, तो वह केवल एक भाषा नहीं खोता, अपने भीतर की एक पूरी दुनिया खो देता है।

सभी करें हिंदी का सम्मान

यह कहना उचित होगा कि भाषा का अपमान केवल उस भाषा का अपमान नहीं, वह पूरी संस्कृति का अपमान है। जिस तरह किसी वृक्ष की जड़ों को काटकर उसकी शाखाओं की हरियाली की उम्मीद नहीं की जा सकती, उसी तरह अपनी भाषा से कटकर अपनी सांस्कृतिक पहचान को जीवंत रखने की कल्पना भी अधूरी रह जाती है। यह प्रवृत्ति बदलनी चाहिए और इसके लिए किसी बड़े आंदोलन की नहीं, बल्कि छोटे-छोटे व्यावहारिक प्रयासों की आवश्यकता है। घर के भीतर बच्चों से हिंदी में बात करना, कार्यस्थल पर जहां संभव हो वहां हिंदी को सहजता से अपनाना, हिंदी साहित्य को केवल पाठ्यक्रम की मजबूरी न मानकर आनंद के लिए साहित्यिक किताबें पढ़ना, ऐसे ही अनेक छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।

संकल्प लेने का दिन हिंदी दिवस

आज जब हिंदी दिवस के अवसर पर सरकारी कार्यालयों में औपचारिक समारोह होंगे, भाषणों में हिंदी की महिमा गाई जाएगी, तब यह प्रश्न स्वयं से पूछना जरूरी है कि क्या हमने इस भाषा को अपने दैनिक जीवन में उतना सम्मान दिया, जितना वह हकदार है। हिंदी को बचाने की जिम्मेदारी किसी एक दिन या किसी एक विभाग की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है, जो इसे अपनी भाषा मानता है। हिंदी दिवस केवल स्मरण का दिन नहीं, संकल्प का दिन बने, यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम अपनी भाषा बोलने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक उसकी समृद्ध विरासत आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए आइए, इस हिंदी दिवस पर केवल उत्सव नहीं, आत्मनिरीक्षण भी करें और अपनी भाषा को उसका वास्तविक सम्मान लौटाएं। *

विशेषः गणेश चतुर्थी

परंपरा-आस्था का संगम महापर्व गणेशोत्सव

गणेश चतुर्थी से आरंभ होने वाला गणेशोत्सव केवल धार्मिक पर्व नहीं है। इसकी जड़ें भारत की परंपरा, इतिहास और संस्कृति से भी जुड़ी हैं। इस पर्व का आरंभ सामाजिक समारोहों के रूप में कब और कैसे हुआ, आप जरूर जानना चाहेंगे।

सांस्कृतिक पर्व / शिखर चंद जैन

गणेश चतुर्थी का त्योहार भारतीय जनमानस के हृदय में अत्यंत पवित्र स्थान रखता है। यद्यपि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी (14 सितंबर) को विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की स्थापना और अनंत चतुर्दशी को उनके विसर्जन का दृश्य हर वर्ष भारत के कोने-कोने में दिखाई देता है, परंतु इस महापर्व के कई ऐसे पहलू हैं, जो बहुधा लोकस्मृति या सामान्य वार्ताओं से परे छूट जाते हैं। यह उत्सव केवल धार्मिक कर्मकांड, ढोल-नगाड़ों और सुंदर झांकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके मूल में राजनीति, समाज, प्राचीन भूगोल, खगोल विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण की गहरी जड़ें जुड़ी हुई हैं। गणेश चतुर्थी भारत की उस अमर सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, जो अध्यात्म को समाज सेवा से, इतिहास को भविष्य की सोच से और धर्म को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ती है।

तिलक की दूरदर्शी सामाजिक पहलः गणेश चतुर्थी का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और 18वीं शताब्दी में पेशवाओं के काल में इसे पुणे में राज्योत्सव के रूप में मनाया जाता था। आधुनिक भारत में इसका स्वरूप पूरी तरह से बदलने का श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। वर्ष 1893 में तिलक ने इसे निजी गृह-पूजा के बंद कमरों से निकालकर 'सार्वजनिक गणेशोत्सव' का रूप दिया।

ब्रिटिश हुकूमत के दौर में 'वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट' और अन्य कठोर कानूनों के कारण भारतीयों के लिए राजनीतिक सभाएं करना या सामाजिक मुद्दों पर एकत्र होना पूरी तरह प्रतिबंधित था। तिलक ने भांप लिया कि अंग्रेज शासक धार्मिक सम्मेलनों में सीधे हस्तक्षेप करने से डरते हैं। अतः उन्होंने गणेशोत्सव को एक सांस्कृतिक और सामाजिक मंच बनाया। पंडालों में स्वतंत्रता संग्राम के विचारों, स्वदेशी आंदोलनों और समाज सुधारों पर चर्चा होने लगी। इस प्रकार, एक धार्मिक उत्सव औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जनक्रांति का प्रतीक बन गया।

जल निकायों का वैज्ञानिक कायाकल्पः आधुनिक समय में विसर्जन के कारण होने वाले जल प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की जाती है, लेकिन पुराने दौर में गणेश प्रतिमा का निर्माण और उसका जल-विसर्जन एक अत्यंत वैज्ञानिक और पर्यावरणीय प्रक्रिया थी। पारंपरिक रूप से, गणेश प्रतिमाएं केवल शुद्ध चिकनी मिट्टी (शाडू माटी) से बनाई जाती थीं। इसमें हल्दी, चंदन, भस्म और कुमकुम का लेप किया जाता था। मानसून के अंत में जब नदियां और तालाब नए पानी से भर जाते थे, तब इन मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित किया जाता था। मिट्टी, जल निकायों को समृद्ध करती थी, जबकि हल्दी और चंदन प्राकृतिक एंटीसेप्टिक तथा जीवाणुरोधक के रूप में पानी को शुद्ध करते थे। यह प्राचीन परंपरा वास्तव में वर्षा ऋतु के बाद जल स्त्रोतों के वैज्ञानिक कायाकल्प का माध्यम थी।

मोदक का औषधीय महत्वः गणेश जी को 'मोदक प्रिय' कहा जाता है, लेकिन मोदक केवल एक स्वादिष्ट मिठाई नहीं है। इसका निर्माण आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है। पारंपरिक रूप से भाद्रपद (सितंबर) के महीने में उकडीचे मोदक (भाप में पके हुए मोदक) बनाए जाते हैं। मानसून के खत्म होने और शरद ऋतु के आगमन के समय शरीर में 'पित्त' दोष बढ़ने की संभावना होती है। मोदक के बाहरी आवरण में चावल का आटा और अंदर गुड़, ताजा कसा हुआ नारियल, जायफल और इलायची का मिश्रण होता है, जिसे शुद्ध देशी घी के साथ परोसा जाता है। नारियल और गुड़ पेट की अग्नि को शांत करते हैं और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं। इस तरह मोदक का भोग ऋतु परिवर्तन के दौरान स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला एक आयुर्वेदिक आहार है।

समृद्ध करे सांस्कृतिक परिदृश्यः भारत के कला और सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध करने में गणेशोत्सव ने एक 'अदृश्य अकादमी' के रूप में भूमिका निभाई है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में सार्वजनिक पंडालों द्वारा संगीत संध्याएं, नाटक (नाट्य संगीत), लोककलाएं (जैसे लावणी, गोंधल) और नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस तरह इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। *

कविता

अलका 'सोनी'

जन-मन में बसती है हिंदी

किताबों के पन्नों पर
पढ़े जाने से पहले,
भाषणों में,
कहीं सुने जाने से पहले,
गूंजी थी वो मेरे कानों में।
जैसे गूंजी थी
अभिमन्यु के कानों में
चक्रव्यूह भेदने की कला।
फिर अकसर गूंजती ही रही वो,
मां की आवाज में।
लोरी में,
और पिता की डांट में
छिपे दुलार में भी।
और उनके कई
अनकहे भय के बीच,
हौंसला देने वाले संसार में भी।
उसने तब भी
गले लगाया था मुझे
जब मैं नहीं जानती थी
उसके व्याकरण का कोई नियम।
क्योंकि यह उसके
और मेरे बीच के
उन रिश्तों की गर्माहट है,
जिन्हें परिभाषित नहीं कर सकता
कोई शब्दकोश।
वो मेरे आंगन में बिखरी
सुबह की धूप है।
सर पर बनी रहने वाली,
ममता की छांव है।
दादी की कहानी में
हर बार आता हुआ
कोई पुराना गांव है।
वो और कोई नहीं
मेरी हिंदी है।
जिसमें बसी है
कबीर की निर्भीकता,
तुलसी की लोक-गंध की खुशबू
प्रेमचंद के पात्रों का संघर्ष,
महादेवी की करुणा,
और निराला की विद्रोही चेतना।
क्योंकि मेरी हिंदी ने
बनाया है
राजमहलों से अधिक
जन-मन में अपना घर।

व्यंग्य / गोविंद भारद्वाज

सरकार जब नई आती है तो रुतबा जमाने के लिए और आमजन में भरोसा कायम करने के लिए यह आदर्श वाक्य दोहराती है कि हमारी सरकार में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन धीरे-धीरे नए-नए तरीके से गड़बड़ी आरंभ हो जाती है।

गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं

गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं-यह जुमला मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं। यह जुमला आज के दौर में उतना ही प्रसांगिक है, जितना पुराने दौर में। सत्ता आए या जाए, सरकार किसी की भी बने लेकिन 'गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं' स्थाई आदर्श वाक्य है। यह न बदला है और न कभी बदलेगा। सरकार जब नई आती है तो रुतबा जमाने के लिए और आमजन में भरोसा कायम करने के लिए यह आदर्श वाक्य दोहराती है कि हमारी सरकार में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। धीरे-धीरे नए-नए तरीके से गड़बड़ी आरंभ होती है और पांच साल तक गड़बड़ी के सहारे ही सरकार चलती है। गड़बड़ी कोई और नहीं उन्हीं के नेता और कार्यकर्ता करते हैं। आम लोग तो उनकी गड़बड़ी बर्दाश्त करते हैं। सरकारों की बात छोड़िए हमारे यहां के प्रशासन ने भी इसे नारा ही बना लिया है। कोई आला अधिकारी जब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है तो वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी को यही हिदायत देता है, 'मेरे होते हुए गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।' जिले में बैठे अफसर भी यही कहते हैं कि जिले में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल प्रशासन से लेकर सचिवालय प्रशासन तक के अधिकारी बस यही आदर्श वाक्य इस तरह से दोहराते हैं कि जनता और कर्मचारी उनके इस वाक्य से डर जाएंगे। भैया डरना तो दूर की बात वे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि थोड़े दिन रुक जाओ अभी नया-नया आया है। सचमुच नयापन झड़ते ही वह अधिकारी भी पुराने ढर्रे पर आ जाता है और गड़बड़ी बर्दाश्त करने का आदी हो जाता है। आप से ही यह कहकर निश्चिंत हो लेता है कि गड़बड़ी कहां नहीं होती! यह देश चल ही रहा गड़बड़ियों के सहारे है। गड़बड़ी बर्दाश्त करना हमारी परंपरा है। बिना गड़बड़ के तो सरकार चल ही नहीं सकती। गड़बड़ी नहीं होगी तो पुलिस की क्या जरूरत। जांच करने के लिए कोई आयोग बनाया तब ही जाएगा, जब गड़बड़ी होगी। कुल मिलाकर गड़बड़ी बर्दाश्त करना हमें आना चाहिए। जो गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता वह कुशल प्रशासक बन ही नहीं सकता। पिछले दिनों की बात है हमारे शहर के माननीय ने कार्यग्रहण किया। दूसरे दिन समाचार पत्र में छपा कि महोदय ने आला अधिकारियों के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला और शहर वासियों को संदेश दिया की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि कौन-सी और किस प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी? ये चोर-लुटेरों, बदमाशों, उठाईगीरों या जमाखोरों, भ्रष्टाचारियों, लापरवाहों, रिश्वतखोरों, बलात्कारियों या मिलावटखोरों के लिए चेतावनी दी गई या आम नागरिकों के लिए। खैर यह जुमला असरदार हो न हो पर लोगों को दिलासा दिलाए रखने के लिए कहना जरूरी है। हालांकि गड़बड़ी करता कौन है, ये विषय शोध का है। *

पुस्तक चर्चा / विज्ञान भूषण

संगीतमय जीवन

विख्यात खयाल गायिका गंगूबाई हंगल की आत्मकथा कई वर्ष पहले कन्नड़ भाषा में प्रकाशित हुई थी। हाल में ही उसका हिंदी अनुवाद 'जीवन संगीत' शीर्षक से प्रकाशित होकर आया है। यह आत्मकथा सामाजिक उपेक्षाओं, पारिवारिक समस्याओं और आर्थिक संकटों के बीच रहकर संगीत को समर्पित एक कलाकार की साधना यात्रा है। गंगूबाई हंगल ने कई स्थलों पर स्वीकार किया है कि उनकी मां के त्याग और उनके गुरुओं के सही मार्गदर्शन ने ही उन्हें इतनी प्रतिष्ठा दिलाई। यही नहीं वे पूरी विनम्रता से हर उस शख्स के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती दिखाई देती हैं, जिन्होंने किसी भी रूप में उनकी संगीत साधना में जरा भी सहयोग प्रदान किया था। हालांकि कुछ स्थलों पर उनके मन में समाई टीस प्रकट हुई है। जातिगत भेदभाव पर अपने अतीत को याद करते हुए वह कहती हैं, 'अगर हम लोग किसी ऊंची जाति के घर खाना खाने जाते थे तो हमें खुद अपने बर्तन मांजने पड़ते थे।' किशोरावस्था में ही विवाह कर दिए जाने और उसके कुछ समय बाद ही मां-पिता के निधन होने के बावजूद गंगूबाई ने कभी अपनी संगीत साधना में व्यवधान नहीं आने दिया। इसी का परिणाम रहा कि वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों के सोपानों पर अग्रसर रहीं और अद्वितीय प्रतिष्ठा प्राप्त की। इस आत्मकथा में कहीं भी आत्मश्लाघा का भाव नजर नहीं आता है। वे अपने सभी प्रशंसक संगीत प्रेमियों, विभिन्न सम्मानों से नवाजने के लिए सरकार के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करती हैं। *

पुस्तकः जीवन संगीत- गंगूबाई हंगल (आत्मकथा), अनुवादः मृत्युंजय, मूल्यः 199 रुपए, प्रकाशकः राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली

लघुकथाएं

परीक्षा

पिछली सर्दियों की बात है। रात के अंधेरे को चीरती हुई ट्रेन अंबाला की तरफ भागती चली जा रही थी और साथ ही मेरी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में अंबाला आने वाला था। आज सुबह की ट्रेन से मैं पापा के साथ दिल्ली गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर की परीक्षा देने और अब वापिस लौट रही थी। वापस लौटते हुए ट्रेन में पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। माइग्रेन के दौरे के कारण उन्हें चक्कर आने लगे थे और मितली भी। ऐसी तकलीफ उन्हें हर चार-छह महीने में कभी भी हो जाया करती थी। ऐसे में उन्हें दो दिनों तक पूरा आराम करना पड़ता था। ट्रेन ने रात के एक बजे अंबाला पहुंचना था। मुझे डर लग रहा था कि सर्दी की ठिठुरती रात में इस समय मैं पापा को संभाले हुए सुरक्षित घर तक कैसे पहुंचूंगी? घर से स्टेशन पर किसी को बुलाया भी नहीं जा सकता था। न मम्मी को और न छोटी बहन को। अंबाला के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी तो मैंने सहारा देकर पापा को डिब्बे से नीचे उतारा। फिर सहारा देकर उन्हें स्टेशन से बाहर ले आई। पापा निढाले से थे।

स्टेशन के बाहर पांच-सात ऑटो-रिक्शा खड़े थे, जिनके ड्राइवर कपड़े से मुंह, सिर ढंके स्टेशन से बाहर आती सवारियों से उनके गंतव्य के बारे में पूछ रहे थे। ऐसे किसी ड्राइवर से बात करने में भी मुझे डर लग रहा था। तभी न जाने कैसे मुझमें इतनी हिम्मत आ गई कि एक ड्राइवर को मैंने बड़ी आत्मविश्वास भरी रौबदार आवाज में शंकर नगर चलने के लिए कहा और पापा के साथ ऑटो-रिक्शा में बैठ गई। मुझे लगा पुलिस इंस्पेक्टर की परीक्षा से पहले ही असली परीक्षा मैंने पास कर ली है। *

-हरीश कुमार 'अमित'

खाका

अविनाश पुलिस महकमे का वरिष्ठ स्केच आर्टिस्ट था। उसके हाथों से बने खाके कभी गलत नहीं होते थे। एक शाम, एक सहमी हुई बुजुर्ग महिला उसके घर में हुई डकैती के गवाह के तौर पर एक शख्स का हुलिया बताने पहुंची। अविनाश ने कागज पर पेंसिल टिकाई। जैसे-जैसे महिला उस शख्स के माथे के कटे निशान, तीखी नाक और गहरी आंखों का ब्योरा देने लगी, अविनाश की अंगुलियां कांपने लगीं। कैनवास पर उसके अपने इकलौते बेटे का चेहरा उभर रहा था। अविनाश के भीतर भयंकर द्वंद्व छिड़ गया, एक कलाकार की निष्ठा और बाप के मोह के बीच। क्या वह लकीरों को बदलकर अपने बेटे को बचा ले? उसने भारी मन से, बिना कोई हेर-फेर किए बिल्कुल हूबहू वैसा चेहरा उकेरा, जैसा महिला ने बताया था और ड्रॉइंग शीट पुलिस अफसर की ओर बढ़ा दिया। तभी महिला स्केच देखकर रोते हुए बोली, 'हां साहब! यही वो जांबाज लड़का है, जिसने डकैतों से भिड़कर मेरी जान बचाई। अस्पताल में बेहोश पड़ा है, इसके घर खबर करवा दो।' अविनाश की कांपती अंगुलियों से पेंसिल छूटकर गिर गई। *

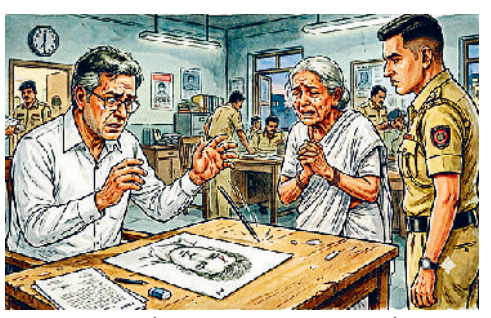

– देवेंद्रराज सुथार

खबर संक्षेप

कबड्डी में शामिल होने आया खिलाड़ी किशोर डूबा, रेस्क्यू जारी

दुर्ग। जिले के उतई थाना क्षेत्र के सेलूद भाठापारा स्थित तंदुला नहर में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। रायपुर के गुढ़ियारी से सेलूद में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल होने आए 15 वर्षीय खिलाड़ी शिवम यादव नहर के तेज बहाव में बह गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ को जानकारी दी गई। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर शिवम की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, शिवम यादव प्रतियोगिता स्थल के पास स्थित तंदुला नहर की ओर शौच के लिए गए थे। इसके बाद नहर किनारे हाथ-पैर धोने के दौरान काई और ढलान के कारण उनका पैर फिसल गया। नहर में पानी का बहाव तेज होने के कारण शिवम खुद को संभाल नहीं सके और गहरे पानी में बह गए। शिवम को नहर में बहता देखकर उनके साथी खिलाड़ियों ने तत्काल बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वे सफल नहीं हो सके। देखते ही देखते शिवम तेज बहाव में लापता हो गए। घटना की सूचना सेलूद सरपंच ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही उतई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल एसडीआरएफ को जानकारी दी। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल टीम लगातार नहर में शिवम की तलाश कर रही है।

सेवा संकल्प अभियान को लेकर हुई चर्चा

भोपाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल एवं प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान की प्रदेश टोली एवं विभिन्न कार्यक्रमों की टोलियों की बैठक को संबोधित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक को प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं पार्टी के प्रदेश महामंत्री व अभियान के प्रदेश संयोजक राहुल कोठारी ने भी संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश शासन के मंत्री राकेश सिंह, निर्मला भूरिया, विश्वास कैलाश सारंग, इन्दर सिंह परमार, कृष्णा गौर, धर्मेन्द्र सिंह लोधी, नरेन्द्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह, प्रदेश महामंत्री लता वानखेड़े, संभाग प्रभारी डॉ. अभय यादव सहित अन्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने 'सेवा संकल्प अभियान' को लेकर की पत्रकार वार्ता

'सेवा संकल्प अभियान' सुशासन, संस्कार सेवा व जनभागीदारी का व्यापक अभियान

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश भर में चलाए जाने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' को लेकर शुक्रवार भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष सेवा, समर्पण, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हैं।

प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की इस सेवा यात्रा से जन-जन को परिचित कराने और सेवा के संस्कार को समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया जा रहा है। यह केवल कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं, बल्कि सेवा, संस्कार, सुशासन और जनभागीदारी का व्यापक अभियान है। प्रधानमंत्री के सेवा-संकल्प से प्रेरणा लेकर विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण को नई गति देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने का कार्य मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है। मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम के माध्यम से मध्यप्रदेश में दो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के विकास की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है।

प्रेस कांफ्रेंस करते डॉ. यादव एवं खंडेलवाल।

कर्मचारियों को पदोन्नति दुग्ध उत्पादन भी बढ़ाया

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में करीब एक लाख अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। 85 हजार शासकीय पदों पर भर्तियां की जा रही हैं, जबकि ढाई लाख पदों पर आने वाले समय में भर्ती किए जाने की तैयारी है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और संकलन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निवेश और रोजगार के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

71 हजार से अधिक बूथों के लाभार्थियों तक पहुंचेगी भाजपा: खंडेलवाल

प्रदेश अध्यक्ष खण्डेलवाल ने कहा कि पीएम मोदी के सेवा व समपर्ण के 25 वर्ष जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया जाएगा। भाजपा 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए 71 हजार से अधिक बूथों के लाभार्थियों तक पहुंचेगी। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 17 सितंबर को शाम सात बजे प्रदेश के 71 हजार से अधिक बूथों के हर लाभार्थियों के घरों में आशीर्वाद का दीया प्रज्वलित किया जाएगा। 07 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

प्रदेश के सभी 11404 शक्ति केंद्रों पर सेवा की कहानियां करेंगे साझा

खण्डेलवाल ने कहा कि प्रदेश के सभी 11404 शक्ति केंद्रों में सेवा की कहानी कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के लाभार्थियों की न्यूनतम 10-10 वास्तविक कहानियों (रील्स) को सोशल मीडिया पर साझा किया जाएगा। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हर जिले और गांव में पदयात्रा, साइकिल व बाइक रैलियां निकाली जाएंगी, जो एक मुख्य स्थल पर मिलकर 'विकसित भारत-2047' का सामूहिक संकल्प लेंगी। गुजरात के वडनगर स्थित हाटकेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर 250 बाइकों पर 500 यात्री जल लेकर वाराणसी (काशी विश्वनाथ) के लिए 10 अलग-अलग समूह में प्रस्थान करेंगे।

नवाचारों-आधुनिक तकनीकों पर केंद्रित प्रदर्शनी का सीएम ने किया शुभारंभ

महिलाओं की ओर से संचालित 'रैपिडो पिंक' बाइक-टैक्सी को मिलेगा बढ़ावा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

◆ स्मार्ट और ग्रीन मोबिलिटी की ओर मध्यप्रदेश के कदम : इंदौर समिट में कनेक्टिविटी और नवाचारों पर हुआ मंथन

◆ प्रदेश में सुरक्षित, सुलभ, किफायती और तकनीकी सक्षम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मिलेगी नई गति

मप्र में स्मार्ट, सुरक्षित, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार मोबिलिटी इकोसिस्टम के निर्माण में प्रदेश के नागरिकों, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों और नवप्रवर्तकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर 'एमपी मोबिलिटी इनोवेशन चैलेंज 2026' का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में नवाचारों और आधुनिक तकनीकों पर केंद्रित विशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री का इंदौर के जनप्रतिनिधियों और बस ट्रांसपोर्ट संचालकों ने आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश में 14 सितंबर को विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आगमन होने जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश स्थापना के माध्यम से देशवासियों को एकजुट किया था। इसी माह 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिवस है। उनके नेतृत्व में पहले गुजरात और अब भारत ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उनकी दूरदर्शी सोच से पूरा भारत गौरवान्वित है। मोदी सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले देश के इकलौते नेता हैं। देशभर से नक्सलवाद की समस्या खत्म हुई है। मप्र लाल सलाम को आखिरी सलाम करने वाला देश का पहला राज्य है।

एमपीवायपी आईएल और रेपिडो के बीच एमओयू का आदान प्रदान हुआ।

परिवहन सेवा उपलब्ध कराने का

एका मोबिलिटी, पुणे के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुधीर मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का प्रदेश में सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध कराने का विजन प्रशंसनीय है और इसी दिशा में यात्री परिवहन विजन समिट का आयोजन महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि एका मोबिलिटी द्वारा मध्यप्रदेश में चौथे प्लांट के रूप में पीथमपुर में इलेक्ट्रिक बस निर्माण का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसका कार्य मात्र 14 माह में पूर्ण किया गया है। इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 हजार ई-बसों की होगी, जो प्रदेश के औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के साथ सुगम एवं आधुनिक परिवहन व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सीएम ने नवाचार और नवीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर केंद्रित प्रदर्शनी का शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में यात्री परिवहन विजन समिट-2026 के दौरान तकनीक, नवाचार और प्रदेश के नवीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने ब्रिलियंट कन्वेशन सेंटर में ही यात्री परिवहन विजन समिट-2026 में बस निर्माताओं, आईटी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य उद्योगों के साथ प्रदेश के विभिन्न शासकीय निगमों की गतिविधियों और नवाचारों पर आधारित इंडस्ट्री एक्सपो का भी उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक्सपो में विभिन्न कंपनियों की ओर से प्रदर्शित बसों का अवलोकन किया तथा उनके फीचर्स और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं की जानकारी ली। प्रदर्शनी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित, आधुनिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई कंपनियों और संस्थानों ने सहभागिता की। प्रदर्शनी में कंपनियों ने अपनी तकनीक, सेवाओं, उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन किया।

नेटवर्किंग एवं एक्सपो का शुभारंभ किया।

इसके अतिरिक्त उन ईवी बसों को भी प्रदर्शित किया गया, जो भविष्य में परिवहन का अहम जरिया बनेंगी। प्रदर्शनी में थिंक गैस, यश टेक्नोलॉजीज, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), इंडियन ऑयल, लाइट मेट्रिक्स, एमपीआईडीसी, क्यूब कंस्ट्रक्शन, कल्याणी पावरट्रेन लिमिटेड और ओम्निफिसेंट सहित विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में परिवहन क्षेत्र से जुड़े आधुनिक समाधानों, तकनीकी नवाचारों, ऊर्जा और ईंधन से संबंधित सुविधाओं तथा अधोसंरचना विकास की संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान परिवहन एवं स्कूलशिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित थे।

प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने की समीक्षा

'जन विश्वास अभियान' में डोर-टू-डोर सर्वे कर शिकायतों का करें निराकरण

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने बैतूल वृत्त का मैदानी दौरा कर विद्युत वितरण व्यवस्था, राजस्व संग्रहण, अधोसंरचना विकास कार्यों एवं उपभोक्ता सेवाओं की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही कंपनी के राजस्व में सुधार के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गर्ग ने जन विश्वास अभियान की तैयारियों और कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शिविरों से पहले क्षेत्र में डोर-टू-डोर सर्वे किया जाए। सर्वे के दौरान उपभोक्ताओं की मीटर, बिलिंग एवं अन्य विद्युत संबंधी समस्याओं की जानकारी एकत्र कर उनका शिविरों में प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए प्रबंध संचालक ने अधिक बकाया वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण में लापरवाही या असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने लाइनों एवं ट्रांसफार्मरों के नियमित रख-रखाव, लाइन पेट्रोलिंग तथा विद्युत लाइनों के आसपास पेड़ों की शाखाओं की समय पर कटाई-छंटाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मिरे असेट एमएफ ने बीएसई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स फंड लॉन्च किया

मुंबई। मिरे असेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मिरे असेट बीएसई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स फंड बीएसई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टोटल रिटर्न इंडेक्स को रेप्लिकेट/ट्रैक करने वाली एक ओपन-एंडेड स्कीम के लॉन्च की घोषणा की है। यह फंड निवेशकों को एक ही इंडेक्स-ट्रैकिंग प्रोडक्ट के जरिए भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसिव और रूल्स-बेस्ड तरीके से निवेश का मौका देता है। इस सेक्टर में आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, आईटी-इनेबल्ड सर्विसेज और हार्डवेयर कंपनियां शामिल हैं। इस फंड का नया फंड ऑफर एनएफओ 8 सितंबर को खुलेगा और 22 सितंबर को बंद होगा। इसके बाद यह स्कीम निरंतर बिक्री और पुनर्खरीद सेल एंड री-परचेज के लिए 28 सितंबर को फिर से खुलेगी। मिरे असेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ईटीएफ प्रोडक्ट्स के प्रमुख और फंड मैनेजर सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने कहा भारत का आईटी सेक्टर डॉट-कॉम क्रैश से लेकर कोविड-19 तक कई टेक्नोलॉजी साइकिल की कसौटी पर परखा जा चुका है और हर बार यह इंडस्ट्री खुद को ढालकर और भी मजबूत होकर उभरी है।

कैरेटलेन ने कोलकाता के गरियाहाट में खोला नया फ्लैगशिप स्टोर

कोलकाता। भारत के प्रमुख ओम्नीचैनल ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक, टाटा समूह के कैरेटलेन ने हाल ही में कोलकाता के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र, गरियाहाट में अपना नया फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च किया। यह लॉन्च पूर्वी भारत में ब्रांड के रिटेल विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम है। यह कैरेटलेन का महज़ एक और नया स्टोर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्टोर है जो दिखने में और अपने कलेक्शन में पूरी तरह से कोलकाता के रंग में रंगा हुआ है। इसके डिज़ाइन, सजावट, और माहौल में कोलकाता की अनूठी संस्कृति और यहां के लोगों की पसंद की झलक बेहद खूबसूरती से देखने को मिलती है। यह स्टोर कैरेटलेन के आधुनिक ज्वेलरी डिज़ाइन्स व बेहतरीन ओम्नीचैनल शॉपिंग अनुभव को शहर के ग्राहकों के और करीब लाता है; जहाँ रोजमर्रा पहनने के लिए, उपहार और आभूषणों का कलेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। 3 मंजिलों का यह विशाल स्टोर पारंपरिक 'कोल-ब्रेकिंग' (कोयला तोड़ने की रस्म) के साथ शुरू हुआ, जो नए स्टोर की शुरुआत और आने वाले समृद्ध समय का प्रतीक माना जाता है। यह लॉन्च भारत के प्रमुख बाजारों में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने की कैरेटलेन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

देश भर में 388 से अधिक स्टोर्स (जिसमें पूर्वी क्षेत्र के 69 स्टोर्स शामिल हैं) के बढ़ते रिटेल नेटवर्क के साथ, गरियाहाट का यह नया स्टोर राष्ट्रीय स्तर पर कैरेटलेन के सबसे बड़े और प्रमुख स्टोर्स में से एक है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की बात करें तो, ब्रांड वर्तमान में राज्य के 11 शहरों में 31 स्टोर्स चला रहा है।

महिंद्रा का ब्लेज़ो आई-टीआरके नए मानकों को स्थापित करेगा

कोलकाता । महिंद्रा ट्रक एंड बस, जोकि महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा है, ने आज ऑल-न्यू ब्लेज़ो आई-टीआरके-को लॉन्च करने की घोषणा की। यह नए दौर का हैवी कमर्शियल ट्रक ट्रांसपोर्टर्स और फ्लीट मालिकों से एक ही मुख्य वादा करता हैः प्रॉफिट का रॉकेट। महज़ एक ट्रक से बढ़कर, ब्लेज़ो आई - टीआरके को पूरे बिजनेस के समाधान के रूप में तैयार किया गया है। यह बेहतरीन माइलेज, पावरफुल इंजन, स्मार्ट कनेक्टेड तकनीक और उद्योग में सबसे बेहतरीन अपटाइम गारंटी का शानदार मेल है। यह ग्राहकों को कमाई बढ़ाने, काम की रफ्तार सुधारने, चलाने का खर्च घटाने और अपनी गाड़ियों पर बेहतर कंट्रोल रखने में मदद करता है। ब्लेज़ो आई - टीआरके-को ग्राहकों के लिए इन तीन बड़े फायदों के साथ तैयार किया गया है। ब्लेज़ो आई - टीआरके- रेंज में महिंद्रा का भरोसेमंद और बेहतरीन 320 HP एमपावर इंजन दिया गया है, जो दमदार प्रदर्शन, उच्च विश्वसनीयता और अधिक उत्पादकता प्रदान करता है। ड्राइवर के आराम को बढ़ाने के लिए इसमें कॉम्फीमैक्स सस्पेंडेड सीट, ईज़ीक्रूज़ क्रूज़ कंट्रोल, हैंड्स-फ्री और सुरक्षित बातचीत के लिए माइक के साथ ब्लूटूथ-सक्षम म्यूज़िक सिस्टम, और एक विशाल, प्रीमियम व एर्गोनॉमिक एसी केबिन दिया गया है। यह ड्राइवर को लंबी दूरी के संचालन में भी ऊर्जावान बनाए रखता है, जिससे फ्लीट मालिक अधिक दक्षता के साथ ज़्यादा ट्रिप पूरे कर पाते हैं।

संतोषी विहार में 1.43 करोड़ के विकास कार्यों को मिली रफ्तार

भोपाल। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 68 में विकास कार्यों को गति देते हुए विधायक एवं मंत्री कृष्णा गौर ने विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। करीब 1.43 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इन विकास कार्यों की कड़ी में संतोषी बिहार कॉलोनी स्थित मंदिर में पेविंग ब्लॉक लगाने, मंदिर की छत के सुधार तथा सामने की मुख्य सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद कॉलोनी के प्रमुख उमेश गौतम एवं मंजू गौतम के निवास पर मंत्री कृष्णा गौर का शाल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। इस दौरान क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी बात भी रखी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद उर्मिला मौर्य, जिला उपाध्यक्ष भीकम सिंह बघेल, इंद्रपुरी मंडल अध्यक्ष लवकुश यादव, पार्षद वार्ड शिरोमणी शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता-निर्देशक मंजू उमेश गौतम, लक्ष्मी ठाकुर, कॉलोनी अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

हांसी में 3 हरियाणा बटालियन एनसीसी का प्रशिक्षण शिविर

हांसी। द ई5 कॉलेज, घड़ी, हांसी में 3 हरियाणा बटालियन एनसीसी, हिसार के तत्वाधान में वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का आयोजन बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुनील कटारिया के नेतृत्व में किया जा रहा है। 12 से 21 सितंबर तक चलने वाले इस वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से कुल 590 एनसीसी कैडेट्स उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। शिविर में कैडेट्स को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, शारीरिक दक्षता, ड्रिल, मानचित्र-पठन, हथियार प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास तथा राष्ट्र सेवा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

विशेष रूप से, रोहतक ग्रुप के अंतर्गत 11 बटालियनों से 194 आरडीसी कैडेट्स भी इस शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। इन कैडेट्स को आगामी रिपब्लिक डे कैंप (आरडीसी) की तैयारियों के दृष्टिगत विभिन्न सैन्य एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में दक्ष बनाया जाएगा। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुनील कटारिया ने कैडेट्स को शिविर के दौरान अनुशासन, समर्पण और टीम भावना के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

स्वास्थ्य मंत्री का बंगला घेरने का प्रयास, युवा कांग्रेस की पुलिस से झड़प

इलाज कराने वालों को होना पड़ रहा परेशान

युवा कांग्रेस ने कहा- वेंटिलेटर पर मप्र की स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहिए इस्तीफा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

स्वास्थ्य मंत्री पर जवाबदेही से बचने का आरोप

मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निवास का घेराव करने की कोशिश की। प्रदेश अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया ने आरोप लगाया कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयों की कमी है। मरीजों को समय पर एंबुलेंस तक नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के कारण आम लोगों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। घनघोरिया ने रीवा से लेकर भोपाल तक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं।

प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी।

रीवा की घटना का हवाला

युवा कांग्रेस ने रीवा की घटना का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। प्रदर्शन में भोपाल जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंकित दुबे, राहुल मंडलोई, प्रदेश महासचिव रोहित राजोरिया, प्रदेश सचिव मोहित सक्सेना, नरेंद्र यादव, लोकेन्द्र शर्मा, जयंत जोशी, अनिकेत द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भारत व कनाडा में रणनीतिक साझेदारी की घोषणा

नई दिल्ली। भारत की सॉवरेन एआई क्लाउड सेवा प्रदाता भारथक्लाउड ने भविष्य की ब्रांड मार्केटिंग पहलों और इवेंट टेक्नोलॉजी के लिए उत्तरी अमेरिका और भारत में परिचालन करने वाली एआई-संचालित प्रौद्योगिकी कंपनी आइबेंटोस के साथ साझेदारी की है।केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित सातवें भारत-कनाडा व्यापार एवं निवेश मंत्रिस्तरीय संवाद के अवसर पर हाल में आयोजित भारत-कनाडा बिजनेस समिट में दोनों व्यावसायिक संस्थाओं के बीच हुई चर्चाओं के बाद इस साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया। यह साझेदारी आइबेंटोस के एआई-संचालित प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी ब्रांड मार्केटिंग, इवेंट टेक क्षमताओं और ग्राहक जुड़ाव को मजबूत करने की भारथक्लाउड की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह ऐसे समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब एमएसएमई भारत की जीडीपी में 31.1 प्रतिशत का योगदान करते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा मंत्रियों ने वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में मजबूत वृद्धि का उल्लेख किया, जो 2024 में 23.66 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें वस्तु व्यापार का मूल्य लगभग 8.98 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है।

इनडीड हायरिंग इंडेक्स जारी, कैंडिडेट्स ने पारदर्शिता की मांग की

नई दिल्ली। हायरिंग की प्रक्रिया में लगातार बदलाव हो रहा है। जॉब मैचिंग और हायरिंग में ग्लोबल लीडर, इनडीड ने हायरिंग के सफर में दोनों पक्षों की स्थिति को स्पष्ट करने का अद्वितीय नजरिया पेश किया है। कंपनी का नया हायरिंग कॉन्फिडेंस इंडेक्स यह समझने में मदद करता है कि हायरिंग प्रक्रिया में विश्वास कैसे स्थापित होता है, कहाँ पर अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं और एम्प्लॉयर कैंडिडेट्स को हायरिंग का ज्यादा स्पष्ट, निष्पक्ष और मानवीय अनुभव कैसे प्रसान कर सकते हैं। कैंडिडेट हायरिंग की प्रक्रिया में एम्प्लॉयर्स से ज्यादा स्पष्टता चाहते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर की उम्मीद पूरी नहीं हो पाती है। इनडीड के पहले 'हायरिंग कॉन्फिडेंस इंडेक्सः मेजरिंग जॉब सीकर कॉन्फिडेंस इन हायरिंग एंड ए.आई' के मुताबिक भारत को 100 में से 58 का स्कोर मिला है। इनडीड ने हायरिंग कॉन्फिडेंस इंडेक्स यह समझने के लिए पेश किया है कि हायरिंग की प्रक्रिया में कैंडिडेट का विश्वास बढ़ाने या घटाने वाली चीजें कौन सी हैं। इसमें नौकरी के इच्छुकों और एम्प्लॉयर, दोनों के नजरिए को शामिल किया गया है। इस रिसर्च में हायरिंग के उन दैनिक पहलुओं को शामिल किया गया है, जो विश्वास बढ़ाते हैं। इनमें काम को लेकर स्पष्टता, हायरिंग की समय सीमा, रिक्रूटर के साथ बातचीत, कैंडिडेट का मूल्यांकन करने का तरीका और ए.आई का इस्तेमाल शामिल है। रोहन सिल्वेस्टर, टेलेंट स्ट्रेट्जी एडवाईजर, इनडीड ने कहा नौकरी तलाश रहे कैंडिडेट्स को अपने आवेदनों को लेकर अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए। नौकरी के बाजार में विश्वास कैसे स्थापित होता है, यह समझने के लिए इनडीड ने पहला ट्रस्ट हायरिंग इंडेक्स पेश किया है, जिसमें भारत को कैंडिडेट्स के ट्रस्ट के लिए 100 में से 58 का बेसलाईन स्कोर प्राप्त हुआ है।

राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन में जर्जर इमारत ढहने की घटना कोई अकेली त्रासदी नहीं है, बल्कि यह भारत की बदहाल शहरी बुनियादी संरचना और जर्जर इमारतों के उस विशाल संकट का एक खौफनाक प्रतीक है, जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी, अवैध निर्माण और प्रशासन की घोर लापरवाही इंसानी जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। एक तरह शहरों में तब्दील हो रहे गांव और उनमें बढ़ती आबादी के जरूरत अनुसार तमाम सुविधाएं जुटाने और सुरक्षा मुहैया कराने में प्रशासन और स्थानीय निकाय सुस्त पड़े हैं। वहीं किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय न होना भी इस समस्या को और विराल रूप दे रही है। शहरों को स्मार्ट बनाने का अर्थ केवल कैमरे, ऐप और डिजिटल सिस्टम लगाना नहीं है। स्मार्ट शहर वह है, जहां नागरिक को साफ सड़क, सुरक्षित फुटपाथ, व्यवस्थित यातायात, पर्याप्त पानी, बेहतर सीवर, स्वच्छ वातावरण और समय पर सरकारी सेवाएं मिलें। इसके लिए सरकार को शहरी प्रशासन का विकेंद्रीकरण, स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और नागरिकों के प्रति स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। अब समय केवल शहरों को फैलाने का नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से संचालित करने का है। *इन्हीं मुद्दों की पड़ताल करता आजकल का यह खास अंक...*

बढ़ती आबादी और सुस्त स्थानीय निकाय

विश्लेषण

उमेश चतुर्वेदी

वरिष्ठ स्तंभकार

शहरी नियोजन और उसकी चुनौतियों को समझने से पहले शहरी इलाकों में रह रही जनसंख्या और शहरों की ओर बढ़ती ललक के आंकड़ों पर ध्यान देना जरूरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी देश की कुल जनसंख्या का 31.16 प्रतिशत यानी करीब 37.71 करोड़ थी। हालिया अनुमानों के अनुसार, यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 36 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया है। 1981 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक देश की शहरी आबादी 15.9 करोड़ और तब की आबादी का 23.3 प्रतिशत थी। साफ है कि भारत में शहरीकरण या शहरों की ओर पलायन अस्सी के दशक में बढ़ गया था, जिसमें नई आर्थिक नीति के बाद तेजी दिख रही है।

शिक्षक दिवस के अगले ही दिन दिल्ली के सत्य निकेतन की एक इमारत के जमींदोज होने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने भारत की शहरी आबादी की सुरक्षा, सहूलियतों और सुविधाओं पर सवाल खड़ा कर दिया है। भारत की सदियों से पहचान उसकी ग्राम और कृषि संस्कृति के लिए रही है। लेकिन आधुनिक आर्थिकी को अपनाने के बाद भारत अपनी इस पहचान को लगातार पीछे छोड़ने की कोशिश में जुटा है। पश्चिम की तरह वह भी शहरीकरण को विकास का मानदंड मान चुका है। देश की बड़ी आबादी कभी मजबूरी के रोजगार तो कभी शिक्षा तो कभी स्वास्थ्य कारणों से लगातार शहरों की ओर पलायन कर रही है। पलायन की इस प्रवृत्ति को प्रतिशत के लिहाज से देखें तो बड़ी भले न लगे, लेकिन विशाल जनसंख्या वाले देश के लिहाज से असल में यह संख्या बहुत बड़ी है। इसका असर शहरी नियोजन और प्रशासन पर भी रोजाना दिखता है।

आंकड़ों की बाजीगरी में इस दबाव की लगातार अनदेखी होती रहती है। इस खेल में शहरी इलाकों में रहने वाली जनसंख्या और उन्हें मिलने वाले छोटे और किसी तरह पेट भर पाने वाले रोजगार को ही विकास का पैमाना मान लिया जाता है। सत्य निकेतन की घटना ने आंकड़ों की इसी बाजीगरी और शहरी नियोजन के साथ ही शहरी निकाय प्रबंधन के बारे में सोचने का अवसर मुहैया कराया है। शहरी नियोजन और उसकी चुनौतियों को समझने से पहले शहरी इलाकों में रह रही जनसंख्या और शहरों की ओर बढ़ती ललक के आंकड़ों पर ध्यान देना जरूरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी देश की कुल जनसंख्या का 31.16 प्रतिशत यानी करीब 37.71 करोड़ थी। हालिया अनुमानों के अनुसार, यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 36 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया है। 1981 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक देश की शहरी आबादी 15.9 करोड़ और तब की आबादी का 23.3 प्रतिशत थी। साफ है कि भारत में शहरीकरण या शहरों की ओर पलायन अस्सी के दशक में बढ़ गया था, जिसमें नई आर्थिक नीति के बाद तेजी दिख रही है।

अवैध मकान बनाने की प्रवृत्ति पर लगाम नहीं

नगर निगम और पुलिस वालों में इतना सहयोग दिखता है कि अगर एक किसी नए निर्माण की सूचना से वंचित रह गया तो दूसरा अपना हिस्सा लेने के बाद उसे सूचित जरूर करता है, ताकि बेईमानी की इस कमाई में आपसी ईमान बना रहे। दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में स्थानीय स्तर पर कई गांव भी शहरों में समा गए हैं। लेकिन उनके प्रशासन और नियोजन के लिए स्थानीय निकायों में उस तरह की दिलचस्पी नहीं देखी जाती, जैसी विकसित कॉलोनियों और पॉश मोहल्लों के लिए दिखती है। एक यह भी कारण है कि सत्यनिकेतन की बिल्डिंग जैसे कमजोर और अवैध मकान बनाने की प्रवृत्ति पर लगाम नहीं लग सकती। दो राय नहीं कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय निकायों को वित्तीय और दूसरे अधिकार तो मिले ही हैं, उनके लिए आवंटन भी बढ़ा। लेकिन उन्हें जैसी चुस्ती दिखानी चाहिए, वह उनमें नहीं दिखती। एक बात और है कि शहरी निकाय प्रशासन की कल्पना शक्ति जैसी होनी चाहिए, नजर नहीं आती। इसलिए विकास की दिशा को लेकर वे सचेत नहीं दिखते। सत्यनिकेतन की घटना के बहाने शहरी निकाय प्रशासन की इन चुनौतियों पर खुला विमर्श होना चाहिए, तभी राह निकलेगी और भविष्य में देश के शहर भी अमेरिकी-यूरोपीय शहरों की तरह साफ, चमकीले और नागरिक सुविधाओं से युक्त बन सकेंगे।

शहरों की ओर पलायन

संयुक्त राष्ट्र-हैबिटैट के वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2016 के आकलन के मुताबिक भारत की शहरी आबादी 2015 में 42 करोड़ थी। कुछ अनुमानों के अनुसार, साल 2030 तक भारत की 40 फीसद से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी, जबकि कुछ अनुमानों में इसे पचास प्रतिशत तक बताया जा रहा है। अगर मौजूदा आंकड़ों के अनुसार मान लें कि करीब 40 फीसद ही आबादी शहरों में रह रही है तो एक सौ पचास करोड़ की जनसंख्या के लिहाज से यह संख्या साठ करोड़ के आसपास बैठती है। यह संख्या अकेले अमेरिका की जनसंख्या से दोगुनी है। लेकिन अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो भारत की स्थिति अमेरिका के मुकाबले बेहद कम है। इसलिए उसकी बराबरी कम से कम मौजूदा हालात में संभव नहीं है।

उदारीकरण की जिस मौजूदा आर्थिकी को पूरी दुनिया ने अपना रखा है, वह अमेरिका और ब्रिटेन से आई है। इस लिहाज से देखें तो मौजूदा आर्थिकी के प्रभाव में पूरी दुनिया अमेरिका होना चाहती है, लेकिन संसाधनों के संदर्भ में देखें तो ऐसा होना तत्काल संभव नहीं है।

उचित सुविधाएं जुटाना कठिन

अमेरिका या यूरोप की तरह शहरों में बसना आज प्राथमिकता हो गई है, सरकारें भी चाहती हैं कि गांवों की तुलना में शहर ही ज्यादा हों। इसकी वजह यह है कि शहरी जनसंख्या और रिहायश घनी होती है, ग्रामीण आबादी की तरह बिखरी नहीं होती। इसकी वजह से बिजली और परिवहन जैसी सुविधाएं गांवों की तुलना में शहरी आबादी को कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है। इस प्रक्रिया में हो ये रहा है कि बेतहाशा बढ़ती शहरी आबादी के लिए उचित सुविधाएं जुटाना ना तो सरकारों के लिए आसान है और न ही शहरी प्रबंधन की जवाबदेही वाले स्थानीय निकाय ही। रही बात शहर आने वाले लोगों की तो उनमें बड़ी संख्या कुछ हजार महीने कमाने वालों की है। अपनी छोटी कमाई से वे किसी तरह गुजर-बसर ही करते हैं। शहरों की बड़ी आबादी इसी वजह से सस्ते या कई बार दड़बेनुमा सीलनभरे मकानों और कमरे में ही जिंदगी गुजारने को मजबूर है। कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के सामने भी कुछ वैसी ही चुनौतियां हैं। सत्यनिकेतन में मारे गए छात्रों में से ज्यादातर ऐसी ही पृष्ठभूमि से थे।

छात्रावासों की निगरानी जरूरी

मौजूदा अर्थव्यवस्था के चलते किसी भी राज्य या शहरी निकाय प्रशासन और सरकार के लिए संभव ही नहीं है कि हर व्यक्ति को साफ और उचित घर मुहैया करा सके।

केंद्र सरकार के भी वश का नहीं कि हर छात्र को वह स्वच्छ और सहूलियत युक्त छात्रावास और कमजोर आर्थिक आय वाले व्यक्ति को मकान उपलब्ध करा सके। लेकिन सरकारें एक काम जरूर कर सकती हैं। खुले बाजार में उचित दर पर सहूलियत भरे मकान उपलब्ध कराने वाले मकान मालिकों और छात्रावास संचालकों की निगरानी जरूर कर सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के जवाबदेह ज्यादातर लोगों की निगाह ऊपरी कमाई पर होती है। दिल्ली के लोगों को पता है कि वे अगर घर बनाना शुरू करते हैं तो नगर निगम का स्थानीय बेलदार मकान मालिक से वसूलने में देर नहीं लगाता। कानूनी रूप से अब दिल्ली पुलिस की भूमिका इन मामलों में खत्म कर दी गई है। लेकिन अब भी स्थानीय बीट कांस्टेबल भी निर्माण कार्यों के एवज में वसूली करते हैं।

निकायों की जवाबदेही तय करने का समय

व्यवस्था

योगेश कुमार सोनी

स्वतंत्र पत्रकार

परिवर्तन संसार का नियम है। तरक्की करना व्यक्ति व देश की अनिवार्यता है, लेकिन इसके चलते साइड इफेक्ट का भी ध्यान रखना जरूरी है। भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। गांवों और कस्बों से शहरों की ओर बढ़ती आबादी ने महानगरों पर भारी दबाव पैदा कर दिया है। सड़कें पहले से अधिक व्यस्त हैं, सीवर व्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा है, पेयजल की मांग बढ़ रही है और कचरा प्रबंधन जैसी समस्याएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं। इसके बावजूद हमारी शहरी व्यवस्था आज भी काफी हद तक पुराने ढर्रे पर चल रही है। सवाल यह है कि क्या केवल नई सड़कें, फ्लाईओवर और कुछ बड़ी परियोजनाएं बनाकर शहरों को बेहतर बनाया जा सकता है? शायद नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि स्थानीय निकायों और शहरी प्रशासन के पूरे ढांचे की समीक्षा की जाए। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत नागरिकों के सबसे नजदीक की सरकार हैं। नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी अधिकांश समस्याएं इन्हीं संस्थाओं से संबंधित होती हैं- सड़क, नाली, सीवर, कूड़ा, स्ट्रीट लाइट, पार्क, पार्किंग और स्थानीय स्तर की स्वच्छता। लेकिन समस्या यह है कि कई बार जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की होती है, जबकि निर्णय लेने और धन उपलब्ध कराने की शक्ति किसी दूसरे स्तर पर होती है। परिणामस्वरूप नागरिक विभागों के बीच चक्कर लगाता रहता है। इस व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। जिस संस्था को जिम्मेदारी दी जाए, उसे पर्याप्त अधिकार और वित्तीय संसाधन भी दिए जाने चाहिए। सड़क बने और कुछ दिन बाद फिर खोद दी जाए। हमारे शहरों की एक बड़ी समस्या विभागों के बीच समन्वय की कमी है। एक एजेंसी सड़क बनाती है, कुछ समय बाद सीवर या पानी की पाइपलाइन के लिए सड़क खोद दी जाती है। फिर किसी अन्य एजेंसी द्वारा केबल या पाइपलाइन डालने के लिए वही सड़क दोबारा खोदी जाती है। इससे सरकारी धन की बर्बादी तो होती ही है, नागरिकों को भी धूल, जाम, दुर्घटना और जलभराव जैसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसका समाधान एकीकृत शहरी योजना में है। सड़क निर्माण से पहले यह तय होना चाहिए कि अगले कई वर्षों में उस सड़क के नीचे किन-किन सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। नागरिक केवल करदाता नहीं, भागीदार भी हैं। शहर में रहने वाला नागरिक केवल संपत्ति कर, पानी का बिल या अन्य शुल्क देने वाला व्यक्ति नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसे यह जानने का अधिकार भी है कि उसके क्षेत्र के विकास के लिए कितना धन आया, कहां खर्च हुआ और काम की गुणवत्ता कैसी रही। सूचना का अधिकार नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड और परियोजनाओं से संबंधित जानकारी हासिल करने का महत्वपूर्ण माध्यम देता है। इसी तरह शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था नागरिकों को अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का रास्ता देती है। लेकिन अधिकार तभी प्रभावी होंगे जब शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई भी हो। यदि किसी इलाके में महीनों से सड़क टूटी हुई है, नाली जाम है या जलभराव लगातार हो रहा है, तो नागरिक को यह पता होना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार विभाग कौन है और समाधान की समयसीमा क्या है। आज जरूरत ऐसी व्यवस्था की है जिसमें हर शिकायत का एक जिम्मेदार अधिकारी, निश्चित समयसीमा और कार्रवाई की स्थिति नागरिक को दिखाई दे। इसके साथ ही नगर निकायों के बजट और परियोजनाओं को अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। जनता को यह जानकारी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए कि उसके वार्ड में कितना पैसा स्वीकृत हुआ और उसका उपयोग कहां किया गया। वार्ड स्तर पर बढ़े नागरिकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। शहरी प्रशासन को केवल अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। वार्ड समितियों और स्थानीय नागरिक समूहों को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। मोहल्ले के लोगों को यह बताने का अवसर मिलना चाहिए कि उनके क्षेत्र की प्राथमिक जरूरत क्या है। कहीं सड़क की जरूरत है, कहीं पार्क की, कहीं पार्किंग की और कहीं जल निकासी की। हर इलाके की समस्या एक जैसी नहीं होती। इसलिए स्थानीय जरूरतों के आधार पर स्थानीय योजनाएं बनाना अधिक प्रभावी होगा। शहरों का भविष्य केवल सरकार नहीं, नागरिक भी तय करेंगे। शहरों को स्मार्ट बनाने का अर्थ केवल कैमरे, ऐप और डिजिटल सिस्टम लगाना नहीं है। स्मार्ट शहर वह है जहां नागरिक को साफ सड़क, सुरक्षित फुटपाथ, व्यवस्थित यातायात, पर्याप्त पानी, बेहतर सीवर, स्वच्छ वातावरण और समय पर सरकारी सेवाएं मिलें। इसके लिए सरकार को शहरी प्रशासन का विकेंद्रीकरण, स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और नागरिकों के प्रति स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। आखिरकार शहर किसी एक सरकार या विभाग के नहीं होते। शहर वहां रहने वाले नागरिकों के होते हैं। इसलिए शहरी विकास की हर योजना के केंद्र में नागरिक होना चाहिए। यदि सरकार स्थानीय निकायों को अधिकार, संसाधन और जवाबदेही के तीनों स्तंभ मजबूत कर दे, तो शहरों की अनेक बुनियादी समस्याओं का समाधान स्थायी रूप से किया जा सकता है। अब समय केवल शहरों को फैलाने का नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से संचालित करने का है।

हमारे शहरों की एक बड़ी समस्या विभागों के बीच समन्वय की कमी है। एक एजेंसी सड़क बनाती है, कुछ समय बाद सीवर या पानी की पाइपलाइन के लिए सड़क खोद दी जाती है। फिर किसी अन्य एजेंसी द्वारा केबल या पाइपलाइन डालने के लिए वही सड़क दोबारा खोदी जाती है।

अदालती चेतावनी को भी कर रहे नजरअंदाज

अनदेखी

रवि शंकर

स्वतंत्र पत्रकार

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत गिरने की घटना में एक बार फिर साबित कर दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में लापरवाही की कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। जहां कभी अवैध इमारत ढह जाती है, कभी होटलों में आग लग जाती है, कभी पानी कोचिंग सेंटरों के भीतर घुस जाता है, तो कभी भगदड़ जैसी घटनाएं हो जाती हैं। हर बार जवाबदेही बयानों और कागजों में दबकर रह जाती है। सत्य निकेतन की घटना कोई अकेली त्रासदी नहीं है, बल्कि यह भारत की बदहाल शहरी बुनियादी संरचना और जर्जर इमारतों के उस विशाल संकट का एक खौफनाक प्रतीक है, जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी, अवैध निर्माण और प्रशासन की घोर लापरवाही इंसानी जिंदगियों पर भारी पड़ रही है।

दिल्ली में इमारत गिरने की यह कोई अकेली घटना नहीं है। बीते दो वर्षों में रोहिणी, साकेत, वेलकम, करोल बाग, पहाड़गंज और मुस्तफाबाद के अलावा दिल्ली के कई अन्य इलाकों में इमारत गिरने की घटनाएं हुईं। दिल्ली की एक बड़ी समस्या अनऑथराइज्ड कॉलोनियां भी हैं, जिसकी वजह से आए दिन कोई न कोई हादसा सुनने में आता ही है। इन इलाकों में लंबे समय से मालिकाना हक, सड़क, सीवर और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की समस्या रही है। अप्रैल 2026 में सरकार ने 1,511 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को 'जैसी है, जहां है' के आधार पर नियमित करने का फैसला किया। दिल्ली में समस्या यह नहीं है कि हर घर असुरक्षित है या हर सड़क जानलेवा है। समस्या यह है कि बार-बार होने वाले हादसे व्यवस्था की कमजोरियां सामने ला रहे हैं। एनसीआरबी की एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया (एडीएसआई) रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 2024 के बीच देशभर में कुल 7,874 लोगों की जान चली गई। इसमें सबसे चिंताजनक स्थिति देश की राजधानी में इस तरह की घटनाओं में मौत के आंकड़ों का बढ़ना है। अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की जगह उन्हें संरक्षण दिया जाता है। इन घटनाओं से अवैध निर्माण को कानूनन वैध करने की प्रक्रिया पर भी प्रश्न खड़े होते हैं। अदालती चेतावनी को भी नजरअंदाज किया जाता है। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर चेतावनी देने के साथ ही वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने वाले अधिकारियों की जवाबदेही पर जोर दिया था। इसके बावजूद अवैध और असुरक्षित भवनों के विरुद्ध कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। राजधानी में सस्ते आवास की कमी के कारण छात्र, प्रवासी और गरीब परिवार इन असुरक्षित भवनों में रहने को मजबूर होते हैं। साफ है, भारतीय शहरों की घनी आबादी और जमीनों की ऊंची कीमत भी निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को, जिन्होंने किसी तरह से खुद के लिए छोटे मकान का बंदोबस्त किया है, वे ही अतिरिक्त निर्माण के लिए बाध्य हैं। ऐसे सभी निर्माण, योजना कानूनों को धराशायी कर देते हैं। उन्हें स्थानीय निकायों के तरफ से नोटिस भी दिया जाता है, परंतु आमतौर पर ऐसे हालातों में स्थानीय प्रबंधन का सहारा ले लिया जाता है, ताकि इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए। कई धनाढ्य लोगों के लिए, कानून के कोई मायने नहीं होते हैं। उनमें से कई लोग अनाधिकृत निर्माण में लिप्त होते हैं और राजनीतिक रसूख अथवा पैसों की मदद से अपने विरोधियों का मुह बंद कर देते हैं। अहम सवाल ये है कि देश की राजधानी में हुई घटना के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? दिल्ली सरकार, एमसीडी या स्थानीय प्रशासन? कहने को तो कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जैसा कि ऐसे हादसों के बाद हमेशा होता है। क्या निलंबन कोई कार्रवाई होती है? जो आज निलंबित होंगे, वे चार-छह महीनों में दोबारा कुर्सियों पर आ टिकेंगे। क्या इससे जवाबदेही तय होगी? कामकाज में कोई सुधार आएगा? क्या इस कार्रवाई के बाद इमारतें नहीं ढहेंगी? यह सिर्फ दिल्ली का नहीं, पूरे देश का मामला है। सरकारें क्या कर रही हैं? अधिकारी कब जागेंगे? आम आदमी की जान की कद्र कब होगी? दुर्भाग्यवश, हमें ईमानदारीपूर्वक ये मानना होगा कि शहरों में अवैध निर्माण के प्रसार पर समूची रोकथाम नहीं लगाई जा सकी है। इनके सतत बढ़त के पीछे कई वजह हैं। जैसे-जैसे हम बढ़ते हैं और घेरा बनाते जाते हैं, ये शहर अपने साथ-साथ समस्याओं में और भी जटिलताएं लाते हैं ।

भारतीय शहरों की घनी आबादी और जमीनों की ऊंची कीमत भी निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को, जिन्होंने किसी तरह से खुद के लिए छोटे मकान का बंदोबस्त किया है, वे ही अतिरिक्त निर्माण के लिए बाध्य हैं। ऐसे सभी निर्माण, योजना कानूनों को धराशायी कर देते हैं।

बेहतर व्यवस्था ही दिलाएगी असली गौरव

बुनियादी जरूरत

सुशील देव

स्वतंत्र पत्रकार

इस समय दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें चीन,रूस जैसी महाशक्तियों समेत कुल 21 देशों के प्रमुख एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। यानी दुनिया की नजरें इस समय दिल्ली पर टिकी हैं। सम्मेलन में वैश्विक साझेदारी, खुले व्यापार या बदलते शक्ति संतुलन की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस राजधानी में नागरिक सुविधाओं को लेकर भी चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आखिर क्यों किसी खास मौके पर ही सरकारी तंत्र सक्रिय हो जाते हैं और यातायात, सफाई व्यवस्था, सुरक्षा तथा पुलिसिंग सब ठीक-ठाक हो जाती है? दिल्ली के नागरिकों की ओर से सरकार के समक्ष यह एक बड़ा सवाल है। कहते हैं कि सस्ती सुविधाओं के लिए सरकार राजधानी शहर में भी सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से समझौता करती है। सरकार कई मोर्चे पर असफल साबित होती हैं। यातायात, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था के अलावा कई बुनियादी जरूरतें भी हैं जिनमें ढिलाई, भ्रष्टाचार या लापरवाही शामिल हैं। इनके कारण दिल्ली शहर की लगातार बदनामी होती है।

दिल्ली में सत्य निकेतन की घटना में 9 लोगों की जान चली गई। इनमें ज्यादातर छात्र थे। पांच मंजिला इमारत में नियम-कानून को ताक पर रखकर पीजी चलाया जा रहा था। हालांकि इस घटना में एमसीडी के कई अफसरों को निलंबित कर दिया गया। मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया। लेकिन यह सब तब हुआ, जब हादसा हो गई। ऐसे में यह सवाल उठता है कि हादसा होने से पहले प्रशासन नींद से क्यों नहीं जागता? घटना के बाद पड़ताल की जा रही है तो एक के बाद एक ऐसी जर्जर इमारतों का पता चल रहा है, जो बहुत ही खतरनाक हैं। पता नहीं, वह किस दिन गिर जाए और कई जिंदगियां दफन हो जाएं। इन इमारतों में रहने वाले छात्र, जो देश का भविष्य हैं। उनका जीवन हर पल खतरे के साए में रहता है। अवैध निर्माण का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है, जो शहरी नियोजन और सुरक्षा प्रणालियों की खामियों को उजागर करता है।

रोशनी, हवा से महरूम डिब्बानुमा कमरे में आज लाखों बच्चे दिल्ली के विभिन्न सघन आबादी वाले इलाकों में पढ़ाई कर रहे हैं। इस उम्मीद में कि एक दिन उसका करियर और सपना पूरा होगा। इसके लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों में महंगी फीस चुकाकर और महंगे खर्च उठाकर अपना भविष्य संवारने की कोशिश करते हैं। परंतु पैसा कमाने की हवस में मकान मालिक या पीजी संचालक उन्हें मौत का दरवाजा तक दिखा देते हैं। उनकी सुविधाओं का जरा भी ख्याल नहीं रखा जाता। किराया वसूली के लिए काम चलाऊ निर्माण जरूर कर दिया जाता है। सभी जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के निकट छात्र आवास का सघन बाजार है। निजी पेइंग गेस्ट भी बहुत ज्यादा हैं।

गली-मोहल्लों में अवैध निर्माण कर हॉस्टल बना दिए गए हैं। वहां कोई नियम या सरकार की नीति नहीं है। बेहतर प्रबंधन नहीं। जिम्मेदार महकमों से सौदेबाजी कर जहां-तहां बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी जाती है। इनमें होटल और रेस्टोरेंट भी बिना मानक के चला दिए जाते हैं, जो सरासर गलत है। यह घटना कोई नई नहीं है। दिल्ली के हौजरानी, सैदुलाजाब की घटनाओं को अभी लोग भूले भी नहीं थे कि फिर से सत्य निकेतन की हृदयविदारक घटना घट गई। हादसे में किसी ने अपने बेटे, किसी ने भाई और किसी ने परिवार के चिराग को खो दिया। सवाल उठता है कि किसी भी अनहोनी के बाद ही सरकारी सिस्टम क्यों एक्टिव होता है?

अफसरों पर कोई भी कठोर सजा या तुरंत एफआईआर क्यों नहीं होती? हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया था, लेकिन उस प्रशासनिक छवि का क्या होगा, जो राजधानी शहर में अच्छा होने का दंभ भरते हैं? आखिर, कब तक जर्जर दीवारों के बीच छात्रों का दम घुटता रहेगा? नॉर्थ कैंपस एरिया, लक्ष्मी नगर, रमेश पार्क, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, मुखर्जी नगर और मुनिरका जैसे इलाके में भी सत्य निकेतन जैसे हालात हैं जहां पुरानी इमारतें, संकरी गलियां, भीड़ और कमजोर सुरक्षा इंतजाम दिखते हैं। इसलिए सरकार को मास्टर प्लान 2047 से पहले भी दिल्ली में बहुत कुछ करने और बदलने की जरूरत है।

गली-मोहल्लों में अवैध निर्माण कर हॉस्टल बना दिए गए हैं। वहां कोई नियम या सरकार की नीति नहीं है। बेहतर प्रबंधन नहीं। जिम्मेदार महकमों से सौदेबाजी कर जहां-तहां बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी जाती है। इनमें होटल और रेस्टोरेंट भी बिना मानक के चला दिए जाते हैं, जो सरासर गलत है।

गुजरात में 'हर घर जल' के दावे पर सीएजी की रिपोर्ट से घिरी भाजपा सरकार, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने साधा इस पर निशाना

14.84 लाख परिवारों के नल कनेक्शन का इंतजार करने का दावा, 89 फीसदी तक पानी के नमूने पीने योग्य नहीं पाए गए

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'हर घर जल' के दावे की हकीकत दूषित पानी और नल कनेक्शन के लिए इंतजार कर रहे परिवारों के आंकड़ों से सामने आ गई है।

खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गुजरात में दशकों से भाजपा का शासन है, लेकिन राज्य में पानी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने दावा किया कि नौ में से करीब 10 पानी के नमूने पीने योग्य नहीं पाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते वर्ष

2004 में 'सुजलाम-सुफलाम' योजना का प्रचार किया गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद यही दावे 'जल जीवन मिशन' के रूप में आगे बढ़े। अब सीएजी की रिपोर्ट ने गुजरात सरकार के वर्ष 2022 में राज्य के सभी ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात ने अक्टूबर 2022 तक 91.18 लाख ग्रामीण परिवारों को 100 प्रतिशत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध होने का दावा किया था। हालांकि 27 जिलों की जिला वार्षिक कार्ययोजनाओं में 1 अप्रैल 2024 तक 14.84 लाख परिवारों के नल कनेक्शन की प्रतीक्षा में होने की बात सामने आई। सीएजी ने इन आंकड़ों के बीच विरोधाभास को देखते हुए आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भरोसा जताने में असमर्थता व्यक्त की। ऑडिट में यह भी सामने आया कि सभी 18,024 गांवों को 'हर घर जल' के अनुरूप बताया गया था, लेकिन अगस्त 2025 तक केवल 16,920 गांवों यानी 93.87 प्रतिशत गांवों को ही इसका प्रमाणन मिला था। छह जिलों में किए गए सर्वेक्षण में नवंबर 2024 तक 71,842 परिवारों यानी करीब 15 प्रतिशत परिवारों के पास कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन नहीं था। पानी की गुणवत्ता पर भी सीएजी ने गंभीर सवाल उठाए। रिपोर्ट की जांच में चुनिंदा गांवों में परीक्षण किए गए पानी के करीब 89 प्रतिशत नमूने पीने योग्य नहीं पाए गए। इसके अलावा 48 गांवों के भौतिक सत्यापन में चार गांवों में पानी की आपूर्ति ही नहीं मिली, जबकि कई अन्य गांवों में निर्धारित 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम पानी की आपूर्ति दर्ज की गई।

रिपोर्ट में जल परियोजनाओं में देरी और वित्तीय अनियमितताओं का भी उल्लेख है। गुजरात वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 11 बड़ी पाइपलाइन परियोजनाओं में पांच परियोजनाएं आठ से 25 महीने की देरी से पूरी हुईं। ऑडिट में गलत थोक मूल्य सूचकांक के इस्तेमाल से ठेकेदारों को 54.32 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान और गलत जीएसटी दर के कारण 18.65 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान की बात भी सामने आई।

धोलका के पांच गांवों में दूषित पानी को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन भी जारी है। ग्रामीणों का दावा है कि पिछले सात वर्षों में इन गांवों में 54 लोगों की कैंसर से मौत हुई है और रासायनिक प्रदूषण के कारण भूजल प्रभावित हुआ है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अहमदाबाद के मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि इन गांवों में कैंसर के कारणों की जांच की जरूरत है। खड़गे ने सौराष्ट्र के राजकोट और जामनगर सहित कई इलाकों में पेयजल संकट तथा कच्छ-सौराष्ट्र में किसानों के सूखे से जूझने का भी दावा किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात की जनता को 2047 के विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है, जबकि राज्य में लंबे समय से शासन कर रही भाजपा सरकार के दावों और जमीनी स्थिति में अंतर दिखाई दे रहा है। खड़गे ने अपने पोस्ट के अंत में भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गुजरात में न 'सुजलाम' यानी शुद्ध पानी है और न 'सुफलाम' यानी भरपूर फल एवं उपजाऊ फसलें!

खबर संक्षेप

ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ करने वाला टीटीई अरेस्ट

पलक्कड़। पलक्कड़ के शोरानूर के पास ट्रेन में महिला यात्री से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में टिकट निरीक्षक (टीटीई) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान कोल्लम के कडक्कल निवासी शिजू के रूप में हुई है। वह रेलवे के तिरुवनंतपुरम मंडल से जुड़ा है।

सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार

कोझिकोड। केरलम के पेराम्ब्रा में एक महिला से कथित सामूहिक दुष्कर्म में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पेराम्ब्रा पुलिस थाने ने बताया कि महिला आरोपियों में से एक की रिश्तेदार है। आरोप है कि उसे मादक पदार्थ दिए गए और लॉज तथा घरों समेत अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान दौरा पड़ने से पायलट की मौत

नई दिल्ली। एयर इंडिया के एक पायलट का दिल्ली में प्रशिक्षण के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह घटना दिल्ली के एक होटल में हुई, जहां वे लेओवर आराम पर थे। एयर इंडिया ने कॉकपिट क्रू सदस्य के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। पायलट को शुक्रवार शाम होटल में अचेत पाया गया था।

सोनितपुर में कार-ट्रक की टक्कर, 5 की मौत

तेजपुर। असम के सोनितपुर जिले में शनिवार को कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा रंगापारा थाना क्षेत्र के बालीपारा में एक पेट्रोल पंप के पास तब हुआ जब सामने से आ रहे ट्रक से कार की टक्कर हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में मारे गए सभी लोग कार में सवार थे।

नड्डा और नायडू ने आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का किया उद्घाटन

स्वास्थ्य प्रणालियों के बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती और लोगों को मिलेगा ज्यादा फायदा

एजेंसी ▶▶ विजयवाड़ा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू ने राज्यभर में 249 करोड़ की लागत से स्थापित 10 गहन चिकित्सा खंडों और 12 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) का शनिवार को उद्घाटन किया। गहन चिकित्सा खंडों में कुल 500 बिस्तर है और इनमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर के साथ-साथ अल्ट्रासाउंड, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोसर्जरी की सुविधाएं भी मौजूद हैं। उद्घाटन के बाद विजयवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि यह स्वास्थ्य प्रणालियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। हमने 12 जगहों पर आईपीएचएल और 10 स्थानों पर गहन चिकित्सा खंड का उद्घाटन किया है। नड्डा ने 2020 में आई कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य प्रणाली और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत को समझा।

विजयवाड़ा में 10 गहन चिकित्सा खंडों, 12 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब का लोकार्पण किया

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए 1,271 करोड़ दिए

उन्होंने कहा कि 2021 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन शुरू किया गया। सरकार ने अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 64,180 करोड़ खर्च करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महामारी और आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार करना है। नड्डा ने कहा कि 23 गहन चिकित्सा खंड, 26 आईपीएचएल और 45 आयुष्मान आरोग्य शहरी मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए 1,271 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है।

'संजीवनी परियोजना' राज्य में शुरू होगी: नायडू

नायडू ने कहा कि राजग सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधार किए हैं और कई देशों को कोविड- के टीके उपलब्ध कराए हैं। देश में मेडिकल सीट की संख्या 51 हजार से अधिक बढ़कर दोगुनी से ज्यादा हो गई है और मंगलागिरि में एम्स को बेहतर तरीके से विकसित किया जा रहा है। नायडूने कहा कि स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से जुड़ी 'संजीवनी परियोजना' जल्द पूरे राज्य में शुरू की जाएगी और यह एक बड़ा बदलाव लाएगी। इससे पहले नड्डा और नायडू ने विजयवाड़ा के पुराने सरकारी अस्पताल में एक गहन चिकित्सा खंड और आईपीएचएल का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। बाद में दोनों नेताओं ने इन नई सुविधाओं का दौरा किया जहां अधिकारियों ने उन्हें इनकी विशेषताओं की जानकारी दी।

गहन चिकित्सा खंड में सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी

उन्होंने कहा कि गहन चिकित्सा खंड में आपातकालीन सेवाएं, आईसीयू, पृथक वार्ड, बड़े और छोटे ऑपरेशन थिएटर तथा बच्चों के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अमरावती क्वांटम बायो वैली को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने के नायडू के अनुरोध पर नड्डा ने केंद्र के सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक तकनीकी दल राज्य की नई राजधानी में भेजा जाएगा।

मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर

देशभर में एमबीबीएस की 13,186 सीटें बढ़ीं, कुल संख्या 1.40 लाख के पार

मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने संशोधित सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है। अब देश में एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को छोड़कर एमबीबीएस की 1,40,214 सीटें हो गई हैं। इनमें 61,185 सरकारी सीटों में 2,786 की वृद्धि हुई है। निजी मेडिकल कॉलेजों की 65,843 सीटों में 10,400 सीटें बढ़ी हैं।

कर्नाटक में सर्वाधिक 1,650 वृद्धि उसके बाद तमिलनाडु में

देश में सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीटें कर्नाटक में बढ़ाई गई हैं। यहां 1,650 नई सीटें जोड़ी गई हैं। तमिलनाडु में 1,250 और बिहार में 1,240 सीटें बढ़ी हैं। कर्नाटक में एमबीबीएस की कुल 15,745 सीटें हो गई हैं। तमिलनाडु में 14,299 हो गई है।

राजस्थान और तेलंगाना में भी 1,000 से ज्यादा सीटें बढ़ीं

राजस्थान में एमबीबीएस की 1,100 नई सीटें जोड़ी गई हैं। यहां 8,280 सीटें हो गई हैं। तेलंगाना में 1,010 सीटें बढ़ी हैं। बंगाल में 975, छग में 645, महाराष्ट्र में 550 और आंध्र में 525 सीटें हैं।

झारखंड और मध्य प्रदेश में 520-520 सीटें बढ़ीं

झारखंड और मध्य प्रदेश में 520-520 सीटें बढ़ाई गई हैं। हरियाणा में 350, केरल में 300 और गुजरात में 250 सीटों का इजाफा हुआ है।

केंद्रीय मंत्री ने राज्यों, सरकारी विभागों और निजी क्षेत्र में स्वदेशी स्टील स्लैग रोड तकनीक को बढ़ावा देने का आह्वान किया

स्टील स्लैग की सड़कें निर्माण लागत में कर सकती हैं 40 प्रतिशत तक की कटौती: जितेंद्र सिंह

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी सड़क निर्माण लागत को लगभग 40 प्रतिशत तक कम कर सकती है, जबकि पारंपरिक सड़कों की तुलना में चार गुना अधिक मजबूती प्रदान करती है। यह बात शनिवार को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि यह तकनीक सड़कों के रखरखाव चक्र को भी काफी बढ़ा सकती है—इसमें लगभग 15 वर्षों के बाद ही रखरखाव की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी क्रांतिकारी ब्रेकथ्रू है जिसके प्रभाव न केवल सड़क इंजीनियरिंग पर, बल्कि संपूर्ण बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेंगे। डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस स्वदेशी तकनीक को एक परियोजना से कई परियोजनाओं तक और एक राज्य से कई राज्यों तक ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ-साथ रेलवे, अन्य सरकारी विभागों, राज्य सरकारों, निजी बिल्डरों, ठेकेदारों और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों द्वारा भी इसे व्यापक रूप से अपनाए जाने पर बल दिया। डॉ. जितेंद्र सिंह सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीआरआरआई) नई दिल्ली और जिंदल स्टील लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से हासिल किए गए 'प्रसंस्कृत स्टील स्लैग एग्रीगेट्स से बनी विश्व की सबसे लंबी सड़क' के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

प्रदान किये जाने वाले समारोह में बोल रहे थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बनी 1.85 किलोमीटर लंबी यह सड़क स्वदेशी तकनीक के बड़े पैमाने पर विस्तार को दर्शाती है, जो इस्पात उत्पादन के उप-उत्पाद (प्रसंस्कृत स्टील स्लैग) को सड़क निर्माण के लिए एग्रीगेट्स में परिवर्तित करती है। इस कार्यक्रम के दौरान सड़क का वर्चुअल उद्घाटन, एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री का विमोचन, सीएसआईआर-सीआरआरआई और जिंदल स्टील के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर, 'स्टील ग्रिट' ब्रांड का शुभारंभ और प्रोजेक्ट टीम का सम्मान भी संपन्न हुआ। इस अवसर पर संसद सदस्य एवं जिंदल स्टील के अध्यक्ष तथा इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन जिंदल, डीएसआईआर की सचिव एवं सीएसआईआर की महानिदेशक डॉ. एन. कलाईसेल्वी, नीति आयोग के पूर्व सदस्य एवं डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक डॉ. वी.के. सारस्वत, सीएसआईआर-सीआरआरआई के निदेशक डॉ. सी.एच. रवि शेखर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, इंजीनियर, इंडस्ट्री लीडर्स और मीडियाकर्मी उपस्थित थे।

रेड नोटिस जारी था, पंजाब में दोहरे हत्याकांड समेत गंभीर मामलों में था वांछित

मोल्दोवा से भारत लाया गया वांछित अपराधी अमृतपाल सिंह, सीबीआई ने कराया प्रत्यर्पण

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंटरपोल रेड नोटिस वाले वांछित अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह का मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पण कराने में सफलता हासिल की है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से यह कार्रवाई पूरी की। पंजाब पुलिस की चार सदस्यीय टीम आरोपी को भारत वापस लाने के लिए मोल्दोवा भेजी गई थी। सीबीआई के अनुसार, अमृतपाल सिंह पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। उसके खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल से दोहरे हत्याकांड, शस्त्र अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उस पर जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल और पासपोर्ट अधिनियम के उल्लंघन के भी आरोप हैं।

175 वांछित अपराधी भारत लाए गए

सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों से 175 वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है। भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में सीबीआई विदेशी एजेंसियों के साथ प्रत्यर्पण और अन्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग की प्रक्रिया में समन्वय करती है। सीबीआई ने बताया कि देश की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए भारतपोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके माध्यम से इंटरपोल के चैनलों के जरिए आवश्यक सहायता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग हासिल किया जाता है। सीबीआई के मुताबिक, अमृतपाल सिंह का मोल्दोवा से प्रत्यर्पण भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय का परिणाम है।

पूर्व सीएम रावत का कांग्रेस से इस्तीफा

पार्टी के संघर्ष में मेरी वजह से कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए

एजेंसी ▶▶ देहरादून

उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि उनसे जुड़ी किसी भी चीज की से विधानसभा चुनावों से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी की लड़ाई कमजोर पड़े। रावत ने उन रिपोर्टों का जिक्र किया जिनमें कहा गया था कि उनके पूर्व ओएसडी और सहयोगी जीना के पास से भारी मात्रा में कैश और गहने जब्त किए गए हैं। रावत ने उन्हें सज्जन और मेहनती व्यक्ति बताया और कहा कि सच्चाई सामने आएगी।

मुझे आरोप पर विश्वास नहीं

रावत ने कहा कि अगर ग्राम सेवकों की भर्ती में ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की और कोई भी गलती उन्होंने की है, उसके प्रमाण हैं तो उनके इस तथाकथित दुस्साहसिक कृत्य के लिए मैं लज्जित हूं। परंतु मुझे इस आरोप पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है।

कानपुर में 5,600 करोड़ की साइबर लूट का खुलासा

हैदराबाद से गिरोह के 2 शातिर अरेस्ट आरोपियों की 76 फर्जी कंपनियां मिलीं

एजेंसी ▶▶ कानपुर

पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल ठगी का पर्दाफाश किया है। चमनगंज और बेकनगंज के 2 साइबर अपराधियों ने मिलकर पूरे देश में करीब 5,600 करोड़ का फ्रॉड किया है।

इन्हें साइबर क्राइम टीम ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है टीम ने रैकेट के सरगना बेकनगंज के तलाक महल निवासी शाहवेज वारिस को हैदराबाद में ट्रेस किया। इन्हें कानपुर लाया गया। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने नेटवर्क का खुलासा किया।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी

दोनों आरोपी ऑनलाइन गेमिंग, आईपीएल में सट्टा, शेयर मार्केट में निवेश और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। कम समय में पैसा कई गुना करने का झांसा देकर लोगों से उनके बैंक खातों में रकम मंगवाई जाती थी। आरोपियों ने 76 फर्जी कंपनियां बना रखी थीं। इनसे पैसों को ठिकाने लगाते थे। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दोनों के खिलाफ 86 शिकायतें दर्ज हैं। शाहवेज वारिस के 11 बैंक खातों में 170 करोड़ की ठगी की शिकायतें हैं, जबकि सलमान के 2 खातों पर 16 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड की 32 शिकायतें हैं।

मुख्यमंत्री सैनी ने दी मंजूरी, फाइनेंशियल मॉडल फॉर स्टेट कंट्रीब्यूशन को लेकर हुई बैठक

एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के बाहर बनाए जाएंगे रिंग रोड: नायब

कुरूक्षेत्र, नारनौल, जींद तथा सोहना पलवल में बाइपास निर्माण कार्य को मिली मंजूरी परियोजनाओं पर खर्च होंगे 9700 करोड़ रुपए

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आमजन के लिए बेहतर आवागमन सुनिश्चित करने के लिए एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों एवं कस्बों के बाहर रिंग रोड एवं नेशनल हाईवे बनाने के कार्य को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सचिवालय में राष्ट्रीय राजमार्ग से शहरी क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करने के लिए मास्टर प्लान के तहत एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल मॉडल फॉर स्टेट कंट्रीब्यूशन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में लोक निर्माण विभाग के मंत्री रणबीर गंगवा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्टर प्लान के तहत बाह्य रिंग रोड एवं नेशनल हाईवे बनाने के लिए केंद्र सरकार अनुसार पॉलिसी तैयार की जाए, ताकि शहरों एवं कस्बों में ट्रैफिक के दबाव कम करने के लिए बनाई जाने वाली सड़कों को अमलीजामा पहनाया जा सके। बैठक के दौरान केन्द्र सरकार के

लागत शेयर के लिए वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों की तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने बैठक में हिसार बाईपास, कुरूक्षेत्र बाइपास, नारनौल सिटी बाइपास, जीन्द बाइपास तथा सोहना पलवल बाईपास निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की। हिसार बाइपास, हिसार-राजगढ रोड़ एनएच 52 से हिसार देहली रोड़ तथा हिसार कैथल रोड से जोड़ने का कार्य करेगा। इसी प्रकार कुरूक्षेत्र लाडवा बाइपास की भी डीपीआर तैयार कर ली गई है। जल्द ही इस परियोजना पर भी कार्य आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नारनौल सिटी बाइपास का भी निर्माण किया जाएगा। लगभग 11 किलोमीटर लम्बे इस बाइपास को स्टेट हाईवे एनएच 148बी से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जींद के दूसरी तरफ बाह्य रिंग रोड़ एवं बाइपास एनएच 352 चार मार्गीय सड़क का निर्माण किया जाएगा। एनएच 919 से पलवल सोहना बाइपास को भी जीर्णोद्वार एवं रि-डिजाइन कर निर्माण किया जाएगा। यह चार मार्गीय सड़क मार्ग लगभग 24 किलोमीटर लंबाई का होगा। इन परियोजनाओं पर लगभग 9700 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएनडी-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाइपास केएमपी लिंक से देहली मुंबई एक्सप्रेस वे ग्रीनफिल्ड कनेक्टिविटी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए भी तैयार किया जाएगा। करनाल रिंग रोड के लिए भी भूमि शेयर जमा करवा दिया गया है। अंबाला शहर एवं कैंट से जोड़ने के लिए रिंग रोड का कार्य भी निर्माणाधीन है। बैठक में रेवाड़ी भटिंडा रेलवे लाइन पर सिरसा में सिविल स्टेशन रोड पर रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण तथा कनीना महेंद्रगढ रोड़ से अनावास, ढाणी राजावास स्कूल से बलाना, खातोद से बुडीन, निम्भेड़ा और बलैचा के लिए लिंक रोड़, महेंद्रगढ बुचौली रोड़, नांगवास से अटेली सड़क के अतिरिक्त कार्य को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, अनुराग अग्रवाल, आयुक्त एवं सचिव अशिमा बराड़ जे गणेशन भी मौजूद रहे।

आर्थिक आजादी की असली सुरक्षा कमाई के साथ जोखिम का भी बीमा

- बाढ़, आग, सड़क हादसे व साइबर ठगी जैसे जोखिम एक झटके में खत्म की रहे जमा पूंजी
- अब निवेश के साथ बीमा सुरक्षा को भी वित्तीय योजना का जरूरी हिस्सा बनाने की जरूरत

सुरक्षा
बिजनेस डेस्क

आर्थिक आजादी का मतलब सिर्फ अच्छी कमाई, बैंक में पर्याप्त पैसा या शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश होना नहीं है। असली आर्थिक मजबूती तब मानी जाती है, जब अचानक आने वाला बड़ा खर्च भी परिवार की वर्षों की बचत और निवेश को हिला न सके। बीमारी, सड़क हादसा, घर या दुकान में आग, प्राकृतिक आपदा और अब साइबर ठगी जैसे जोखिम कभी भी सामने आ सकते हैं। ऐसे में बीमा केवल किसी नुकसान की भरपाई का साधन नहीं, बल्कि पूरी वित्तीय योजना को सुरक्षित रखने वाली ढाल बन जाता है। अक्सर निवेशक अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उस संपत्ति को जोखिम से बचाने की योजना पीछे छूट जाती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने कई वर्षों में बचत करके घर बनाया, बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश किया और सेवानिवृत्ति के लिए अलग कोष तैयार किया। यदि अचानक कोई बड़ा हादसा हो जाए और लाखों रुपये का खर्च सामने आ जाए तो वह व्यक्ति अपने निवेश को समय से पहले निकालने के लिए मजबूर हो सकता है। बाजार में गिरावट के समय निवेश बेचने की स्थिति पैदा हो जाए तो आर्थिक नुकसान और बढ़ सकता है।

वित्तीय योजना में सुरक्षा की चार परतें

एक मजबूत वित्तीय योजना को चार स्तरों में देखा जा सकता है। पहला, रोजमर्रा और अचानक आने वाले छोटे खर्चों के लिए आपातकालीन निधि। दूसरा, परिवार के लिए पर्याप्त जीवन बीमा। तीसरा, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरी बीमा सुरक्षा। चौथा, लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए विविध निवेश। इन चारों को अलग-अलग उद्देश्य के साथ तैयार करने से किसी एक संकट का असर पूरी आर्थिक योजना पर नहीं पड़ता। इसके साथ ही नामांकित व्यक्ति की जानकारी, पॉलिसी दस्तावेज और दावा प्रक्रिया से जुड़े जरूरी कागजात परिवार के सदस्यों को भी पता होने चाहिए।

पॉलिसी लेते समय जल्दबाजी से बचें

बीमा खरीदते समय केवल प्रीमियम की राशि देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। बीमित राशि, जोखिम का दायरा, दावा निपटाने की प्रक्रिया, प्रतीक्षा अवधि, अपवर्जन और नवीनीकरण की शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा में अपनी वास्तविक जरूरत के मुताबिक कवरेज तय करना चाहिए। संपत्ति या कारोबार का बीमा लेते समय भी यह देखना जरूरी है कि पॉलिसी में वास्तविक संपत्ति और संभावित जोखिम पर्याप्त रूप से शामिल हैं या नहीं। किसी भी पॉलिसी में दावा करने की समयसीमा और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी पहले से रखना बाद में परेशानी कम कर सकता है।

बीमा और निवेश की भूमिका अलग-अलग

वित्तीय योजना में बीमा और निवेश को एक-दूसरे का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। निवेश का मुख्य उद्देश्य समय के साथ धन बढ़ाना है, जबकि बीमा का उद्देश्य बड़े जोखिम से आर्थिक सुरक्षा देना है। इसलिए पहले पर्याप्त बीमा सुरक्षा तैयार करना और उसके बाद लक्ष्य के मुताबिक निवेश बढ़ाना ज्यादा संतुलित रणनीति हो सकती है। जीवन बीमा परिवार के कमाने वाले सदस्य की अनुपस्थिति में आर्थिक सुरक्षा देता है। स्वास्थ्य बीमा अचानक आने वाले अस्पताल खर्च से बचाने में मदद करता है। वाहन बीमा सड़क दुर्घटना से जुड़े नुकसान को संभालने में उपयोगी है। घर और कारोबार के लिए संपत्ति बीमा आग, प्राकृतिक आपदा या अन्य निर्धारित जोखिमों में वित्तीय सुरक्षा दे सकता है। छोटे कारोबारियों के लिए यह सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दुकान, मशीनरी, माल और कारोबार से जुड़े जोखिमों के लिए उचित बीमा न होने पर एक दुर्घटना का असर केवल मालिक की संपत्ति पर नहीं, बल्कि पूरे कारोबार और कर्मचारियों की आय पर पड़ सकता है।

साइबर ठगी बना नया आर्थिक जोखिम

डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ वित्तीय जोखिमों का स्वरूप भी बदल रहा है। पहले चोरी, आग या प्राकृतिक आपदा जैसे जोखिम प्रमुख माने जाते थे, अब साइबर ठगी भी आम व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौती है। फर्जी बैंक कॉल, गलत लिंक, पहचान संबंधी जानकारी की चोरी और दूसरे डिजिटल धोखे से लोग अपनी जमा पूंजी गंवा सकते हैं। हालांकि हर तरह का साइबर नुकसान सामान्य बीमा से स्वतः सुरक्षित नहीं होता। इसलिए किसी भी साइबर सुरक्षा उत्पाद या बीमा योजना को लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसमें किन परिस्थितियों में दावा स्वीकार किया जाता है और किन परिस्थितियों को बाहर रखा गया है। केवल बीमा खरीद लेना पर्याप्त नहीं है, उसकी शर्तों को समझना भी उतना ही जरूरी है।

कम बीमा, ज्यादा वित्तीय जोखिम

भारत में बड़ी आबादी अभी भी बीमा को निवेश या बचत का साधन मानकर खरीदती है। कई लोग केवल इसलिए पॉलिसी लेते हैं क्योंकि उसमें भविष्य में पैसा मिलने की उम्मीद होती है। इस सोच में जोखिम सुरक्षा का मूल उद्देश्य पीछे छूट सकता है। विशेषज्ञों की नजर में बीमा खरीदते समय पहला सवाल यह होना चाहिए कि परिवार या संपत्ति को वास्तविक रूप से कितनी सुरक्षा चाहिए। उसके बाद प्रीमियम, अवधि, कवरेज, अपवर्जन और दावा प्रक्रिया को देखना चाहिए। कम प्रीमियम देखकर ऐसी पॉलिसी चुनना जिसमें वास्तविक जोखिम के समय पर्याप्त भुगतान न मिले, वित्तीय योजना को कमजोर कर सकता है।

आपदा के समय निवेश बचाने का काम

बीमा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह संकट के समय निवेश को समय से पहले तोड़ने की जरूरत कम कर सकता है। मान लीजिए किसी परिवार के पास बच्चों की शिक्षा और सेवानिवृत्ति के लिए अलग-अलग निवेश हैं। अचानक घर में आग लगने से बड़ा नुकसान हो जाता है। यदि पर्याप्त संपत्ति बीमा है तो नुकसान की भरपाई में बीमा मदद कर सकता है और परिवार को अपने दीर्घकालिक निवेश को तोड़ने से बचाया जा सकता है। इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी बड़े खर्च के समय स्वास्थ्य बीमा परिवार की बचत पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकता है। इसका सीधा लाभ यह है कि निवेश को उसके निर्धारित लक्ष्य तक जारी रखने की संभावना बढ़ती है।

2047 की आर्थिक मजबूती में बीमा की बड़ी भूमिका

भारत जब विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब परिवारों की आय और संपत्ति के साथ उनके जोखिम भी बढ़ेंगे। अधिक घर, वाहन, कारोबार, डिजिटल लेनदेन और निवेश का मतलब यह भी है कि संभावित वित्तीय नुकसान का आकार बड़ा हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब केवल ज्यादा कमाना और ज्यादा निवेश करना नहीं होगा। इसमें जोखिम का सही आकलन और पर्याप्त सुरक्षा भी शामिल होगी। निवेश से संपत्ति बनाने की प्रक्रिया जितनी जरूरी है, उसे किसी बड़े झटके से बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक आजादी की असली परीक्षा उस समय होती है, जब जिंदगी अचानक योजना से बाहर चली जाती है। अगर उस समय परिवार को अपने बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च या भविष्य के निवेश को बचाने के लिए वर्षों की जमा पूंजी नहीं तोड़नी पड़े, तभी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत कहा जा सकता है। इसलिए निवेश की रणनीति बनाते समय एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए मैं कितना कमा और निवेश कर रहा हूं, इसके साथ यह भी कि अचानक बड़ा जोखिम आया तो मेरी बनाई हुई संपत्ति कितनी सुरक्षित है?

पहली बार निवेश कर रहे हैं तो इन 5 गलतियों से बचें

निवेश मंत्रा
बिजनेस डेस्क

- बीमा को निवेश न समझें और पूरा पैसा एक ही साधन में न लगाएं
- शुरुआती निवेशक अक्सर करते हैं कुछ गलतियां
- सही शुरुआत लंबे समय में बना सकती है मजबूत वित्तीय आधार

निवेश की दुनिया में पहला कदम रखना जितना उत्साहजनक होता है, उतना ही महत्वपूर्ण यह समझना भी है कि शुरुआत कहां से और कैसे की जाए। अक्सर नए निवेशक किसी दोस्त की सलाह, इंटरनेट पर मिली जानकारी या बाजार में चल रही चर्चा के आधार पर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन निवेश का सही तरीका किसी एक उत्पाद को चुनने से नहीं, बल्कि अपनी जरूरत, लक्ष्य, समय और जोखिम को समझने से शुरू होता है। नए निवेशकों के लिए कुछ बुनियादी नियम ऐसे हैं, जिन्हें शुरुआत में ही समझ लिया जाए तो आगे की कई वित्तीय गलतियों से बचा जा सकता है।

1. बीमा और निवेश को एक ही नजर से न देखें

भारत में कई परिवारों के लिए पहली बड़ी वित्तीय योजना जीवन बीमा होती है। इसलिए लोग बीमा पॉलिसी को निवेश का माध्यम भी मान लेते हैं। लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है। बीमा का प्राथमिक मकसद परिवार को वित्तीय जोखिम से सुरक्षा देना है, जबकि निवेश का लक्ष्य समय के साथ संपत्ति तैयार करना है। इसलिए जीवन बीमा की जरूरत हो तो अपनी परिस्थितियों के मुताबिक पर्याप्त सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। वहीं धन बनाने के लिए अलग निवेश योजना बनाई जा सकती है। इससे निवेशक को यह समझने में मदद मिलती है कि वह कितना पैसा सुरक्षा के लिए और कितना पैसा संपत्ति बनाने के लिए लगा रहा है।

2. पूरा पैसा एक ही जगह न लगाएं

निवेश में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है विविधता। अपनी पूरी रकम किसी एक ही साधन या संपत्ति वर्ग में लगाने से जोखिम बढ़ सकता है। अलग-अलग परिसंपत्ति वर्गों का प्रदर्शन एक जैसा नहीं होता। बाजार आधारित निवेश में उतार-चढ़ाव हो सकता है, जबकि सुरक्षित माने जाने वाले साधनों में रिटर्न की क्षमता अलग हो सकती है। सोने की कीमत भी अलग परिस्थितियों में बदलती है। इसलिए निवेशक अपनी जोखिम क्षमता और लक्ष्य के आधार पर अलग-अलग साधनों में संतुलन बना सकते हैं। इसका उद्देश्य किसी एक निवेश से सबसे ज्यादा रिटर्न हासिल करना नहीं, बल्कि पूरे निवेश को एक ही जोखिम से बचाना है।

3. सेवानिवृत्ति दूर है तो भी शुरुआत आज से करें

युवा उम्र में सेवानिवृत्ति काफी दूर लगती है। इसी वजह से बहुत से लोग इस लक्ष्य के लिए निवेश टालते रहते हैं। लेकिन लंबी अवधि के निवेश में समय सबसे महत्वपूर्ण साथी बन सकता है। छोटी उम्र में निवेश शुरू करने का फायदा यह है कि छोटी-छोटी नियमित रकम भी लंबे समय में बड़ा कोष तैयार करने में योगदान दे सकती है। इसका कारण चक्रवृद्धि का प्रभाव है, जिसमें निवेश पर मिलने वाला लाभ आगे अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता पैदा करता है। इसलिए सेवानिवृत्ति के लिए निवेश शुरू करने के लिए बड़ी रकम का इंतजार जरूरी नहीं है। आय बढ़ने के साथ निवेश की राशि धीरे-धीरे बढ़ाई जा सकती है।

4. पैसे लगाने से पहले वित्तीय समझ बढ़ाएं

निवेश करना अब पहले की तुलना में आसान हो गया है। मोबाइल फोन से खाता खुल सकता है और कुछ ही मिनट में निवेश भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन निवेश की प्रक्रिया आसान होने का मतलब यह नहीं है कि हर उत्पाद समझना भी आसान है। नए निवेशक को यह समझना चाहिए कि किसी निवेश में पैसा कैसे काम करता है, उसमें कितना जोखिम है, शुल्क कितना है और पैसा कितने समय के लिए लगाया जाना चाहिए। किसी उत्पाद का पिछला प्रदर्शन उसके भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होता। सोशल मीडिया या परिचितों की सलाह पर बिना समझे पैसा लगाने के बजाय जरूरत पड़ने पर योग्य वित्तीय सलाहकार की मदद लेना बेहतर हो सकता है। जब निवेश की रकम बड़ी हो या लक्ष्य लंबी अवधि का हो।

5. सारी कमाई सिर्फ निवेश में न लगाएं

वित्तीय अनुशासन का अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान जिंदगी की हर छोटी खुशी को टाल दिया जाए। निवेश जरूरी है, लेकिन परिवार व जरूरतों के लिए खर्च करना वित्तीय योजना का हिस्सा है। मासिक बजट बनाते समय बचत, निवेश और जरूरी खर्चों के साथ मनोरंजन और व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए भी एक उचित रकम जरूरी है। इससे निवेश योजना बोझ जैसी महसूस नहीं होती और लंबे समय तक जारी रखना आसान रहता है। अगर लगातार अपनी जरूरतों और इच्छाओं को दबाता रहे तो वित्तीय योजना लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकती।

शुरुआत छोटी हो सकती है, योजना बड़ी रखें

पहली बार निवेश करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वह किसी एक निवेश के पीछे भागने के बजाय अपनी पूरी वित्तीय तस्वीर को समझे। पहले जरूरी खर्चों और आपातकालीन जरूरतों के लिए व्यवस्था करें, फिर बीमा सुरक्षा सुनिश्चित करें और उसके बाद लक्ष्य के अनुसार निवेश की योजना बनाएं। निवेश का चुनाव उम्र, आय, लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार बदल सकता है।

गुल्लक से बाजार तक पहुंचा पैसा बदल रही बचत की तस्वीर

नकद, सोना और एफडी के साथ एसआईपी, म्यूचुअल फंड में लगा रहे पैसा छोटे निवेशकों की बढ़ती भागीदारी से तेज हो रहा वित्तीय बचत का दौर

सुझाव
बिजनेस डेस्क

भारतीय परिवारों के लिए पैसा बचाने का मतलब लंबे समय तक घर में नकद रखना, सोना खरीदना, जमीन लेना या बैंक की सावधि जमा में रकम लगाना रहा है। लेकिन अब इस सोच में धीरे-धीरे बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। परिवारों की बचत का एक हिस्सा बैंक और पारंपरिक साधनों से निकलकर म्यूचुअल फंड, एसआईपी और शेयर बाजार जैसे वित्तीय साधनों की ओर बढ़ रहा है। यानी बचत की पुरानी आदत खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसके साथ निवेश की नई आदत तेजी से जुड़ रही है। इस बदलाव का सबसे बड़ा संकेत घरेलू बचत में वित्तीय साधनों की बढ़ती हिस्सेदारी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 23 में घरेलू बचत में वित्तीय बचत की हिस्सेदारी करीब 27 फीसदी थी, जो वित्त वर्ष 25 में बढ़कर 33 फीसदी हो गई। वहीं, वित्त वर्ष 25 में प्रतिभूति बाजार के माध्यम से परिवारों की बचत का प्रवाह बढ़कर करीब 6.91 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 24 में यह करीब 3.58 लाख करोड़ रुपये था।

एफडी के साथ अब बाजार भी विकल्प

भारतीय परिवारों की वित्तीय मानसिकता में बदलाव का मतलब यह नहीं है कि बैंक जमा या एफडी का महत्व खत्म हो गया है। बैंक जमा आज भी बचत का बड़ा माध्यम है। लेकिन अब निवेशक अपने पूरे पैसे को एक ही जगह रखने के बजाय अलग-अलग साधनों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिस्सा बैंक में तरल जरूरतों के लिए रखा जा रहा है, कुछ पैसा बीमा और सेवानिवृत्ति योजनाओं में जा रहा है और लंबी अवधि के लक्ष्य के लिए म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार का रास्ता अपनाया जा रहा है। हालिया आंकड़ों में भी यही बदलाव दिखाई देता है। वित्त वर्ष 25 में घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों में म्यूचुअल फंड में प्रवाह करीब 4.7 लाख करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 24 के करीब 2.4 लाख करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है।

एसआईपी ने बदली निवेश की आदत

म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ने की एक बड़ी वजह एसआईपी का बढ़ता चलन है। पहले शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए लोगों को बड़ी रकम की जरूरत महसूस होती थी। एसआईपी ने इस धारणा को बदला है। अब नियमित अंतराल पर छोटी रकम निवेश करना संभव है। इससे निवेश बाजार में एकमुश्त पैसा लगाने के बजाय धीरे-धीरे निवेश करने की आदत में बदल रहा है। सरकार के एक हालिया आधिकारिक विवरण के मुताबिक वार्षिक घरेलू वित्तीय बचत में इक्विटी और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 12 के करीब 2 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 15.2 फीसदी से ज्यादा हो गई। इसी अवधि में एसआईपी का औसत मासिक प्रवाह भी कई गुना बढ़ा है। यह बदलाव निवेश की संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नियमित निवेश बाजार की तेजी या मंदी के बजाय निवेशक की वित्तीय दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है।

छोटे शहरों से भी बढ़ी भागीदारी

बाजार आधारित निवेश को लंबे समय तक बड़े शहरों और ज्यादा कमाई वाले लोगों से जोड़कर देखा जाता था। डिजिटल प्लेटफॉर्म और आसान ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा ने इस तस्वीर को बदला है। अब निवेश शुरू करने के लिए बड़े शहर में रहना या किसी निवेश कार्यालय तक जाना जरूरी नहीं रह गया। मोबाइल फोन और डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने वित्तीय उत्पादों तक पहुंच आसान की है। इससे छोटे शहरों और कस्बों के निवेशकों की भागीदारी बढ़ने का रास्ता खुला है। युवा निवेशकों के लिए यह बदलाव और ज्यादा स्पष्ट है। वे बचत को केवल भविष्य की जरूरत के लिए सुरक्षित रखने के बजाय उसे लंबी अवधि में बढ़ाने के विकल्प भी तलाश रहे हैं।

महिलाओं की भागीदारी अहम

बदलती बचत संस्कृति में महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो रही है। परिवार के वित्तीय फैसलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ निवेश के साधनों की समझ भी बढ़ रही है। महिलाएं अब केवल सोना या बचत खाते तक सीमित नहीं हैं। म्यूचुअल फंड, एसआईपी और दूसरे वित्तीय साधनों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। इससे परिवार के निवेश निर्णय पहले की तुलना में ज्यादा विविध हो सकते हैं। हालांकि केवल निवेश खाता खोलना वित्तीय समझदारी की गारंटी नहीं है। बचत का पैसा बाजार तक पहुंचना निश्चित रूप से वित्तीय क्षेत्र के विस्तार का संकेत है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी बढ़ता है। बैंक जमा और बाजार आधारित निवेश की प्रकृति अलग है। शेयर और इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड में रिटर्न निश्चित नहीं होता और बाजार में उतार-चढ़ाव का असर निवेश पर पड़ता है। यही वजह है कि बाजार में निवेश बढ़ने के साथ वित्तीय शिक्षा भी जरूरी हो जाती है। सिर्फ सोशल मीडिया पर किसी की सलाह देखकर शेयर खरीदना या बाजार तेजी में देखकर निवेश बढ़ाना जोखिमपूर्ण हो सकता है। निवेशक को अपने लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार निवेश का चुनाव करना चाहिए। छोटी अवधि की जरूरत का पैसा अत्यधिक जोखिम वाले साधनों में लगाने से बचना जरूरी है।

बचत से पोर्टफोलियो तक पहुंच रहा परिवार

भारतीय परिवारों की वित्तीय सोच में सबसे बड़ा बदलाव शायद यही है कि अब बचत को केवल एक जगह जमा करके रखने के बजाय अलग-अलग उद्देश्यों में बांटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। घर का जरूरी खर्च और आपातकालीन जरूरतों के लिए सुरक्षित रकम, बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग निवेश, सेवानिवृत्ति के लिए लंबी अवधि की योजना और संपत्ति बढ़ाने के लिए बाजार आधारित निवेश-यह सोच धीरे-धीरे जगह बना रही है। यानी परिवार अब केवल यह नहीं सोच रहा कि "पैसा कहां सुरक्षित रहेगा?", बल्कि यह भी पूछ रहा है कि "पैसा कितने समय में और किस लक्ष्य के लिए बढ़ सकता है?"

आने वाले वर्षों में और बढ़ सकता है वित्तीय निवेश

भारत की युवा आबादी, डिजिटल वित्तीय ढांचा और निवेश उत्पादों तक बढ़ती पहुंच इस बदलाव को आगे बढ़ा सकती है। हालिया आंकड़ों में भी वित्तीय परिसंपत्तियों की ओर बढ़ती रुचि साफ दिखाई देती है। हालांकि भारत में परिवारों की बड़ी संपत्ति अभी भी भौतिक परिसंपत्तियों में है।

कमाई बढ़ने के साथ खर्च बढ़ा तो हाथ रह सकता है खाली
बचत को प्राथमिकता, नियमित निवेश, जीवनशैली पर नियंत्रण जरूरी
सालाना वित्तीय समीक्षा लंबे समय में बना सकती है मजबूत संपत्ति

सैलरी बढ़ने से नहीं, पैसे की सही चाल से बनती है दौलत

जानकारी
बिजनेस डेस्क

अच्छी नौकरी, बढ़ती सैलरी और हर साल मिलने वाली वेतनवृद्धि किसी भी व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत होने का भरोसा देती है, लेकिन ज्यादा कमाई अपने आप में दौलत की गारंटी नहीं है। कई बार आय बढ़ने के साथ खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ जाता है और महीने के अंत में बचत पहले जितनी ही रह जाती है। इसके उलट सीमित आय वाला व्यक्ति अगर खर्च पर नियंत्रण रखे, नियमित बचत करे और लंबे समय तक अनुशासन के साथ निवेश करता रहे तो वह अच्छी संपत्ति बना सकता है। यही वजह है कि धन बनाने की प्रक्रिया में कमाई के साथ पैसे को संभालने की आदतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। वित्तीय विशेषज्ञों के मुताबिक आर्थिक मजबूती किसी एक बड़े निवेश या अचानक मिले बड़े रिटर्न से नहीं बनती। यह छोटे-छोटे लेकिन लगातार लिए गए सही वित्तीय फैसलों का परिणाम होती है।

पहली आदत : बचत बाद में नहीं, पहले

ज्यादातर लोगों की आर्थिक दिनचर्या कुछ ऐसी होती है कि पहले घर का खर्च, बिल, खरीदारी और दूसरी जरूरतें पूरी की जाती हैं और महीने के अंत में बची रकम को बचत में डालने की कोशिश होती है। समस्या यह है कि अक्सर महीने के अंत तक बचाने के लिए कुछ खास बचता ही नहीं।इसके बजाय वेतन आते ही बचत और निवेश की रकम अलग कर देना ज्यादा प्रभावी तरीका हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की मासिक आय एक लाख रुपये है तो वह अपनी क्षमता के मुताबिक 20 से 30 हजार रुपये पहले ही बचत या नियमित निवेश के लिए अलग कर सकता है। इसके बाद बची रकम में महीने का खर्च चलाने की आदत बनाई जा सकती है। इसका फायदा यह है कि बचत इच्छा पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि वित्तीय दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है।

दूसरी आदतः बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं

निवेश शुरू करना आसान है, लेकिन बाजार में गिरावट आने पर निवेश जारी रखना ज्यादा मुश्किल होता है। शेयर बाजार में तेजी के दौरान निवेशक उत्साहित होते हैं और गिरावट में कई लोग डरकर निवेश रोक देते हैं या जल्दबाजी में अपनी हिस्सेदारी बेच देते हैं। लंबी अवधि के निवेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज नियमितता और अनुशासन है। निवेश का तरीका व्यक्ति की आय, जोखिम उठाने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्य के अनुसार होना चाहिए। भविष्य के लक्ष्य के लिए अलग-अलग साधनों में निवेश का संतुलन बनाया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि, सार्वजनिक भविष्य निधि, पेंशन योजनाएं, म्यूचुअल फंड और अन्य साधनों की भूमिका व्यक्ति की जरूरत के अनुसार अलग हो सकती है।

तीसरी आदत : आय बढ़े तो पूरा खर्च न बढ़ाएं

सैलरी बढ़ने के साथ जीवनशैली में बदलाव स्वाभाविक है। समस्या तब शुरू होती है जब आय में हुई हर वृद्धि का बड़ा हिस्सा नए खर्च में चला जाता है। बेहतर कार, महंगा मोबाइल, बड़ा घर, बाहर खाना और बार-बार छुट्टियों पर खर्च जैसी चीजें धीरे-धीरे मासिक बजट का हिस्सा बढ़ा देती हैं। इसे जीवनशैली की महंगाई कहा जा सकता है। इससे बचने का आसान तरीका यह है कि वेतनवृद्धि का पूरा फायदा खर्च में न लगाया जाए।

चौथी आदत : बीमा को निवेश नहीं, सुरक्षा मानें

वित्तीय योजना में बीमा की भूमिका को लेकर अक्सर भ्रम रहता है। कई लोग बीमा को भी निवेश की तरह देखते हैं और रिटर्न की तुलना करने लगते हैं। जबकि बीमा का मूल उद्देश्य बड़े वित्तीय जोखिम से सुरक्षा देना है। स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में अस्पताल का बड़ा खर्च वर्षों की बचत पर भारी पड़ सकता है। पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा ऐसी स्थिति में बचत और निवेश को अचानक निकालने की जरूरत कम कर सकता है। इसी तरह परिवार के कमाने वाले सदस्य के साथ अनहोनी होने पर जीवन बीमा परिवार की आर्थिक जरूरतों को संभालने में मदद कर सकता है। इसलिए निवेश की योजना बनाने से पहले जरूरी जोखिमों के लिए पर्याप्त सुरक्षा तैयार करना समझदारी है। बीमा का चुनाव केवल प्रीमियम देखकर नहीं, बल्कि कवरेज और शर्तों को समझकर करना चाहिए।

पांचवीं आदत : साल में एक बार पूरे पैसे का हिसाब

निवेश शुरू करने के बाद उसे भूल जाना भी सही रणनीति नहीं है। आय, खर्च, कर्ज, बीमा और निवेश की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए साल में कम से कम एक बार पूरी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। इस समीक्षा में देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष कितना पैसा बचा, निवेश कितना बढ़ा, कर्ज कितना कम हुआ और क्या मौजूदा निवेश अभी भी तय लक्ष्य के मुताबिक है। आय बढ़ने पर निवेश की रकम बढ़ाई जा सकती है।

दौलत बनाने का असली सूत्र

धन निर्माण को एक सरल क्रम में समझा जा सकता है। कमाई बढ़ाएं, बचत पहले करें, जोखिम से सुरक्षा लें, नियमित निवेश करें और समय-समय पर समीक्षा करते रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश के लिए छोटी रकम से शुरुआत करके समय के साथ निवेश बढ़ाना अधिक व्यावहारिक हो सकता है। नियमित निवेश लंबे समय में चक्रवृद्धि का फायदा मिलने की संभावना बढ़ती है। अमीर बनने का फार्मूला या रातोंरात पैसा दोगुना करने वाली योजना नहीं है। मजबूत संपत्ति आमतौर पर लगातार किए गए छोटे वित्तीय फैसलों से बनती है।

सूर्यवंशी या सैमसन?

अफगानिस्तान के खिलाफ चयन की दुविधा

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

अफगानिस्तान के खिलाफ रविवार को 3 मैचों की टी20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत के सामने दुविधा होगी कि 'वंडर ब्वॉय' वैभव सूर्यवंशी को उतारा जाए या संजू सैमसन के अनुभव पर भरोसा किया जाए।

■ आज टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20

सूर्यवंशी को इंग्लैंड में सैमसन की जगह अंतिम एकादश में जगह दी गई थी लेकिन श्रृंखला के आखिरी मैच में 15 वर्ष के सूर्यवंशी की जगह सैमसन को उतारा गया। टी20 प्रारूप में सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी कामयाब रही है। उम्मीद है कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर जापान में होने वाले एशियाई खेलों की अंतिम एकादश तय करने से पहले सैमसन और सूर्यवंशी दोनों को बराबर मौके देंगे।

अभ्यास सत्र में सैमसन अधिक संतुलित

अभ्यास सत्र के दौरान सूर्यवंशी की तुलना में सैमसन अधिक संतुलित नजर आए। सूर्यवंशी को जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर सहज होकर खेलने में समय लगा क्योंकि पिच से भी बुमराह की गेंदों को मदद मिल रही थी। यह भी हो सकता है कि लगातार लाल गेंद के तीन मैच खेलने के बाद सूर्यवंशी को सामंजस्य बिठाने में समय लग रहा हो। वैसे अफगानिस्तान के पास बुमराह जैसा कोई गेंदबाज नहीं है। अफगानिस्तान के गेंदबाजों के सामने सूर्यवंशी को फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करने पर भी दिक्कत नहीं आएगी।

सूर्यवंशी को लेकर हाइप बढ़ी

सैमसन की बात करें तो तीन पारियों में नाकामी के बाद उन्हें इंग्लैंड दौरे से बाहर करना ज्यादती था। लेकिन सूर्यवंशी को लेकर हाइप इतनी बढ गई थी कि टीम प्रबंधन ने जनता की मांग पर फैसला लिया भले ही बार-बार वे कहते हों कि बाहरी आवाज का असर नहीं होता। अगर ईशान किशन नहीं खेल पाते हैं तो सूर्यवंशी और सैमसन दोनों को मौका मिल सकता है। ईशान को नेट अभ्यास के दौरान कमर में चोट लगी थी।

टीमें इस प्रकार

भारत : श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई

अफगानिस्तान : इब्राहिम जदरान (कप्तान), दारविश रसूली, नूर उल रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजइ, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदिन नायब, नांगेलिया खरोटे, अब्दुल्लाह अहमदजइ, फजलहक फारूकी, नवीनुल हक, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद।

मैच का समय : शाम 7.30 से

फाइनल में शेल्टन, आज ज्वेरेव से खिताबी भिड़ंत

यूएस ओपन : सेमीफाइनल में टियाफो को हराया

एजेंसी ▶▶| न्यूयॉर्क

अमेरिका के बेन शेल्टन ने हमवतन फ्रांसिस टियाफो को हराकर अमेरिकी ओपन के पुरुष एकल फाइनल में प्रवेश कर लिया, जहां उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। स्थानीय खिलाड़ियों के बीच हुए इस मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। दोनों का हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक और कई मशहूर हस्तियां मौजूद थीं। दोनों पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे थे। रविवार को होने वाले फाइनल में दर्शकों का समर्थन लगभग पूरी तरह शेल्टन के पक्ष में रहने की उम्मीद है। अब वह लंबे समय से चले आ रहे अमेरिकी ग्रैंड स्लैम खिताब के सूखे को खत्म करने की सबसे बड़ी उम्मीद बन गए हैं।

अमेरिका को पिछला खिताब 2003 में मिला था

आठवीं वरीयता प्राप्त शेल्टन ने सेमीफाइनल में टियाफो को 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबले में उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। अमेरिका को पुरुष एकल में पिछला ग्रैंड स्लैम खिताब 2003 में मिला था, जब एंडी रॉडिक ने फ्लशिंग मीडोज में अमेरिकी ओपन का खिताब जीता था।

अपना सब कुछ झोंकने जा रहा हूं : शेल्टन

शेल्टन ने कहा, 'मैं यहां अपना सब कुछ झोंकने जा रहा हूं और कोर्ट पर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। उम्मीद है कि आप सभी आकर मेरा समर्थन करेंगे। आइए, इसे अमेरिका के लिए करते हैं।'

ज्वेरेव ने खाचानोव को हराया

अमेरिकी सपने को साकार नहीं होने दूंगा : ज्वेरेव

ज्वेरेव ने कहा, 'उम्मीद है कि रविवार को मैं अमेरिकी सपने को साकार नहीं होने दूंगा।'

ज्वेरेव ने पहले सेमीफाइनल में कारेन खाचानोव को 6-3, 7-6 (7), 7-6 (6) से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। टियाफो को तीसरी बार अमेरिकी ओपन के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले 2024 में उन्हें हमवतन टेलर फ्रिट्ज ने, जबकि उससे पहले यानिक सिनर ने हराया था। टियाफो ने कहा, 'मैं ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचना चाहता था। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा मुकाबला था। उसकी सर्विस भी बेहद अच्छी रही, जिसने मेरे लिए मुकाबला काफी मुश्किल बना दिया।' ज्वेरेव को लंबे समय तक ऐसे पुरुष खिलाड़ी के तौर पर देखा जाता रहा, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीता था, लेकिन उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिना जाता था। इस साल फ्रेंच ओपन में आखिरकार उन्होंने यह इंतजार खत्म किया।

टाउनसेंड-सिनियाकोवा ने जीता महिला युगल खिताब

जोड़ी ने पूरा किया करियर ग्रैंडस्लैम

अमेरिका की टेलर टाउनसेंड और चेक गणराज्य की कैटरीना सिनियाकोवा ने एक टीम के रूप में कैरियर ग्रैंडस्लैम पूरा करते हुए वाइल्ड कार्डधारी एशलिन क्रूगर और रॉबिन मोंटगोमेरी को हराकर अमेरिकी ओपन महिला युगल खिताब जीत लिया। शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने 5-7, 6-0, 6-2 से जीत दर्ज की। 30 वर्ष की टाउनसेंड को एकल वर्ग में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी एरिना सबालेंका ने हराया था। टाउनसेंड और सिनियाकोवा ने 2024 विम्बलडन, 2025 आस्ट्रेलिया ओपन और इस साल फ्रेंच ओपन जीता था। यह सिनियाकोवा का 12वां ग्रैंडस्लैम है, जिन्होंने चेक गणराज्य की ही बारबोरा क्रेसिकोवा के साथ सात और कोको गाफ के साथ एक खिताब जीता है।

खबर संक्षेप

8 अक्टूबर से एपीएल हिस्सा लेंगी दीपिका

नई दिल्ली। चार बार की ओलंपियन दीपिका कुमारी और विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता अतनु दास 8 अक्टूबर से हैदराबाद में शुरू हो रही तीरंदाजी प्रीमियर लीग (एपीएल) के दूसरे सत्र में मेजबान रिकर्व टीम का हिस्सा होंगे। गत एशियाई चैंपियन धीरज बोम्मदेवरा समेत भारत के 36 सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज इसमें दस देशों के 12 अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ मुकाबला करेंगे। कंपाउंड वर्ग में कई बार विश्व कप जीत चुकी एशियाई खेल चैंपियन ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा के साथ पूर्व विश्व चैंपियन ओजस प्रवीण देवताले उतरेंगे। विदेशी खिलाड़ियों में तोक्यो ओलंपिक 2020 चैम्पियन तुर्किये के मेटे गाजोज, पेरिस ओलंपिक 2024 कांस्य पदक विजेता अमेरिका की कासे काउफहोल्ड, ब्राजील के अलमेइडा और दुनिया की दूसरे नंबर की तीरंदाज ब्रिटेन की एला गिब्सन शामिल हैं।

20 से 23 नवंबर तक एशियाई कैडेट कप

चेन्नई। उपमहाद्वीप के युवा तलवारबाजों के लिए एशियाई कैडेट कप 20 से 23 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट में 30 से अधिक देशों के 500 से अधिक खिलाड़ी, कोच, अधिकारी और तकनीकी अधिकारी भाग लेंगे। टूर्नामेंट तीन वर्गों एपी, फॉइल और साबर में आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन भारतीय तलवारबाजी संघ ने एशियाई तलवारबाजी परिसंघ के साथ मिलकर युवा कार्य और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण के साथ किया है। एफएआई महासचिव राजीव मेहता ने कहा,' इससे एशिया के युवा तलवारबाजों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिलेगा और भविष्य में एशियाई खेलों, विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा।'

सूचना

सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (डिस्पले/क्लासीफाईड) में दिए गए तथ्यों/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय लें और विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को परखें। हरिभूमि समूह के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की विज्ञापनों के तथ्यों से सम्बन्धित कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

जूनियर एशिया कप हॉकी : फाइनल में टीम इंडिया, सुप्रिया ने लगाई हैट्रिक

गत चैंपियन भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया

एजेंसी ▶▶| मोकी

ड्रैग फ्लिकर सुप्रिया के तीन गोल की मदद से गत चैंपियन भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर एएचएफ जूनियर महिला एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। सुप्रिया ने तीनों गोल पेनल्टी कॉर्नर पर किए। भारत का सामना अब चीन और जापान के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा।

दोनों टीमों ने संभलकर शुरुआत की लेकिन भारत ने 13वें मिनट में खाता खोला जब मधु सिदर ने शानदार फील्ड गोल पर टीम को 1-0 से बढत दिलाई। दूसरे क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने कोरियाई गोल पर लगातार हमले बोले। भारत को 17वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर सुप्रिया ने गोल करके बढत दुगुनी कर दी।

भारत ने गेंद पर बनाया दबदबा

भारत ने गेंद पर नियंत्रण के मामले में दबदबा बनाए रखा और 21वें मिनट में कोरियाई गोल के 23 मीटर के भीतर हवा में आई गेंद को भारतीय विंगर ने लपका और सर्कल के भीतर शानदार क्रॉस दिया। इसे सुखवीर ने गोल में बदलकर स्कोर 3-0 कर दिया। भारत को 33वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को सुप्रिया ने गोल में बदला। दक्षिण कोरिया के लिए यूरी जियोंग ने 41वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 4-1 किया। भारत ने आखिरी क्वार्टर में बेहतरीन डिफेंस का प्रदर्शन करते हुए कोरियाई हमलों को नाकाम कर दिया। भारत के लिए पांचवां गोल 56वें मिनट में सुप्रिया ने पेनल्टी कॉर्नर पर किया।

अमेरिकी ओपन जूनियर: सेमीफाइनल में हारी रेवती-एंटोनिना की जोड़ी

अमेरिकी जुड़वां बहनें अनिका और क्रिस्टीना पेनिकोवा जीतीं

एजेंसी ▶▶| न्यूयॉर्क

भारत की माया राजेश्वरन रेवती और उनकी यूक्रेनी जोड़ीदार एंटोनिना सुष्कोवा का शानदार सफर अमेरिकी ओपन जूनियर बालिका युगल के सेमीफाइनल में मिली हार के साथ समाप्त हो गया।

माया और एंटोनिना की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी को अमेरिकी जुड़वां बहनों अनिका और क्रिस्टीना पेनिकोवा से 6-7(2), 2-6 से हार का सामना करना पड़ा। भारत और यूक्रेन की इस जोड़ी ने हालांकि टूर्नामेंट में प्रभावशाली प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल तक के सफर में कई वरीय खिलाड़ियों को हराया।

इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज की 3-0 से 'क्लीन स्वीप'

एजेंसी ▶▶| बर्मिंघम

इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए टेस्ट सीरीज के तीसरे और अंतिम मुकाबले को 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। पाकिस्तान से मिले 130 रन के आसान टारगेट को मेजबान टीम ने मुकाबले के चौथे दिन 24.2 ओवरों में हासिल कर लिया। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम पहली पारी में 133 रन पर सिमट गई। आलम ये रहा कि इस पारी में 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। सऊद शकील ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि मोहम्मद अब्बास ने 21 रन का पारी खेली। इनके अलावा, रजाउल्लाह ने टीम के खाते में 11 रन का योगदान दिया। मेजबान खेमे से जोश टंग ने 42 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि ओली रॉबिन्सन और जोफ्रा आर्चर ने 3-3 विकेट चटकाए।

पाक ने गलतियों से लिया सबक

पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में पिछली गलतियों से सबक लेते हुए 449 रन बनाए, मगर ये स्कोर मैच बचाने के लिए नाकाफी था। मेहमान टीम ने शुरुआती 4 गेंदों में 2 विकेट खो दिए थे। उस समय तक खाता भी नहीं खुल सका था, लेकिन इसके बाद शान मसूद (95) ने अजान ओवैस (59) के साथ तीसरे विकेट के लिए 125 रन और कप्तान बाबर आजम (76) के साथ चौथे विकेट के लिए 89 रन जोड़े।

महिला एशिया कप : भारत की नजरें आठवें खिताब पर

एजेंसी ▶▶| दुबई

सात बार की चैंपियन भारतीय टीम की नजरें श्रीलंका के खिलाफ रविवार को महिला टी20 एशिया कप फाइनल में श्रीलंका को हराकर आठवीं बार खिताब जीतने पर लगी होंगी ओर इसके लिए शेफाली वर्मा के साथ दीप्ति शर्मा पर काफी दारोमदार रहेगा। दो अर्धशतक समेत 168 रन बना चुकी शेफाली भारत की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुई हैं और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। धीमी और स्पिनरों की मददगार दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर भी उन्होंने सहज बल्लेबाजी की है। स्मृति मंधाना (154) ने एक शानदार शतक लगाया लेकिन दो मैचों में दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सकी। शेफाली के प्रदर्शन में निरंतरता रही है। शेफाली को अपने चिर परिचित स्ट्रोक्स खेलने में भी परेशानी नहीं आई जबकि दूसरे बल्लेबाज जूझते नजर आए हैं।

***मैच का समय :** रात 8 बजे*

दीप्ति ने दिखाया जौहर, आज श्रीलंका से भिड़ंत

श्रीलंका की कप्तान चामारी अटापट्टू के साथ सर्वाधिक 11 विकेट ले चुकी दीप्ति ने गेंदबाजी के अलावा बल्ले के जौहर भी दिखाए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में 6 गेंद में 13 रन बनाकर उन्होंने भारत को 150 रन के पास पहुंचाया। दीप्ति के साथ श्रीचरणी और प्रेमा रावत ने भी उम्दा स्पिन गेंदबाजी की है और इन तीनों ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा है। दोनों टीमें फाइनल तक के सफर में अपराजेय रही हैं और पिछली बार 2024 में भारत को श्रीलंका ने ही फाइनल में आठ विकेट से हराया था। अटापट्टू की टीम ने भी पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान के खिलाफ जुझारूपन दिखाते हुए सेमीफाइनल में जीत दर्ज की। दो साल पहले दाम्बुला में हर्षिता और अटापट्टू ने मिलकर भारत को फाइनल में जीत दर्ज करने से रोका था।

एशियन गेम्स 2026 : 19 सितंबर से 4 अक्तूबर तक होगी प्रतियोगिता

हरियाणा के 8 बॉक्सर करेंगे देश का प्रतिनिधित्व

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रोहतक

जापान में 19 सितंबर से 4 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय मुक्केबाजी दल में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। इन महामुकाबलों में हरियाणा के कुल 8 बेहतरीन मुक्केबाज देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि इस दल के 7 खिलाड़ियों ने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की थी और अब वे जापानी सरजमीं पर तिरंगा फहराने को पूरी तरह तैयार हैं। 60 किलोग्राम में भिवानी के सचिन, 70 किलोग्राम में सुमित, 80 किलोग्राम में अंकुश और 90 से ज्यादा भार वर्ग में नरेंद्र बेरवाल भाग लेंगे। वहीं, लड़कियों में 51 किलोग्राम में साक्षी, 54 किलोग्राम में प्रीति, 60 किलोग्राम में प्रिया और 65 किलोग्राम में प्रवीन का चयन हुआ है। इनमें से कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सचिन, सुमित, अंकुश, नरेंद्र, साक्षी, प्रीति और प्रिया ने मेडल जीते है।

पदक जीतकर इतिहास रचेंगे: सत्यपाल सिंधु

हरियाणा बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष मेजर सत्यपाल सिंधु ने खिलाड़ियों के चयन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरवशाली क्षण है। उन्होंने कहा कि हमारे मुक्केबाजों की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। इन आठों बॉक्सरों ने अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर यह मुकाम हासिल किया है।

मार्केट न्यूज

फिल्म 'हैवान' के रोमांचक सफर के साथ डा. आर्थो दे रहा मजबूत कदमों का भरोसा

फिल्म 'हैवान व आयुर्वेदिक 'डा. ऑर्थो' की विशेष बांड साझेदारी

चंडीगढ़। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म 'हैवान' एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो अपराध, रोमांच और रहस्य से भरपूर कहानी को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करती है। फिल्म में अक्षय कुमार, सैफ अली खान, बोमन ईरानी, श्रिया पिलगांवकर और सैयामी खेर के साथ कई प्रतिभाशाली कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

फिल्म के प्रमोशन के दौरान कलाकारों ने कहा कि चाहे जिंदगी में कितनी भी भागदौड़ और चुनौतियां क्यों न हों, मजबूत कदमों के साथ हर सफर आसान बनाया जा सकता है। ऐसे मजबूत कदमों के लिए चाहिए डा. ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर एवं शूज, जो हर पल देते हैं नई ऊर्जा, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। वहीं, फिल्म की सफलता की कामना करते हुए एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर डा. संजीव जुनेजा ने कहा कि रोमांच, रहस्य और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी कहानियों को प्रभावशाली तरीके से पर्दे पर प्रस्तुत करने वाली फिल्में दर्शकों को बांधे रखने के साथ उन्हें सोचने का अवसर भी देती हैं। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए इसकी शानदार सफलता की कामना की। इस अवसर पर कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि डा. ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर एवं शूज को पैरों की बेहतर देखभाल और आराम को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। यह प्रोडक्ट डेली लाइफ में पैरों को आराम प्रदान करने के साथ-साथ एक्टिव और एनर्जेटिक लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने में सहायक है।

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में महाशक्तियों के मिलन को देख अमेरिका के बदले सुर

ब्रिक्स सम्मेलन के चलते नई दिल्ली में महाशक्तियों का मिलन

भारत की कूटनीतिक ताकत देख झुका अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप बोले ईरान संग बहुत जल्द खत्म होगी जंग, तेल की कीमतें भी गिरेंगी

ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने नई दिल्ली में शनिवार को मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से मुलाकात के दौरान अमेरिका को साफ नसीहत देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट क्षेत्र की सुरक्षा और उसकी सीमाओं की हिफाजत यहां के देशों और क्षेत्र के मुख्य खिलाड़ियों के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती है। इस इलाके को अमेरिका जैसे किसी बाहरी 'रीजनल पुलिसमैन' की जरूरत नहीं है

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में महाशक्तियों के मिलन को देख अमेरिका के सुर बदल गए हैं। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच ब्रिक्स सम्मेलन में दो धुर विरोधी देशों ईरान और यूएई का जिस गर्मजोशी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया उसे देखकर दुनिया हैरान है। ब्रिक्स सम्मेलन से भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। पूरे विश्व को टैरिफ की धमकी देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंग बहुत जल्द खत्म होगी और इसके बाद तेल की कीमतें गिरेंगी। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने नई दिल्ली में शनिवार को मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से मुलाकात के दौरान अमेरिका को साफ नसीहत देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट क्षेत्र की सुरक्षा और उसकी सीमाओं की हिफाजत यहां के देशों और क्षेत्र के मुख्य खिलाड़ियों के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती है। इस इलाके को अमेरिका जैसे किसी बाहरी 'रीजनल पुलिसमैन' की जरूरत नहीं है। राजनैतिक विश्लेषकों के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति का यह बयान पीएम नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य के बाद आया है जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि सत्ता और फैसले लेने की ताकत शीर्ष पर कुछ देशों और संस्थाओं के हाथों में केंद्रित है, इसमें बदलाव लाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि अब समय आ गया है कि ब्रिक्स में मौजूद हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदला जाए।

इथियोपिया संग कई क्षेत्रों में सहयोग

पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में इथियोपिया के पीएम अबी अहमद के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इथियोपिया ब्रिक्स के नए सदस्य देशों में शामिल है और अबी अहमद शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, क्षमता निर्माण, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। पीएम मोदी और अबी अहमद अली ने गले मिलकर एक-दूसरे का स्वागत किया। इथियोपिया ने भारत की विकास संबंधी पहलों और वैश्विक दक्षिण से जुड़े मुद्दों पर भारत के प्रयासों का समर्थन किया है।

- पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में आए नेताओं का स्वागत किया
- सदस्य देशों संग द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति पर समीक्षा की
- पीएम मोदी ने साझा हितों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की

भारत मंडमप के बाहर ब्रिक्स नेताओं का समूह चित्र

यूएई संग क्षेत्रीय मुद्दों पर की चर्चा

पीएम नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने एक द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने टेक्नोलॉजी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति और सकारात्मक घटनाक्रमों की समीक्षा की थी।

वियतनाम संग रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर

पीएम नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के पीएम ले मिन्ह हंग से मुलाकात की। इस बैठक से दोनों नेताओं को द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने का मौका मिला। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच एक 'बेहतर व्यापक रणनीतिक साझेदारी' है, जो दोस्ती और सहयोग के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर आधारित है। ये संबंध रक्षा और सुरक्षा, फिनटेक, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य उभरते क्षेत्रों में फैल रहे हैं। दोनों पक्ष बहुपक्षीय सहयोग पर मिलकर काम करना जारी रखे हुए हैं। वियतनाम भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का एक मुख्य स्तंभ है।

मलेशिया में खुलेगा वाणिज्य दूतावास

पीएम नरेंद्र मोदी और उनके मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने फरवरी 2026 में पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा के नतीजों पर बात की और व्यापार व निवेश, रक्षा व सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, फिनटेक, शिक्षा, पर्यटन और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। पीएम अनवर इब्राहिम ने कोटा किनाबालु, सबाह में भारत का वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए मलेशिया की सहमति जताई। पीएम मोदी ने आसियान-भारत संबंधों को मजबूत करने में मलेशिया के लगातार समर्थन की सराहना की। नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।

गाला डिनर कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री और राज्यों के सीएम

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होने आए वैश्विक नेताओं के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित रात्रिभोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत अन्य मंत्री भारत मंडपम बस से पहुंचे। विभिन्न राज्यों के केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ भारत मंडपम के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अन्य मंत्री और मुख्यमंत्री बसों से भारत मंडपम पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वैश्विक नेताओं और प्रतिनिधियों के लिए आयोजित रात्रिभोज में शामिल हुए।

इस बस से पहुंचे

मोदी ने मंदिर का महत्व बताया

तमिलनाडु के रामनाथस्वामी मंदिर की पृष्ठभूमि में ब्रिक्स नेताओं का स्वागत

शी जिनपिंग और पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ब्रिक्स नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान पृष्ठभूमि में तमिलनाडु का मशहूर रामनाथस्वामी मंदिर दिख रहा था, जो चार धाम तीर्थस्थलों में से एक है। माना जाता है कि रावण पर जीत के बाद भगवान राम ने यहीं पूजा की थी। नेताओं ने हाथ मिलाया और तमिलनाडु के रामेश्वरम में मशहूर रामनाथस्वामी मंदिर की पृष्ठभूमि में तस्वीरें खिंचवाईं। चीन के राष्ट्रपत जिनपिंग का स्वागत करते हुए मोदी ने उन्हें मंदिर का महत्व भी बताया।

चार धाम तीर्थस्थलों में से रामनाथस्वामी मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, जबकि बाकी तीन उत्तर में स्थित हैं (द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ)। भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11 उत्तर में हैं और सिर्फ रामनाथस्वामी दक्षिण में है। रामेश्वरम न सिर्फ शैव भक्तों के लिए, बल्कि वैष्णव भक्तों के लिए भी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है।

मैत्रीपूर्ण संबंधों पर चर्चा की

राष्ट्रपति मुर्मू से मिले ईरानी राष्ट्रपति ब्रिक्स अध्यक्षता की सराहना की

ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियान ने राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए राष्ट्रपति पेजेश्कियान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ईरान से मिले समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने भारत और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों और लोगों के बीच मजबूत आपसी संपर्क को भी रेखांकित किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्षेत्र में स्थायी शांति के प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति के माध्यम से रास्ता निकालने का आह्वान किया।

सांस्कृतिक विरासत को सराहा

पेजेश्कियन की बेटी जहरा पहुंची ब्रिक्स बाजार, शिल्प प्रदर्शनी देखी

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की बेटी जहरा और उनके पति हसन मजीदी ने शनिवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स बाजार का दौरा किया। उन्होंने ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों की कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती शानदार प्रदर्शनी देखी। जहरा पेजेश्कियन और हसन मजीदी के साथ महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद थीं। इस दौरान वो विभिन्न स्टॉल्स पर मौजूद कारीगरों और शिल्पकारों से बात करती नजर आईं। उन्होंने ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के कई पवेलियन देखे, जिनमें भारतीय पवेलियन भी शामिल था। यहां दो ईरानी स्टॉल्स में से एक बलोची कढ़ाई को प्रदर्शित करता है।

इसे नादिया करीमी ने लगाया है। बलोची कढ़ाई, जिसे स्थानीय भाषा में 'दोच' (जिसका अर्थ है सिलाई या सुई का काम) कहा जाता है, एक प्राचीन और बारीक हाथ की सिलाई वाली कला है। इसे पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में फैले बलूचिस्तान क्षेत्र की महिलाएं करती हैं। ईरान का दूसरा स्टॉल आमनेह सेदिघी ने लगाया है, जिसमें रश्ती कढ़ाई और ईरानी सुई के काम के अन्य रूप दिखाए गए हैं।

अमेरिकी मीडिया की नजर में दिखा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बदलता समीकरण

अमेरिका के प्रमुख अखबारों ने नई दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बदलते वैश्विक हालात की झलक के तौर पर देखा है। ये हालात तनावपूर्ण गठबंधनों, क्षेत्रीय युद्धों और वॉशिंगटन व बीजिंग के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से तय हो रहे हैं।

भारत ब्रिक्स को ताकतवर बनाना चाहता: एनवायटी

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग में से कौन विकासशील दुनिया की अधिक प्रभावशाली आवाज बनकर उभरेगा। चीन ब्रिक्स को अमेरिकी ताकत को चुनौती देने के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर देखता है। वहीं, भारत चाहता है कि यह ग्रुप इतना बड़ा और खुला रहे कि देशों को अलग-अलग गुटों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर न होना पड़े। युद्ध, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें, अमेरिकी टैरिफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चिंताएं देशों को वॉशिंगटन और बीजिंग के साथ अपने रिश्तों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं।

विशाखापट्टनम में संपन्न हुई कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक्सरसाइज

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

नौसेना की पूर्वी कमांड में बीते 9 सितंबर से जारी तीन दिवसीय टेबल टॉप एक्सरसाइज शनिवार को संपन्न हो गई है। जिसका आयोजन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तहत किया गया था। एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में गैर-कानूनी समुद्री गतिविधियों से निपटने की समन्वित प्रतिक्रिया को विकसित करना था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एक्सरसाइज के दौरान संबंधित सदस्य देशों और पर्यवेक्षकों के प्रतिनिधिमंडलों, समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों ने कुल करीब 72 घंटों से अधिक समय तक गहन सिम्युलेटेड ऑपरेशनल परिदृश्यों को लेकर कार्य किया। इस दौरान वार्ता का मुख्य केंद्र जटिल, गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटना था।

इन गतिविधियों पर भी रहा जोर

मंत्रालय ने कहा कि एक्सरसाइज में समुद्री आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अवैध मछली पकड़ने से जुड़ी बिना रिपोर्ट की गई अनियमित गतिविधि शामिल है। प्रतिभागियों ने वर्तमान में मौजूद मानक संचालन प्रक्रिया की समीक्षा की और सामूहिक समुद्री क्षेत्र जागरूकता को बेहतर बनाने के लिए सूचना साझा करने की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। यह पूरी कवायद आईओआर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कॉन्क्लेव से जुड़े देशों के सामूहिक संकल्प को दोहराती है।

'कश्मीर इंटेल' एक्स पर झूठ फैला रहा

भारतीय सेना ने एलओसी पर असामान्य सैन्य तैनाती के दावों को किया खारिज

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रहीं जम्मू-कश्मीर में 'लाइन ऑफ कंट्रोल' (एलओसी) के पास आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी खबरों का खंडन किया है। भारतीय सेना के आधिकारिक फैक्ट चेक अकाउंट से कहा गया कि 'कश्मीर इंटेल' नाम का 'एक्स' अकाउंट ऐसी झूठी खबरें फैला रहा है, जिनमें दावा किया गया है कि 'लाइन ऑफ कंट्रोल' (एलओसी) के पास आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में बड़े सैन्य ठिकानों के पास

रहने वाले लोगों से अपने घर खाली करने को कहा है। सेना ने कहा कि एलओसी पर आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने और 'असामान्य भारतीय सैन्य तैनाती' के दावे पूरी तरह से झूठे हैं। पाकिस्तान से चलने वाला 'कश्मीर इंटेल' नाम का प्रोपेगैंडा अकाउंट यह फेक न्यूज फैला रहा है।

भद्रवाह में 'जैश-ए-मोहम्मद' का कमांडर ढेर, एम4 राइफल बरामद

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह स्थित सेओज धार इलाके में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद के एक पाकिस्तानी आतंकी कमांडर का शव बरामद किया। आतंकी को पहले एक संयुक्त अभियान के दौरान मार गिराया गया था। एसओजी डोडा, राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) और सीआरपीएफ की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान आतंकी का शव बरामद किया। मुठभेड़ स्थल से अमेरिकी निर्मित एम4 राइफल भी बरामद हुई है। सुरक्षाबलों ने बरामद शव और हथियार को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर रही। सुरक्षाबलों की ओर से इलाके में अभियान और तलाशी की कार्रवाई जारी है। इससे पहले यासिर को 5 सितंबर को मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के अशदर गली इलाके में चलाए गए।

कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपोरा, बारामूला और सोपोर में कार्रवाई

जम्मू-कश्मीर में एनआईए की 10 ठिकानों पर छापेमारी, लश्कर के सीमा पार आतंकी नेटवर्क की जांच

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर में सीमा पार आतंकी साजिश से जुड़े मामले में आज 10 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशी कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपोरा, बारामूला और सोपोर सहित विभिन्न स्थानों पर पाकिस्तान स्थित आतंकियों के हैंडलरों और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय ओवरग्राउंड वर्करों के कथित नेटवर्क से जुड़े परिसरों में ली गई। एनआईए के अनुसार, तलाशी के दौरान मामले से संबंधित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। जब्त सामग्री की जांच की जा रही है और इसे पूर्व में जांच के दौरान जुटाए गए अन्य साक्ष्यों से मिलान कर सत्यापित किया जाएगा। एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच इस वर्ष 31 मार्च को एक ओवरग्राउंड वर्कर की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई थी। उसके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड और जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। आगे की जांच में इस साजिश से जुड़े पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई और स्थानीय स्तर पर आतंकियों को सहायता उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क के सदस्यों की पहचान तथा उनकी कथित भूमिकाओं का पता चला। एनआईए के मुताबिक, जांच में आतंकी साजिश से जुड़े वित्तीय लेन-देन, संचार माध्यमों, आरोपियों की आवाजाही तथा हथियारों और विस्फोटकों के स्रोत एवं उनकी आपूर्ति श्रृंखला की भी पड़ताल की जा रही है। एजेंसी ने कहा कि आज की तलाशी कार्रवाई सीमा पार आतंकवाद को मदद पहुंचाने वाले स्थानीय समर्थन तंत्र और व्यापक आतंकी साजिश की जांच को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। मामले में आगे भी कार्रवाई जारी है।

हरिभूमि कम्यूनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक देवेन्द्र सिंह बाल्यान द्वारा हरिभूमि पब्लिकेशंस, चुलियाना मोड़, दिल्ली रोड, रोहतक-124517 से मुद्रित एवं हरिभूमि कार्यालय, 129, ट्रांसपोर्ट सैंटर, पंजाबी बाग, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : डॉ.हिमांशु द्विवेदी। आरएनआई नं 69631/1998, फोन : 011-40451115/16, 40451109